शर्मा हार्डवेयर
SHARMA HARDWARE
Sharma Gali, SJ Road
Athgaon, Guwahati-01
98648-02947

E-Paper : www.goodluckpublications.com, • www.vbslive.in
हिंदी दैनिक
गुवाहाटी, नई दिल्ली, शिमला और जम्मू से एकसाथ प्रकाशित

विकसित भारत समाचार

राष्ट्र निर्माण में प्रयत्नशील

वर्ष : 12 | अंक : 284 | गुवाहाटी | गुरुवार, 21 मई, 2026 | मूल्य : 10 रुपए | पृष्ठ : 8 | VIKSIT BHARAT SAMACHAR | Regd. RNI No. ASSHIN/2014/56526

कॉकरोच से लेकर परजीवियों तक, ऑनलाइन की दुनिया में चल ... पेज 2
मणिपुर के नागा बहुल इलाकों में छह पुरुषों की कैद को लेकर महिलाओं के... पेज 3
उप्र परिवहन निगम की बसों की लाइव ट्रैकिंग से सुरक्षित बनाया जा रहा ... पेज 5
आरसीबी के निदेशक ने बताया टीम की सफलता का राज पेज 7

door graph Premium Quality Hinges
S.S. Traders
Suppliers in : All kinds of Door Fittings Modular Kitchen & Accessories, etc.
D. Neog Path, Near Dona Planet ABC, G.S. Road, Guwahati - 05
97079-99344

सुप्रभात

विपत्ति हीरे की धुल है, जिससे परामात्मा अपने रत्नों को चमकाता है। **लेटन**

भारत-इटली आपसी संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत

रोम (हिंस)। भारत और इटली ने अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने के साथ ही व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, समुद्री अर्थव्यवस्था, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने तथा द्विपक्षीय व्यापार को 20 अरब डॉलर तक ले जाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जोर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिष्ठित विला डोरिया पैम्फिली में बुधवार को हुई द्विपक्षीय बैठक के बाद दोनों देशों ने परस्पर सहयोग के 15 करार किये जिनमें व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, समुद्री अर्थव्यवस्था, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों

के बीच संबंधों को प्रगाढ बनाने के उपायों के समझौते शामिल हैं। इसके अलावा दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को 20 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। बैठक से पहले प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि दोनों नेताओं ने वार्ता के दौरान भू-राजनीतिक घटनाक्रमों पर चर्चा की और साझा हित के वैश्विक मुद्दों पर मिलकर काम करने पर सहमति जताई। एक महत्वपूर्ण निर्णय में, दोनों पक्षों ने भारत-इटली संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों देशों के बीच सहयोग को अधिक सार्थक बनाने के लिए दोनों देश अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक उन्नत करने पर सहमत हुए हैं। आधुनिक तकनीक से जुड़े संयुक्त विकास सुविधाओं को बढ़ाने के लिए दोनों देशों ने रक्षा औद्योगिक रोड मैप तैयार किया है। दोनों देश दुर्लभ खनिजों के क्षेत्र में मिलकर काम करेंगे। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग और आतंक के वित्त पोषण और कर -शेष पृष्ठ दो पर

बांग्लादेश में भारतीय दूतावास के सुरक्षाकर्मी की मौत

ढाका। बांग्लादेश के चिटगांव शहर में स्थित भारतीय दूतावास परिसर के अंदर मंगलवार को एक भारतीय सुरक्षाकर्मी मृत पाया गया। मृतक की पहचान 35 साल के नरेंद्र के तौर पर हुई है। वे हरियाणा के रहने वाले थे और दूतावास में सुरक्षा गार्ड के पद पर तैनात थे। नरेंद्र सोमवार रात अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद अपने कमरे में लौटे थे। मंगलवार सुबह जब वह ड्यूटी पर नहीं पहुंचे तो उनके साथ वालों ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की। कई बार फोन और आवाज लगाने के बाव भी कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद अधिकारियों ने उनके कमरे का दरवाजा खोला। अंदर कमरे के फर्श पर नरेंद्र की डेड बॉडी मिली। वे कैंपस के भीतर बने स्टाफ डॉर्मिटरी में रहते थे। अभी तक मृत सुरक्षाकर्मी की कोई सामने नहीं आई है। जानकारी मिलने के बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। जांच अधिकारी नजरुल इस्लाम ने बताया कि मौत की सही वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगी। उन्होंने कहा कि हमें सूचना मिलने के बाद हमारी टीम मौके पर पहुंची और शव बरामद किया। पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के कारण की पुष्टि हो सकेगी। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधिकारी आरिफुल इस्लाम ने -शेष पृष्ठ दो पर

न्यूज गैलरी

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी को दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली (हिंस)। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन बुधवार को देहरादून पहुंचे, जहां उन्होंने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व केंद्रीय मंत्री बीसी खंडूरी के आवास पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति ने दिवंगत नेता को याद करते हुए कहा कि मेजर जनरल बीसी खंडूरी एक असाधारण नेता, विशिष्ट सैनिक और अनुभवी प्रशासक थे, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र और जनता की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि देश में सड़क बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और कनेक्टिविटी सुधारने में खंडूरी का योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। उपराष्ट्रपति के अनुसार, उनकी कार्यशैली, ईमानदारी और विकासोन्मुख सोच देश के विकास पथ पर एक अमिट विरासत के रूप में बनी रहेगी। उल्लेखनीय है कि मेजर जनरल बीसी खंडूरी का मंगलवार सुबह देहरादून में -शेष पृष्ठ दो पर

अंबुबाची मेला 2026 की तैयारियां शुरू

गुवाहाटी (हिंस)। अंबुबाची मेला 2026 को लेकर कामाख्या मंदिर में तैयारियां शुरू हो गई हैं। पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में शामिल इस मेले के आयोजन में अब लगभग एक माह का समय शेष है, जिसके चलते मंदिर प्रबंधन और प्रशासन ने व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। मंदिर के दोलोई समुदाय के सदस्यों के अनुसार, चार दिवसीय अंबुबाची मेला इस वर्ष 22 जून की रात से आरंभ होगा और 26 जून की सूर्योदय बेला में इसका समापन किया जाएगा। मंदिर प्रशासन ने जिला प्रशासन के साथ सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण और अन्य जरूरी तैयारियों को लेकर बैठकें शुरू कर दी हैं। हर वर्ष की तरह इस बार भी देशभर से लाखों श्रद्धालुओं, साधु-संतों और तांत्रिकों -शेष पृष्ठ दो पर

पीएम मोदी और अमित शाह को लेकर राहुल गांधी के बयान पर बोले नितिन नवीन

ये उनकी अराजकतावादी मानसिकता को दिखाता है

नई दिल्ली। बुधवार को सत्तारूढ़ भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी की टिप्पणी पर जमकर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस नेता के शब्द उनकी अराजक मानसिकता और चरित्र को दर्शाते हैं। भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन ने कहा कि गांधी की टिप्पणी देश की 140 करोड़ जनता का अपमान है और उन्होंने उनसे माफी मांगने की मांग की। यह घटना तब हुई जब गांधी ने बुधवार को अपने लोकसभा क्षेत्र रायबरेली में एक कार्यक्रम में मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर विभिन्न मुद्दों पर हमला करते हुए उन्हें *गद्दार* कहा। गांधी की टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए नबीन ने कहा कि उन्होंने जिस तरह का बयान दिया है, वह स्पष्ट रूप से उनकी अराजक

मानसिकता और चरित्र को दर्शाता है। यह टिप्पणी चुनावों में अपनी पार्टी की हार से उनकी कुंठा और हताशा को भी दर्शाती है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष ने आगे कहा कि मुझे लगता है कि वे अपना मानसिक संतुलन खो रहे हैं। उन्होंने गांधी की टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि यह देश की 140 करोड़ जनता का अपमान है। नवीन ने पूछा कि जिस व्यक्ति ने आतंकी घटनाओं पर अंकुश लगाया, नक्सलवाद का अंत किया, तिरंगे का सम्मान बढ़ाया, ऐसे व्यक्ति के लिए आप इस तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगे? उन्होंने मांग की कि राहुल को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने राहुल का -शेष पृष्ठ दो पर

भारत को विकसित देश बनने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती : राजनाथ

नई दिल्ली (हिंस)। दक्षिण कोरिया की यात्रा पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सियोल में भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में कहा कि इन 12 सालों में हुए बदलावों ने देश के लोगों को पक्का भरोसा दिया है कि भारत को विकसित देश बनने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। उन्होंने कोरिया के उन बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी, जिन्होंने देश की सेवा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। साउथ कोरिया के रक्षा मंत्री के साथ उन्होंने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की, जिसमें क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग के लिए प्रतिबद्धता जताई गई। सियोल में साउथ कोरिया के रक्षा अधिग्रहण कार्यक्रम प्रशासन मंत्री ली योंग-चुल के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बैठक हुई। दोनों मंत्री संयुक्त विकास, संयुक्त उत्पादन

और संयुक्त निर्यात के लिए रास्ते बनाने पर सहमत हुए। दोनों देशों के पारिस्थितिकी तंत्र को एकसाथ लाने के लिए रोडमैप पर चर्चा हुई। राजनाथ ने सियोल में अपने दक्षिण कोरियाई समकक्ष आह्न ग्यू के साथ बैठक में दोनों देशों के रक्षा, रक्षा उद्योग और -शेष पृष्ठ दो पर

अभिषेक बनर्जी से जुड़ी 17 संपत्तियों को नोटिस पर मेयर फिरहाद हकीम का बयान, *आमी जानी ना*

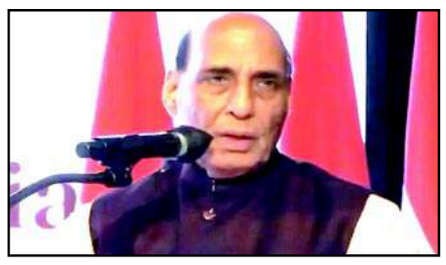

कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस के चार बार के विधायक और ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल कैबिनेट में पूर्व मंत्री, फिरहाद हकीम, जो अभी भी कोलकाता नगर निगम (केएमसी) के मेयर हैं, ने बुधवार को इस बात से इनकार किया कि उन्हें इस बात की जानकारी है कि निगम ने तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी के कथित स्वामित्व वाली या सह-स्वामित्व वाली संपत्तियों के खिलाफ जांच शुरू की है। खबरों के मुताबिक, केएमसी ने तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी के स्वामित्व या सह-स्वामित्व वाली 17 संपत्तियों को केएमसी अधिनियम, 1980 की धारा 400(1) के तहत नोटिस जारी किए हैं। ये संपत्तियां केएमसी के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। धारा 400(1) के तहत कथित तौर पर अवैध निर्माणों के मालिकों को नगर निगम

अधिकारियों के समक्ष पेश होने और अपना पक्ष रखने का अवसर मिलता है। मेयर फिरहाद -शेष पृष्ठ दो पर

मोदी के नेतृत्व में विश्वसनीय वैश्विक भागीदार के रूप में तेजी से उभर रहा भारत : मंत्री सारंग

भोपाल (हिंस)। मध्य प्रदेश के सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि आज ब्रिक्स राष्ट्र विकासशील देशों की आकांक्षाओं, ऊर्जा, नवाचार क्षमता एवं आर्थिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत नवाचार, उद्यमिता, युवा सशक्तीकरण, जलवायु उत्तरदायित्व एवं ग्लोबल साऊथ के विकास के लिए एक विश्वसनीय वैश्विक भागीदार के रूप में तेजी से उभर रहा है। मंत्री सारंग बुधवार को इंदौर में शुरू हुई ब्रिक्स यूथ

एंटरप्रेन्योरशिप वर्किंग ग्रुप की दो दिवसीय बैठक को संबोधित कर रहे थे। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के अंतर्गत आयोजित इस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में भारत सरकार की युवा कार्यक्रम एवं खेल राज्यमंत्री रक्षा खडसे, युवा कार्यक्रम विभाग की सचिव पल्लवी जैन गोविल, अतिरिक्त सचिव नितेश कुमार मिश्रा, ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि, स्टार्टअप लीडर्स, नीति निर्माता, शिक्षाविद् एवं युवा उद्यमी उपस्थित रहे। प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए विश्वास सारंग ने कहा कि भारत सदैव शांति, साझेदारी, मानवीय मूल्यों एवं वैश्विक सहयोग में विश्वास रखने वाला देश रहा है। उन्होंने *वसुधैव कुटुम्बकम् - विश्व एक परिवार है* की भारतीय अवधारणा का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत -शेष पृष्ठ दो पर

नीट-यूजी पुनर्परीक्षा को लेकर शिक्षा मंत्री की उच्चस्तरीय बैठक, फर्जी टेलीग्राम चैनलों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश

नई दिल्ली (हिंस)। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) पुनर्परीक्षा की निष्पक्ष और सुरक्षित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए बुधवार को केंद्रीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में परीक्षा के दौरान कड़ी सतर्कता और चाक-चौबंद सुरक्षा व्यवस्था पर जोर दिया गया। बैठक में शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) के महानिदेशक ने भी हिस्सा लिया। बैठक में परीक्षा की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई तथा संभावित कमजोरियों की पहचान कर समय रहते निवारक और सुधारात्मक कदम उठाने पर चर्चा हुई। इसके समानांतर शिक्षा

मंत्री ने मेटा, गूगल और टेलीग्राम जैसे प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक की। बैठक में प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार, विशेष रूप से टेलीग्राम चैनलों और गुमनाम ऑनलाइन समूहों के माध्यम से फैलाए -शेष पृष्ठ दो पर

गाय को *राष्ट्रीय पशु* का दर्जा देने में सरकार को क्यों हो रही हिचकिचाहट : मौलाना मदनी

नई दिल्ली (हिंस)। जमीअत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने एक बार फिर कहा है कि गाय को *राष्ट्रीय पशु* का दर्जा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी, बल्कि उन्हें खुशी होगी कि गाय के नाम पर होने वाली मॉब लिंचिंग और हिंसा की घटनाएं बंद हो जाएंगी। मौलाना मदनी ने बुधवार को एक बयान में सवाल किया कि जब देश की बहुसंख्यक आबादी गाय को केवल पवित्र ही नहीं मानती, बल्कि उसे मां का दर्जा देती है, तो फिर ऐसी क्या राजनीतिक मजबूरी है कि सरकार उसे *राष्ट्रीय पशु* घोषित करने से बच रही है? उन्होंने कहा कि यह मांग केवल हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि अनेक साधु-संत भी लंबे समय से यह मांग उठा रहे हैं। इसके

बावजूद यदि सरकार इस विषय को गंभीरता से नहीं ले रही है, तो इसका क्या अर्थ निकाला जाए? मौलाना मदनी ने कहा कि गाय के मुद्दे को एक राजनीतिक और भावनात्मक विषय बना दिया गया है। कुछ लोग योजनाबद्ध तरीके से गौकशी की अफवाह फैलाकर या पशु तस्करी के नाम पर निर्दोष लोगों को हिंसा का शिकार बना देते हैं। दुखद पहलू यह है कि लगातार झूठ और अफवाहों के जरिए पूरे देश में मुसलमानों की छवि इस तरह खराब कर दी गई है कि समाज का एक बड़ा वर्ग मुसलमानों को गाय -शेष पृष्ठ दो पर

मेघालय के उमरोई में जुटीं 12 देशों की सेनाएं शुरू हुआ बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास *प्रगति 2026*

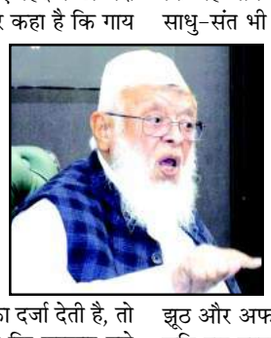

शिलांग (हिंस)। मेघालय के उमरोई सैन्य स्टेशन में प्रगति 2026 का मंगलवार से औपचारिक शुभारंभ हुआ। इस बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, फिलीपींस, सेशेल्स, श्रीलंका और वियतनाम सहित 12 मित्र देशों की सेनाएं भाग ले रही हैं। भारतीय सेना ने सभी विदेशी सैन्य दलों का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया, जो भारत की सांस्कृतिक विरासत और आतिथ्य का परिचायक रहा। *प्रगति* का पूरा नाम *पार्टनरशिप ऑफ रीजनल आर्मीज फॉर ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंडियन ओशन रीजन* है। यह अभ्यास समानता, मित्रता और पारस्परिक सम्मान की भावना के साथ आयोजित किया जा रहा है। उद्घाटन समारोह में वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों -शेष पृष्ठ दो पर

पेट्रोल में बड़ा बदलाव करने जा रही सरकार? अब 30 प्रतिशत तक इथेनॉल मिलाने की तैयारी

नई दिल्ली। देश में बढ़ती ऊर्जा सुरक्षा चिंताओं और पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच केंद्र सरकार ने पेट्रोल में 30 फीसदी तक इथेनॉल मिलाने के मानकों को अधिसूचित कर दिया है। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की नई अधिसूचना ने संकेत दिया है कि सरकार अब ई20 से आगे बढ़कर ज्यादा इथेनॉल मिश्रित ईंधन की दिशा में कदम बढ़ा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक बीआईएस ने ई22, ई25, ई27 और ई30 जैसे नए ईंधन मिश्रणों के लिए मानक तय किए हैं। इसका मतलब है कि पेट्रोल में क्रमशः 22 प्रतिशत, 25 प्रतिशत, 27 प्रतिशत और 30 प्रतिशत तक इथेनॉल मिलाया जा सकेगा। हालांकि फिलहाल यह केवल तकनीकी मानकों की अधिसूचना है, इसे पूरे देश में तुरंत लागू नहीं किया गया है। दरअसल, ईरान-अमेरिका-इजरायल तनाव और होरमुज जलडमरूमध्य पर मंडराते खतरे ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। दुनिया की करीब 20 फीसदी तेल सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है। ऐसे में सरकार तेल आयात पर निर्भरता कम करने के लिए इथेनॉल उत्पादन और उसके इस्तेमाल को बढ़ावा दे

रही है। सरकार पिछले कुछ वर्षों से ई 20 ईंधन को बढ़ावा दे रही है। हालांकि, इसके साथ पुरानी गाड़ियों के इंजन, माइलेज और मेंटेनेंस लागत को लेकर सवाल भी उठते रहे हैं। लेकिन केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरीने दावा किया था कि ई20 लागू होने के बाद इंजन खराब होने का कोई मामला सामने नहीं आया है। उन्होंने ब्राजील का उदाहरण देते हुए कहा था कि वहां वर्षों से इ27 ईंधन का इस्तेमाल बिना किसी दिक्कत के हो रहा है। उधर, ऑटोमोबाइल -शेष पृष्ठ दो पर

CLASSIFIED

For all kinds of classified advertisements please contact

97070-14771
86382-00107

MURTI AVAILABLE

Available all kinds of Marble & White Metal Murties, Ganesh Laxmi, Radha Krishna, Bishnu-Laxmi, Hanuman, Maa Durga, Saraswati, Shivling, Nandi etc. **ARTCLE WORLD,** S-29, 2nd Floor, Shoppers Point, Fancy Bazar, Guwahati-01, **Ph. : 94350-48866, 94018-06952**

कॉकरोच से लेकर परजीवियों तक, ऑनलाइन की दुनिया में चल रहे शब्दों की नई अंडरग्राउंड लड़ाई के पीछे की कहानी

नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर इन दिनों दो पार्टी का नाम तेजी से उभर रहा है। इनमें से एक है कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) और दूसरा है नेशनल पैरासिटिक फ्रंट (एनपीएफ), ये दो व्यंग्यात्मक राजनीतिक संगठन हैं जो ऑनलाइन दुनिया में चर्चा का विषय बने हुए है। अगर साफ तौर पर कहें तो, ये दोनों संगठन खुद को व्यंग्य बताते हैं, लेकिन सभी बेहतरीन भारतीय राजनीतिक व्यंग्यों की तरह, इनके मजाक इसलिए असरदार लग रहे हैं क्योंकि इनके पीछे की कहानी असली हैं। यह चर्चा तब शुरू हुई जब मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने टिप्पणी करते हुए कुछ बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच और परजीवियों से की थी। इसके बाद मानो इंटरनेट पर व्यंग्य की बाढ़ आ गई। इसके साथ ही कॉकरोच जनता पार्टी का उदय हुआ। जो कि खुद को आलसियों और बेरोजगारों की आवाज बताती है, जिसका मुख्यालय जहां भी इंटरनेट है, वहीं है। इसकी आधिकारिक वेबसाइट किसी राजनीतिक पोर्टल जैसी कम, और किसी जेन-जेड स्टैंड अप कॉमेडियन के सेट जैसी ज्यादा लगती है, जो एक चुनावी घोषणापत्र का रूप लिए हुए है। जानकारी के अनुसार, अभिजीत दिपके ने सीजेपी को 16 मई को ऑनलाइन की दुनिया में इसे लांच किया था। इसके बाद यह नाम तेजी से एक्स और इंस्टाग्राम पर छा गई। पार्टी ने कुछ ही दिनों में सोशल मीडिया पर दस लाख से ज्यादा फॉलोअर्स बना लिए, और इस तरह जो बात एक इंटरनेट मजाक के तौर पर शुरू हुई थी, वह एक वायरल राजनीतिक घटना बन गई। दिपके कहते हैं कि लोगों की प्रतिक्रिया उनकी मूल कल्पना से कहीं ज्यादा जबरदस्त रही। उन्होंने बताया कि विवाद के बाद एक अचानक सूझे ऑनलाइन मजाक के तौर पर जो बात शुरू हुई थी, वह अब महज एक मजाक से कहीं आगे निकल चुकी है। उन्होंने माना कि उन्हें इस तरह की प्रतिक्रिया की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी और कहा कि यह समर्थन पूरी तरह से स्वाभाविक था। दिपके ने यह भी बताया कि टिप्पणियों से जुड़ा विवाद ऑनलाइन शुरू होते ही, यह विचार लगभग तुरंत ही उनके मन में आ गया था। उन्होंने सोशल मीडिया पर मजाक में पोस्ट किया था, *क्या होगा अगर सारे कॉकरोच एक साथ आ जाएं?* और देखते ही देखते, यह विचार इंटरनेट पर आंदोलन में बदल गया। जिसमें हजारों लोग शामिल होना चाहते थे। हालांकि, पार्टी की वेबसाइट खुले तौर पर यह स्वीकार करती है कि यह प्रोजेक्ट एक व्यंग्य है, लेकिन इसका मजाकिया घोषणापत्र बड़ी ही होशियारी से असली राजनीतिक चिंताओं को दर्शाता है। इसके साथ ही सीजेपी की अपनी एक वैचारिक ब्रांडिंग है। इसके समर्थक खुद को बेरोजगारी, महंगाई, प्रवेश परीक्षाओं, लिंक्डइन पर आने वाली मोटिवेशनल पोस्ट्स और उन रिश्तेदारों से जूझकर बचे हुए मजबूत लोगों के तौर पर पेश करते हैं, जो अक्सर पूछते हैं, बेटा आजकल क्या कर रहे हो? सीजेपी के बाद एंट्री हुई नेशनल पैरासिटिक फ्रंट की, एक तरफ सीजेपी आलसी और बेरोजगार लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, तो दूसरी तरफ नेशनल पैरासिटिक फ्रंट उस अपमान के दूसरे हिस्से को दिखाने का काम करता है। एनपीएफ की ऑनलाइन मौजूदगी गंभीर राजनीतिक संगठनों के अंदाज की नकल करती है, लेकिन साथ ही बेतुकी बातों को और भी आगे ले जाती है। अगर आसान भाषा में कहा जाए तो यह फ्रंट, बढ़ा-चढ़ाकर कही गई क्रांतिकारी भाषा को व्यंग्यात्मक के रूप में इस्तेमाल करता है। इसकी वेबसाइट पर यह भी बताया गया है कि यह नाम जान-बूझकर रखा गया है। वेबसाइट कहती है कि हम खुद को एक टूटी हुई व्यवस्था से जोड़ते हैं, ताकि उससे फायदा न उठा सकें, बल्कि उसे अंदर से बदलने के लिए मजबूर कर सकें। कुल मिलाकर, इन दोनों समूहों ने मिलकर भारत में गठबंधन का अब तक का सबसे अजीब दौर खड़ा कर दिया है।

हिंद महासागर पोत *सुनयना* कोच्चि लौटा, वाटर कैनन सैल्यूट के साथ हुआ स्वागत

नई दिल्ली (हिंस)। भारतीय नौसेना का जहाज *सुनयना* हिंद महासागर पोत (आईओएस) सागर 7 सप्ताह की यात्रा करने के बाद बुधवार को कोच्चि लौट आया। इस दौरान इस जहाज ने इंडो-पैसिफिक और हिंद महासागर क्षेत्र के सबसे स्ट्रेटेजिक रूप से अहम पानी में हजारों नॉटिकल मील की दूरी तय की। इस यात्रा में साझेदार रहे 16 देशों के 38 क्रू मेंबर्स के साथ यह संयुक्त मिशन पूरा करके भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में क्षेत्रीय समुद्री सहयोग और सामूहिक सुरक्षा को मजबूत किया। भारतीय नौसेना के साथ बांग्लादेश, इंडोनेशिया, केन्या, मलेशिया, मॉरीशस, मालदीव, मोजाम्बिक, म्यांमार, सेशेल्स, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, तंजानिया, थाईलैंड, तिमोर लेस्ते और संयुक्त अरब अमीरात ने मिलकर यह तैनाती की थी। कोच्चि बंदरगाह लौटने पर आईएनएस सुनयना का वाटर कैनन सैल्यूट के साथ औपचारिक स्वागत किया गया। नौसेना की तेज इंटरसेप्टर नौकाओं से एस्कॉर्ट किए गए इस जहाज का दक्षिणी नौसेना कमान के अधिकारियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। जहाज के पहुंचने पर दक्षिणी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ वाइस एडमिरल समीर सक्सेना ने तैनाती के दौरान 16 देशों के 38 क्रू मेंबर्स के पेशेवर व्यवहार और बेहतरीन टीमवर्क को सराहा। इस मौके पर वाइस एडमिरल समीर सक्सेना ने कहा कि 2 अप्रैल को मुंबई से रवाना होते समय आईओएस सागर अपने साथ भारत का दोस्ती, विश्वास, सबको साथ लेकर चलने और साझा समुद्री जिम्मेदारी का संदेश लेकर गया था। भारतीय नौसेना ने लगातार ऑपरेशनल मौजूदगी, मानवीय मदद, क्षमता निर्माण और मित्र देशों के साथ साझेदारी के जरिए इस विजन को एक्शन में बदला है। सेरेमनी के दौरान कर्मचारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने जोर दिया कि सुरक्षित, स्थिर और खुशहाल समुद्री माहौल पक्का करने के लिए क्षेत्रीय समुद्री सेनाओं के बीच लगातार मिलकर काम करने और ऑपरेशनल तालमेल जरूरी है। उन्होंने बताया कि इस तैनाती से संयुक्त प्रशिक्षण, पेशेवर लेनदेन और मिलकर की जाने वाली ऑपरेशनल गतिविधियों के जरिए ऑपरेशनल तालमेल और आपसी समझ में काफी बढ़ोतरी हुई है।

शुभेंदु अधिकारी के निजी सहयोगी की हत्या के मामले में पांचवां आरोपी गिरफ्तार

कोलकाता (हिंस)। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने वाराणसी से एक और आरोपी को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। यह चंद्रनाथ रथ की हत्या से जुड़े मामले में पांचवीं गिरफ्तारी है। अधिकारियों के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी की पहचान विनय राय उर्फ पपम राय के रूप में हुई है, जिसे मंगलवार रात को हिरासत में लिया गया। वह मूल रूप से गाजीपुर जिले के जमानी क्षेत्र का निवासी है, लेकिन पिछले कई वर्षों से वाराणसी में रहकर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहा था। सीबीआई ने आरोपी को वाराणसी की स्थानीय अदालत में पेश किया, जहां से दो दिन की ट्रांजिट रिमांड हासिल कर उसे आगे की पूछताछ के लिए कोलकाता लाया गया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि खुफिया इनपुट और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को रिजर्व पुलिस लाइंस क्षेत्र से हिरासत में लिया गया।

बंगाल के फलता विधानसभा पर पुनर्मतदान की तैयारियां पूरी, 285 बूथों पर होगी वोटिंग

कोलकाता (हिंस)। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट पर गुरुवार, 21 मई को होने वाले पुनर्मतदान के लिए चुनाव आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में कथित छेड़छाड़ और मतदान प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं के आरोपों के बाद पूरे विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान कराया जा रहा है। आयोग ने इस बार सुरक्षा, निगरानी और प्रशासनिक सतर्कता को लेकर अभूतपूर्व व्यवस्था की है। निर्वाचन आयोग के अनुसार फलता विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,36,444 मतदाता हैं। इनमें 1,21,300 पुरुष, 1,15,135 महिला और 9 तृतीय लिंग मतदाता शामिल हैं। इसके अलावा 93 सेवा मतदाता भी हैं। 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के 4343 युवा मतदाता पहली बार मतदान करेंगे। क्षेत्र में 85 वर्ष से अधिक आयु के 1445 मतदाता तथा 100 वर्ष से अधिक आयु के 26 मतदाता भी दर्ज हैं। दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 2109 है। निर्वाचन आयोग के अनुसार, पुनर्मतदान के लिए कुल 285 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 261 मुख्य और 24 सहायक मतदान केंद्र शामिल हैं। चुनाव मैदान में कुल 6 उम्मीदवार हैं और सभी पुरुष उम्मीदवार हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस बार प्रत्येक मतदान केंद्र पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के 8 जवान तैनात किए जाएंगे, जो एक पूर्ण सेक्शन के बराबर होंगे।

पृष्ठ एक का शेष

भारत-इटली आपसी ...

अपराधों को रोकने के लिए परिवर्तन एजेंसियां सहयोग करेंगी। भारत और इटली 2027 को संस्कृति और पर्यटन के वर्ष के रूप में मनायेंगे। भारतीय नर्सों को इटली में रोजगार के अवसर प्रदान करने और हेल्थ केयर सहयोग को बढ़ाने पर दोनों देश सहमत हुए हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स लोथल (गुजरात), उच्च शिक्षा और समुद्री ट्रांसपोर्ट सुविधाओं के विकास, कृषि, समुद्री उत्पाद, आयुर्वेद तथा मौसम और जलवायु परिवर्तन को लेकर भी दोनों देशों के बीच में समझौता हुआ है। साथ ही एलेट्रा में सिंक्रोट्रोन विकिरण सुविधा में भारतीय शोधकर्ताओं को पहुंच प्राप्त होगी। वार्ता के बाद दोनों नेताओं ने संयुक्त वक्तव्य भी दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री मेलोनी के नेतृत्व में भारत-इटली संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। उन्होंने कहा कि भारत-इटली संयुक्त रणनीतिक कार्ययोजना 2025-2029 दोनों देशों की साझेदारी को व्यावहारिक और भविष्य उन्मुख ढांचा प्रदान करती है तथा इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इटली विश्वभर में डिजाइन और प्रिसीजन के लिए प्रसिद्ध है, जबकि भारत बड़े पैमाने, प्रतिभा और किफायती नवाचार की ताकत के रूप में पहचाना जाता है। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय व्यापार को 20 अरब यूरो तक पहुंचाने की दिशा में तेजी से प्रगति हो रही है। भारत में कार्यरत 800 से अधिक इतालवी कंपनियां भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभा रही हैं। उन्होंने कहा कि रक्षा औद्योगिक रोडमैप ने सह-विकास और सह-उत्पादन की दिशा में नया मार्ग प्रशस्त किया है। दोनों देश मिलकर शिपिंग, बंदरगाह आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और ब्लू इकॉनमी के क्षेत्रों में काम करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली इस बात पर एकमत हैं कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर खतरा है। आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ दोनों देशों की साझा पहल ने दुनिया के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि जिम्मेदार लोकतंत्र केवल आतंकवाद की निंदा ही नहीं करते बल्कि उसके आर्थिक नेटवर्क को तोड़ने के लिए ठोस कदम भी उठाते हैं। वहीं, इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने भारत-इटली संबंधों को परिश्रम से जोड़ा और हिन्दी में कहा भी *परिश्रम ही सफलता की कुंजी है।* उन्होंने कहा कि इसका अर्थ है कि कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है और हम अपने रिश्तों को इसी तरह से बनाते हैं जहां कड़ी मेहनत ही सफलता का कारण बनती है। मलोनी ने अपने वक्तव्य में अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का उल्लेख किया जिसमें यूक्रेन संघर्ष, ईरान संकट और मुक्त एवं खुले हिन्द-प्रशांत का विषय शामिल रहा। उन्होंने कहा कि भारत-इटली मिलकर शांति और स्थिरता के लिए हमेशा अपनी भूमिका निभाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि हमने 2027 के लिए इटली-भारत संस्कृति और पर्यटन वर्ष शुरू करने का निर्णय लिया है, जो हमारी सदियों पुरानी संस्कृतियों को संवाद विकसित करने और उन्हें अधिकाधिक रूप से जोड़ने का अनूठा अवसर है। उन्नत विनिर्माण, अवसंरचना, ऊर्जा, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, रक्षा- ये ऐसे सहयोग क्षेत्र हैं जिन पर हम कड़ी मेहनत कर रहे हैं। महत्वपूर्ण खनिज, कृषि-उद्योग, समुद्री परिवहन, पर्यटन और संस्कृति भी महत्वपूर्ण अवसर हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत-इटली की मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी की पुष्टि की और व्यापार, प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्वच्छ ऊर्जा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में चर्चा की। उन्होंने पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर भी विचार-विमर्श किया।

बांग्लादेश में भारतीय दूतावास...

बताया कि शव पर किसी भी तरह की चोट, घाव या संघर्ष के निशान नहीं मिले हैं। शुरुआती तौर पर आशंका जताई जा रही है कि नरेंद्र की मौत हार्ट अटैक या स्ट्रोक की वजह से हुई है। उन्होंने कहा कि मुमकिन है कि रात के दौरान या सुबह बाथरूम से निकलने के बाद उन्हें दिल का दौरा या स्ट्रोक आया हो। असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ होगी। पुलिस के मुताबिक, शव को भारतीय अधिकारियों की मौजूदगी में चिटगांव मेडिकल कॉलेज अस्पताल के मॉर्चरी भेजा गया। भारतीय दूतावास की ओर से फिलहाल इस घटना पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारतीय अधिकारी बांग्लादेश प्रशासन और पुलिस के साथ लगातार संपर्क में हैं ताकि मौत के कारणों पूरी जांच हो सके। घटना के बाद एहतियात के तौर पर भारतीय दूतासाव के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जांच एजेंसियां स्टाफ डॉर्मिटरी और आसपास के इलाके से सबूत जुटाने में लगी हुई हैं। चिटगांव मेट्रोपॉलिटन पुलिस के डिप्टी कमिश्नर आमिरुल इस्लाम ने कहा कि मामला एक विदेशी दूतावास से जुड़ा है, इसलिए पुलिस सीमित जानकारी ही शेयर कर रही है। उन्होंने कहा कि ज्यादा जानकारी के लिए भारतीय मिशन से संपर्क किया जा सकता है।

ये उनकी अराजकतावादी...

एक वीडियो साझा किया, जिसमें कांग्रेस नेता कथित तौर पर एक जनसभा में उपस्थित लोगों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सदस्यों को यह बताने के लिए कहते सुनाई दे रहे हैं कि मोदी और शाह *गद्दार* हैं जिन्होंने देश बेच दिया और संविधान तथा राष्ट्रीय प्रतीकों पर हमला किया। वीडियो में राहुल को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि आपको खड़ा होना होगा और लड़ना होगा। जब आरएसएस कार्यकर्ता आपके घरों में आकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बारे में बात करें, तो आपको उन्हें बताना होगा कि उनका संगठन, मोदी और शाह गद्दार हैं। उन्होंने हमारे देश को बेचने की कोशिश की है और हमारे संविधान, अंबेडकर जी और महात्मा गांधी पर हमला किया है। एक्स पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में भंडारी ने कहा कि गांधी की टिप्पणियां शहरी नक्सलियों की मानसिकता को दर्शाती हैं और आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता देश के हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने 140 करोड़ भारतीयों को गद्दार कहा है। इससे पता चलता है कि उनका नियंत्रण भारत विरोधी ताकतों के हाथ में है। भंडारी ने आगे आरोप लगाया कि गांधी इसलिए नाराज हैं क्योंकि मोदी के नेतृत्व में *भारत एकजुट है* और उन पर भारतीय राज्य को ही निशाना बनाने का आरोप लगाया।

भारत को विकसित देश ...

सामरिक सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की, जिसमें क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग के लिए प्रतिबद्धता जताई गई। दोनों रक्षा मंत्रियों ने नेशनल डिफेंस कॉलेज ऑफ इंडिया और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी ऑफ कोरिया के बीच रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने और यूएन पीसकीपिंग कोऑपरेशन पर एग्रीमेंट्स का आदान-प्रदान किया, जिससे भारत-कोरिया के बीच साझेदारी और मजबूत एवं बहुआयामी बनी। सियोल में भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में राजनाथ सिंह ने कहा कि पहले हमें जो भी चाहिए होता था, हम दूसरे देशों से आयात करते थे। अब हालात बदल गए हैं। पहले भारत विदेशों से हथियारों का आयात करता था, लेकिन आज हम रक्षा निर्यात कर रहे हैं, इसमें वेपन सिस्टम और बाकी सब कुछ शामिल है। हम 40 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा निर्यात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देशों के बीच स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत होने की उम्मीद है। आज का भारत बिल्कुल अलग है। भारत सेमीकंडक्टर सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अर्थशास्त्री हमारे विकास मॉडल को वेलफेयर पॉलिटिक्स का नया मॉडल कह रहे हैं, जिससे लोगों की जिंदगी बेहतर हो रही है। बारह साल पहले शायद ही किसी ने सोचा होगा कि आने वाला दशक भारत के लिए बदलाव लाने वाला दशक होगा, लेकिन इन 12 सालों में हुए बदलावों ने देश के लोगों को पक्का भरोसा दिया है कि भारत एक विकसित भारत बनेगा और दुनिया की कोई भी ताकत इसे रोक नहीं सकती।

अभिषेक बनर्जी से जुड़ी ...

हकीम ने भी इस तरह के नोटिस जारी किए जाने के बारे में किसी भी तरह की जानकारी होने से इनकार किया। हकीम ने बुधवार दोपहर मीडिया से बातचीत में कहा कि केएमसी अधिनियम के तहत, मैं केवल एक नीति निर्माता हूं। मुझे ऐसे नोटिसों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मुझे इस घटनाक्रम के बारे में भी किसी ने सूचित नहीं किया था। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि केएमसी आयुक्त को ऐसे मामलों में निर्णय लेने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि मुझे इस मामले में किसी ने कुछ नहीं बताया था। केएमसी के मेयर का इस बात पर कोई प्रभाव नहीं हो सकता कि निगम के भवन विभाग ने किस मकान को गिराने का फैसला किया है। पद के नाते केएमसी कमिश्नर को ऐसे फैसले लेने का अधिकार है। बता दें कि मंगलवार दोपहर को दक्षिण कोलकाता के कालीघाट स्थित अपने आवास पर पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अध्यक्षता में नवनिर्वाचित तृणमूल कांग्रेस विधायकों की बैठक में अभिषेक बनर्जी भी उपस्थित थे। खबरों के मुताबिक उन्होंने बैठक में कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह राज्य में भाजपा के नेतृत्व वाली नई सरकार के सामने नहीं झुकेंगे। अभिषेक बनर्जी ने बैठक में कहा कि वे जो चाहें करें। वे मुझे नोटिस भेज सकते हैं। वे मेरा घर भी गिरा सकते हैं। लेकिन मैं कभी नहीं झुकूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं भाजपा के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखूंगा। इसी बीच, भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई ने 43 संपत्तियों की एक सूची जारी की, जिनके बारे में भाजपा खेमे ने आरोप लगाया कि वे अभिषेक बनर्जी से जुड़ी हैं। हालांकि, तृणमूल कांग्रेस ने इस सूची को मनगढ़ंत और अविश्वसनीय बताया।

मोदी के नेतृत्व में ...

की सांस्कृतिक एवं सभ्यतागत विरासत विश्व को सद्भाव, समावेशी विकास एवं सामूहिक कल्याण की दिशा प्रदान करती रही है। सारंग ने कहा कि वर्ष 2006 में भारत सहित चार देशों से प्रारंभ हुआ ब्रिक्स समूह आज 11 सदस्य देशों तक विस्तारित हो चुका है, जो विश्व की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करता है तथा वैश्विक जीडीपी में लगभग 35-40 प्रतिशत योगदान देता है। ब्रिक्स केवल एक आर्थिक गठबंधन नहीं, बल्कि व्यापार, प्रौद्योगिकी, नवाचार एवं सतत विकास के भविष्य को दिशा देने वाला परिवर्तनकारी वैश्विक मंच है। उन्होंने कहा कि विश्व अब *सूचना युग* में प्रवेश कर चुका है, जहां डेटा, तकनीक एवं ज्ञान नवाचार और उद्यमिता की सबसे बड़ी शक्ति बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि जब मानव मस्तिष्क को जानकारी, तकनीक एवं ज्ञान से सशक्त किया जाता है, तब वही विचार स्टार्टअप, उद्यमिता और सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन की शक्ति बनते हैं। मंत्री सारंग ने 20 मई के ऐतिहासिक महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि इसी दिन वर्ष 1498 में पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को-डी-गामा समुद्री मार्ग से भारत पहुंचे थे, जिसने वैश्विक व्यापार एवं अंतर्राष्ट्रीय संपर्क का नया अध्याय प्रारंभ किया। सदियों बाद आज विश्व पुन: भारत में एकत्रित हुआ है, लेकिन इस बार उद्देश्य व्यापार मार्गों की खोज नहीं, बल्कि नवाचार, उद्यमिता, तकनीक एवं वैश्विक सहयोग के नए मार्ग निर्मित करना है। उन्होंने 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय मानव संसाधन दिवस का उल्लेख करते हुए कहा कि जिस प्रकार मधुमक्खियां टीमवर्क, समन्वय एवं सतत पारिस्थितिकी तंत्र का प्रतीक हैं, उसी प्रकार मानव संसाधन किसी भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति होते हैं। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देशों के पास विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी एवं कुशल मानव संसाधन क्षमता है, जो नवाचार एवं उद्यमिता के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व प्रदान कर सकती है। मंत्री सारंग ने कहा कि मध्य प्रदेश नवाचार, निवेश, औद्योगिक विकास एवं स्टार्टअप ग्रोथ का प्रमुख केंद्र बनकर उभर रहा है। उन्होंने राज्य की उत्कृष्ट कनेक्टिविटी, औद्योगिक कॉरिडोर, निवेश-अनुकूल वातावरण एवं आईटी, एग्रीटेक, रिन्यूएबल एनर्जी तथा इनोवेशन क्षेत्रों में उपलब्ध संभावनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इंदौर, जो भारत का सबसे स्वच्छ शहर एवं मध्य भारत का इनोवेशन हब है, आधुनिक भारत की स्वच्छता, उद्यमिता, संस्कृति एवं आतिथ्य भावना का उत्कृष्ट उदाहरण है। पवित्र धार्मिक ग्रंथ श्रीमद्भगवद्गीता का उल्लेख करते हुए सारंग ने कहा कि भारत की 18वीं ब्रिक्स समिट की अध्यक्षता का विशेष सांकेतिक महत्व है, क्योंकि श्रीमद्भगवद्गीता के भी 18 अध्याय हैं, जो मानवता को कर्तव्य, निष्काम कर्म एवं विश्व कल्याण का संदेश देते हैं। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानव दर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि विकास सदैव मानव-केंद्रित, समावेशी एवं समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण के प्रति समर्पित होना चाहिए। सारंग ने विश्वास व्यक्त किया कि ब्रिक्स यूथ एंटरप्रेन्योरशिप वर्किंग ग्रुप मीटिंग-2026 ब्रिक्स देशों के बीच दीर्घकालिक सहयोग को सुदृढ़ करेगी तथा भारत एवं मध्य प्रदेश को नवाचार, निवेश, उद्यमिता एवं युवा-नेतृत्व वाले विकास के महत्वपूर्ण वैश्विक केंद्रों के रूप में स्थापित करेगी।

नीट-यूजी पुनर्परीक्षा को ...

जा रहे भ्रामक दावों पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई। अधिकारियों ने बताया कि बड़ी परीक्षाओं से पहले कई टेलीग्राम चैनल अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं और फर्जी पेपर लीक, क्लिकबेट सामग्री तथा अपुष्ट सूचनाएं फैलाकर छात्रों और अभिभावकों में भय, तनाव और भ्रम पैदा करते हैं। कई संदिग्ध लिंक लोगों को ऑटोमेटेड बॉट्स और फर्जी समूहों तक पहुंचाते हैं, जिनका उद्देश्य गलत सूचना को तेजी से फैलाना होता है। खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी के अनुसार कई संदिग्ध चैनल सीमित संख्या के फोन नंबरों के जरिए संचालित किए जा रहे हैं, जिससे संगठित गतिविधियों की आशंका जताई गई है। मामले को गंभीरता से लेते हुए शिक्षा मंत्री ने ऐसे नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने परीक्षा से पहले फर्जी सूचना, दुष्प्रचार और अफवाह फैलाने वाले चैनलों की सक्रिय पहचान कर उन्हें ब्लॉक और हटाने के लिए अभियान चलाने को कहा। प्रधान ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को शिक्षा मंत्रालय, एनटीए और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर तेजी से कार्रवाई करनी होगी, ताकि परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बनी रहे और छात्रों को भ्रामक सूचनाओं से बचाया जा सके। उन्होंने दोहराया कि छात्रों को गुमराह करने वाली बातों से बचाना और परीक्षा प्रक्रिया पर जनता का भरोसा बनाए रखना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उल्लेखनीय है कि एनटीए देश में मेडिकल कोर्स में दाखिले के लिए नीट-यूजी आयोजित करती है। इस वर्ष 3 मई को नीट-यूजी की परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा में कथित अनियमितताओं और जांच एजेंसियों से मिले इनपुट के आधार पर एनटीए ने परीक्षा को रद्द करते हुए 21 जून को दोबारा परीक्षा कराने का फैसला किया है। यह ऑफलाइन परीक्षा होगी, जिसमें 22 लाख से अधिक छात्रों के बैठने की उम्मीद है। इस दौरान छात्रों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा। सरकार ने पूरे मामले की व्यापक जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी है।

गाय को राष्ट्रीय पशु ...

का विरोधी समझने लगा है। मॉब लिंचिंग की एक बड़ी वजह यही मानसिकता है। उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले बड़ी संख्या में मुसलमान गाय पालते थे और उससे दूध का व्यवसाय करते थे, लेकिन वर्ष 2014 के बाद देश में जो नफरत का माहौल पैदा हुआ, उसके बाद मुसलमानों ने एहतियात बरतनी शुरू कर दी और अब अधिकांश लोग गाय की जगह भैंस पालना अधिक सुरक्षित समझते हैं। मौलाना मदनी ने कहा कि वर्ष 2014 में मुंबई में आयोजित एक सम्मेलन में साधु-संतों और विभिन्न धर्मों के लोगों के साथ मिलकर देश में शांति और एकता कायम करने के उद्देश्य से गाय को *राष्ट्रीय पशु* घोषित करने की मांग उठाई गई थी। उन्होंने कहा कि जमीअत उलमा-ए-हिंद आजादी से पहले और आजादी के बाद भी लगातार मुसलमानों को यह सलाह देती रही है कि ऐसा कोई काम न किया जाए, जिससे दूसरे धर्मों के लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हों। इस्लाम इसकी अनुमति नहीं देता, बल्कि बहुधार्मिक समाज में आपसी सम्मान के साथ रहने की शिक्षा देता है। उन्होंने कहा कि जमीअतअपने मंच से लगातार मुसलमानों को यह संदेश देती रही है कि प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी से बचा जाए। हर साल ईद-उल-अजहा के अवसर पर अखबारों में जो विज्ञापन प्रकाशित कराया जाता है, उसमें इस बात पर विशेष जोर दिया जाता है। मौलाना मदनी ने गाय के मुद्दे पर दोहरे कानून को लेकर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के पक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि जब देश एक है, तो कानून भी एक होना चाहिए, लेकिन देश में पशु वध से संबंधित कानून सभी राज्यों में समान रूप से लागू नहीं हैं। उन्होंने कहा कि देश के कई राज्यों में खुलेआम गोमांस खाया जाता है और वहां इस पर कोई रोक नहीं है। यहां तक कि एक केंद्रीय मंत्री भी सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार कर चुके हैं कि वे बीफ खाते हैं।

मेघालय के उमरोई में ...

और कई गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। इस अवसर पर भारतीय सेना के अतिरिक्त महानिदेशक (इन्फैंट्री) मेजर जनरल सुनील श्योराण ने सभी प्रतिभागी देशों के सैन्य दलों का स्वागत करते हुए वर्तमान सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सभी देशों को खुले मन और पारस्परिक सम्मान के साथ एक-दूसरे के अनुभवों से सीखना चाहिए। अधिकारियों के अनुसार, इस सैन्य अभ्यास का मुख्य उद्देश्य सहभागी देशों के बीच संयुक्त अभियानों में बेहतर समन्वय स्थापित करना, साझा सहयोग के क्षेत्रों की पहचान करना तथा आतंकवाद-रोधी अभियानों और खुफिया सूचनाओं के आदान-प्रदान को मजबूत बनाना है। दो सप्ताह तक चलने वाले इस अभ्यास का फोकस अर्ध-पहाड़ी और जंगल क्षेत्रों में आतंकवाद-रोधी अभियानों पर रहेगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम में संयुक्त योजना अभ्यास, सामरिक स्तर की ड्रिल और समन्वित अभियान शामिल किए गए हैं, जिनका उद्देश्य चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में सैनिकों की सहनशक्ति, अनुकूलन क्षमता और सामरिक दक्षता को बढ़ाना है। अभ्यास के दौरान भारतीय रक्षा और प्रौद्योगिकी कंपनियां *आत्मनिर्भर भारत* पहल के तहत स्वदेशी सैन्य उपकरणों और तकनीकी नवाचारों का प्रदर्शन भी करेंगी। इससे रक्षा क्षेत्र में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता और तकनीकी क्षमता को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। अधिकारियों ने उम्मीद जताई कि *प्रगति 2026* क्षेत्रीय साझेदार देशों के बीच सैन्य सहयोग को और मजबूत करेगा तथा साझा सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक रणनीति विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

पेट्रोल में बड़ा बदलाव...

और बायोफ्यूल इंडस्ट्री लंबे समय से ज्यादा इथेनॉल मिश्रण वाले ईंधनों को बढ़ावा देने की मांग कर रही है। मारुति सुजुकि के चेयरमैन आरसी भार्गव ने कहा कि अगर सरकार इसे अनिवार्य बनाती है तो कंपनी इसके लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि विशेषज्ञों ने चेतावनी भी दी है कि ई20 से आगे बढ़ने के लिए देश को ईंधन उपलब्धता, वाहनों की तकनीकी क्षमता और वितरण व्यवस्था को मजबूत करना होगा। अलग-अलग राज्यों की जलवायु और सड़क परिस्थितियों को देखते हुए यह बदलाव आसान नहीं माना जा रहा है। इसके अलावा, विशेषज्ञों का मानना है कि अगर भारत पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा और बढ़ाना चाहता है, तो चीनी निर्यात पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि इथेनॉल उत्पादन के लिए बड़ी मात्रा में गन्ने और चीनी की जरूरत पड़ेगी।

अंबुबाची मेला ...

के मेले में पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। श्रद्धालुओं की सुविधा और भीड़ प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष पांडू की ओर का अतिरिक्त मार्ग भी खोला जाएगा। अब श्रद्धालु मौजूदा नर्सरी मार्ग के अलावा नए विकसित पांडू मार्ग से भी मंदिर तक पहुंच सकेंगे, जिससे आवागमन अधिक सुगम होने की उम्मीद है। मेले के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए मंदिर परिसर में अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरे लगाने की तैयारी भी की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। इधर, कई साधु-संत पहले ही कामाख्या धाम पहुंच चुके हैं, जबकि आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी होने की संभावना है। तंत्र साधना का मुख्य केंद्र माने जाने वाला अंबुबाची मेला असम का एक प्रमुख आध्यात्मिक आयोजन है, जिसमें हर वर्ष नीलाचल पहाड़ियों पर स्थित मां कामाख्या के दरबार में श्रद्धालुओं का विशाल जनसमूह उमड़ता है।

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ...

निधन हो गया। वह 92 वर्ष के थे। उनके निधन से राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में शोक की लहर है। बीसी खंडूरी भारतीय सेना में मेजर जनरल के पद पर सेवाएं देने के बाद राजनीति में आए थे और उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी साफ-सुथरी छवि और प्रशासनिक क्षमता के लिए उन्हें व्यापक सम्मान प्राप्त था।

मणिपुर के नागा बहुल इलाकों में छह पुरुषों की कैद को लेकर महिलाओं के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन शुरू

इंफाल। मणिपुर के कई नागा बहुल इलाकों में बुधवार को हजारों महिलाएं सड़कों पर उतर आईं और कथित तौर पर कुकी उग्रवादियों द्वारा अपहरण किए जाने के बाद से बंधक बनाए गए छह नागा पुरुषों की तत्काल रिहाई की मांग की। सेनापति, उखरुल, चंदेल, तामेंगलोंग और नोनी सहित कई जिलों में धरने और न्याय की मांग के साथ विरोध प्रदर्शन हुए, जिसमें प्रतिभागियों ने लापता पुरुषों के परिवारों के साथ एकजुटता व्यक्त की और सरकार से तत्काल हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। सेनापति जिला मुख्यालय में दैनिक जीवन अस्त-व्यस्त हो गया क्योंकि विरोध प्रदर्शन के आह्वान के जवाब में बाजार बंद रहे और व्यावसायिक वाहन सड़कों से नदारद रहे। प्रदर्शनकारियों ने *बंधकों को रिहा किया जाए* और *कुकी उग्रवादियों, अपहरण बंद करो* जैसे संदेशों वाले तख्तियां ले रखी थीं, साथ ही लापता लोगों की सुरक्षित वापसी की मांग करते हुए नारे लगा रहे थे।

नागा महिला संघ की अध्यक्ष प्रिसिला थिउमाई ने कहा कि ये विरोध प्रदर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार को एक कड़ा संदेश देने के उद्देश्य से किए गए थे। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि उनकी सरकार को न्याय दिलाना चाहिए और बंधकों को जल्द से जल्द बिना किसी नुकसान के वापस लाना चाहिए। दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि दोषियों को तुरंत गिरफ्तार कर कानून के कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। केंद्र के साथ निलंबित सैन्य अभियान (एसओओ) समझौते का पालन कर रहे कुकी उग्रवादियों द्वारा इस तरह के कृत्य आम बात हो गए हैं। यह अस्वीकार्य है। हम केंद्र से कुकी उग्रवादियों के साथ एसओओ समझौते को रद्द करने की अपील करते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, ये अपहरण 13 मई की एक बड़ी घटना से जुड़े हुए हैं, जब कांगपोकपी और सेनापति जिलों में सशस्त्र समूहों द्वारा 38 से अधिक लोगों को बंधक बना लिया गया था, यह घटना कांगपोकपी जिले में एक घात लगाकर किए गए हमले में तीन चर्च नेताओं की हत्या के कुछ ही घंटों बाद हुई थी। अब तक अपहृत किए गए 31 लोगों को रिहा किया जा चुका है, जिनमें कोंसाखुल गांव की 12 नागा महिलाएं, कांगपोकपी जिले के कुकी समुदाय के 16 सदस्य और दो सेल्सियन भाई शामिल हैं। हालांकि, शेष छह नागा पुरुषों का क्या हुआ और वे कहां हैं, यह अभी भी अज्ञात है। इस बीच, राज्य में कुकी जनजातियों का प्रतिनिधित्व करने वाली सर्वोच्च संस्था, कुकी इनपी मणिपुर ने भी दावा किया है कि कुकी समुदाय के 14 सदस्य अभी भी नागा समूहों द्वारा बंधक बनाए हुए हैं, जो मौजूदा संकट के निरंतर तनाव और जटिलता को उजागर करता है।

समय पर पेंशन वितरण सुनिश्चित करने के मुख्यमंत्री शर्मा के फैसले का भाजपा ने किया स्वागत

गुवाहाटी (हिंस)। असम प्रदेश भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा द्वारा पेंशन प्रक्रिया में देरी पर दंडात्मक प्रावधान लागू करने के निर्णय का स्वागत करते हुए इसे एक ऐतिहासिक और जनहितकारी कदम बताया है। असम प्रदेश भाजपा ने कहा कि यह फैसला राज्य सरकार की पारदर्शी, जवाबदेह और जनकेंद्रित प्रशासनिक व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पार्टी ने कहा कि राज्य के सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों ने अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय असम के विकास और सेवा में समर्पित किया है तथा समय पर पेंशन प्राप्त करना उनका अधिकार है। मुख्यमंत्री डॉ. शर्मा ने कहा कि पेंशनरों ने असम की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और उन्हें सम्मान तथा गरिमा के साथ समय पर पेंशन मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार अब ऐसी जवाबदेही व्यवस्था लागू कर रही है, जिसके तहत पेंशन प्रक्रिया में अनावश्यक देरी करने वाले अधिकारियों पर आर्थिक दंड लगाया जाएगा। प्रशासनिक सुधार, प्रशिक्षण, पेंशन एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, पेंशन मामलों में देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर प्रतिदिन 250 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा 5,000 रुपए निर्धारित की गई है। देरी वाले मामलों की पहचान प्रत्येक महीने

कृतज्ञता पोर्टल के माध्यम से की जाएगी तथा जुर्माने की वसूली फिनअसम प्रणाली के जरिए की जाएगी। भाजपा ने कहा कि यह सुधार सभी विभागों में जवाबदेही सुनिश्चित करेगा और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बिना किसी अनावश्यक परेशानी के पेंशन लाभ प्राप्त करने में मदद करेगा। पार्टी ने इसे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में संवेदनशील और प्रभावी शासन का एक और उदाहरण बताया। भाजपा असम प्रदेश ने इस ऐतिहासिक पहल के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए राज्य के पेंशनरों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए सरकार के प्रयासों को पूर्ण समर्थन देने की बात कही।

मिजोरम सरकार ने एचपीसी-डी शांति समझौते के कार्यान्वयन पर समीक्षा बैठक आयोजित की

एजल। अधिकारियों ने बताया कि मिजोरम सरकार ने मंगलवार को राज्य सरकार के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के तहत हमार पीपुल्स कन्वेंशन (डेमोक्रेटिक) के लालमिंगथांगा सनाते के नेतृत्व वाले गुट द्वारा उठाई गई मांगों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, जिसमें हमार-आबादी वाले क्षेत्रों में विकास कार्यों में तेजी लाने पर जोर दिया गया। मिजोरम के गृह मंत्री के सपडांगा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री के सलाहकार (राजनीतिक) लालमुआनपुइया पुंटे, गृह सचिव, गृह विभाग के अधिकारी और सीआईडी (विशेष शाखा) के कर्मियों सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। अधिकारियों ने कहा कि चर्चा में हमार पीपुल्स कन्वेंशन (डेमोक्रेटिक) द्वारा प्रस्तुत मांगों के चार्टर में शामिल विभिन्न प्रावधानों पर ध्यान केंद्रित किया गया । उन्होंने आगे कहा कि आत्मसमर्पण करने वाले कैडरों के पुनर्वास उपायों के अलावा, चार्टर में उत्तरी और उत्तरपूर्वी मिजोरम के हमार-बहुसंख्यक क्षेत्रों के लिए कई विकास पहलों का भी प्रस्ताव किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि इन प्रस्तावों में सड़क संपर्क को मजबूत करना, शैक्षणिक संस्थानों और अतिरिक्त सरकारी कार्यालयों की स्थापना करना, किसानों और भूमि आधारित आजीविका के लिए सहायता प्रदान करना और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना शामिल था। उन्होंने आगे कहा कि कई मांगों के लिए कई सरकारी विभागों के बीच समन्वय की आवश्यकता है। यह निर्णय लिया गया कि संबंधित विभागों को इन मुद्दों पर तत्काल कार्रवाई करने और समय पर अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि विभागों से आगे की समीक्षा के लिए समय-समय पर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा जाएगा। इससे पहले, 14 अप्रैल को, मिजोरम सरकार ने सनाते के नेतृत्व वाले हमार पीपुल्स कन्वेंशन (डेमोक्रेटिक) गुट के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जो पूर्वोत्तर राज्य में बचा हुआ अंतिम विद्रोही समूह था। इसके बाद, 30 अप्रैल को आइजोल के पास सेसावंग में आयोजित एक घर वापसी समारोह के दौरान सनाते सहित 43 कार्यकर्ताओं ने हथियार डाल दिए।

जुबीन गर्ग की स्मृति में 10 बीघा भूमि पर बनेगा भव्य *जुबीन क्षेत्र* : मुख्यमंत्री

गुवाहाटी (हिंस)। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने बुधवार को नई दिल्ली से सीधे *जुबीन क्षेत्र* पहुंचकर असम के लोकप्रिय गायक जुबीन गर्ग की स्मृति में 10 बीघा भूमि पर एक भव्य और सर्वांग सुंदर सांस्कृतिक स्मारक निर्माण की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने जुबीन गर्ग की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि राज्य सरकार कलाकार की वास्तविक पहचान, विरासत और सांस्कृतिक योगदान के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जुबीन गर्ग केवल एक कलाकार नहीं, बल्कि असम की भावनाओं और सांस्कृतिक चेतना के प्रतीक हैं। डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने बताया कि विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने जनता से वादा किया था कि आशीर्वाद मिलने के बाद सरकार *जुबीन क्षेत्र* परियोजना को आगे बढ़ाएगी। उसी प्रतिबद्धता को निभाने के लिए उन्होंने चुनाव समाप्त होने के बाद स्थल का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि भाजपा ने कभी भी जुबीन गर्ग के नाम पर राजनीति नहीं करने का निर्णय लिया था। इसी कारण चुनाव से पहले उन्होंने *जुबीन क्षेत्र* का दौरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि कुछ विपक्षी दलों द्वारा जुबीन गर्ग को लेकर राजनीति किए जाने से भाजपा को

जनता का अतिरिक्त समर्थन मिला। उन्होंने कहा कि राजनीति से ऊपर उठकर जुबीन गर्ग की असली पहचान और सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखना समय की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि लोक निर्माण विभाग द्वारा लगभग तीन करोड़ की लागत से चारदीवारी निर्माण का प्रारंभिक कार्य शुरू किया जा चुका है। साथ ही ऊपरी हिस्से से मिट्टी खिसकने से रोकने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपाय भी किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि सरकार *जुबीन क्षेत्र* को एक गरिमामय, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्थल के रूप में विकसित करने के लिए संकल्पबद्ध है।

कछार में पुलिस का अभियान, महिला समेत तीन बांग्लादेशी हिरासत में

कछार (हिंस)। असम के कछार जिले के काटीगोरा के गुमरा क्षेत्र में पुलिस द्वारा चलाए गए एक अभियान में एक महिला समेत तीन बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार बीती रात हिरासत में लिए गए लोगों की पहचान मोहम्मद आवाल, मोहम्मद हारुण और रीना अख्तर के रूप में हुई है। गुमरा पुलिस ने विशेष सूचना के आधार पर यह अभियान चलाया। पुलिस ने बताया कि तीनों से पूछताछ की जा रही है तथा आवश्यक कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। साथ ही यह पता लगाने के लिए विस्तृत जांच शुरू की गई है कि वे राज्य में कैसे प्रवेश किए और क्या उनके पीछे किसी स्थानीय नेटवर्क की भूमिका है।

गुवाहाटी में मानव तस्करी का बड़ा खुलासा

प्रेमजाल में फंसाकर युवती को बिहार व राजस्थान ले जाकर बेचा

गुवाहाटी (हिंस)। गुवाहाटी के गड़चुक इलाके से मानव तस्करी का एक बेहद चिंताजनक मामला सामने आया है। आरोप है कि एक युवती को प्रेमजाल में फंसाकर पहले उसका अपहरण किया गया और बाद में उसे राज्य के बाहर ले जाकर बेच दिया गया। इस घटना ने असम में महिलाओं और युवतियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार, तस्कर गिरोह युवती को पहले बिहार ले गया, जहां उसे कुछ दिनों तक एक वेश्यालय में रखा गया। इसके बाद युवती को राजस्थान में बेच दिया गया। जांच के दौरान पुलिस ने युवती को तस्करों के चंगुल से सुरक्षित बरामद कर लिया और एक महिला सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया गया है कि नाबालिग लड़की को गुवाहाटी के काटाबाड़ी इलाके से प्रेम संबंध का झांसा देकर ले जाया गया था। पीड़िता की मां द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कामरूप जिले के छयगांव से मुख्य आरोपी अबू बक्कर सिद्दीक को गिरफ्तार किया। इसके अलावा बिहार से अंकित कुमार और काजली कुमार को भी हिरासत में लिया गया है। जांच में सामने आया है कि मानव तस्करी से जुड़े गिरोह युवतियों को प्रेम, शादी और बेहतर जीवन का सपना दिखाकर अपने जाल में फंसा रहे हैं। पुलिस को आशंका है कि गिरफ्तार आरोपी किसी बड़े अंतरराज्यीय मानव तस्करी नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं। मामले की गहन जांच जारी है और अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।

बोड़ोलैंड विश्वविद्यालय में दहेज प्रथा के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

कोकराझाड़ (विभास)। बोड़ोलैंड विश्वविद्यालय के परिसर में सामाजिक बुराई *दहेज प्रथा* के खिलाफ एक भव्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान छात्र-छात्राओं ने विभिन्न गतिविधियों, प्रदर्शनों, नुक्कड़ नाटक और एक रैली के माध्यम से समाज को जागरूक करने का प्रयास किया। कार्यक्रम की शुरुआत एक विशेष वीडियो स्क्रीनिंग के साथ हुई, जिसमें दहेज प्रथा के नकारात्मक प्रभावों और लैंगिक संवेदीकरण के महत्व को प्रमुखता से दिखाया गया। इसके बाद राजनीति विज्ञान विभाग के छात्रों ने एक मर्मस्पर्शी प्रदर्शन और *नुक्कड़ नाटक* की प्रस्तुति दी। इस नाटक के जरिए छात्रों ने दहेज के कारण महिलाओं और उनके परिवारों को झेलने वाली प्रताड़ना, घरेलू हिंसा,

सामाजिक दबाव और मानसिक पीड़ा की कड़वी सच्चाई को मंच पर जीवंत किया। नाटक का मुख्य उद्देश्य समाज से इस कुप्रथा को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए लोगों को जागरूक करना था। नाटक और प्रस्तुतियों के बाद कार्यक्रम में मौजूद सभी छात्रों और प्रतिभागियों ने दहेज के खिलाफ एक सामूहिक शपथ ली। सभी ने संकल्प लिया कि वे भविष्य में न तो कभी दहेज की मांग करेंगे, न इसे स्वीकार करेंगे और समाज में इस प्रथा के खिलाफ हमेशा मजबूती से खड़े रहेंगे। कार्यक्रम के अगले चरण में विश्वविद्यालय परिसर में एक विशाल जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में शामिल छात्र अपने हाथों में बैनर, प्लेकार्ड और पोस्टर लिए हुए थे, जिन पर *दहेज को ना कहें, हर महिला को सम्मान से जीने का अधिकार है* और *उसे दहेज की आग से मुक्त करो* जैसे सशक्त नारे लिखे थे। विश्वविद्यालय प्रशासन और आयोजकों के अनुसार, इस कार्यक्रम का समापन शिक्षा, जागरूकता और सामूहिक जिम्मेदारी के संदेश के साथ हुआ। वक्ताओं ने जोर देकर कहा कि दहेज जैसी सामाजिक बुराई से लड़ने के लिए युवाओं का आगे आना और समाज के हर वर्ग का एकजुट होना बेहद जरूरी है।

त्रिपुरा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास एक ट्रक पलटने से चार मजदूरों की मौत, छह घायल

अगरतला। त्रिपुरा के धलाई जिले के लोंगतराई घाटी उपमंडल में भारत-बांग्लादेश सीमा के पास एक दुखद सड़क दुर्घटना में रविवार शाम को पत्थर के टुकड़ों से लदे एक ट्रक के पलट जाने से चार मजदूरों की मौत हो गई और छह अन्य घायल हो गए। यह दुर्घटना उस समय हुई जब ट्रक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास चल रहे अवसंरचना विकास कार्य के लिए पत्थर के टुकड़े ले जा रहा था और चावमानु से बीजू सीमा चौकी की ओर जा रहा था। लोंगतराई घाटी के उप-मंडल पुलिस अधिकारी, सोनाचरण जमातिया के अनुसार, यह घटना सड़क के एक खड़ी और बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हिस्से पर हुई, जहां ट्रक को चढ़ने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। वाहन पहाड़ी पर चढ़ने में असमर्थ रहा और पीछे की ओर जाते समय पलट गया। परिणामस्वरूप, पत्थर के टुकड़ों से लदे चार मजदूर सड़क पर गिर गए और बाद में जब टुकड़े उन पर गिरे तो वे भारी भार के नीचे दब गए। जमातिया ने कहा कि वाहन के ऊपर बैठे चारों मजदूर पत्थर के टुकड़ों के नीचे दबकर मौके पर ही मर गए, जबकि केबिन के अंदर मौजूद लोग बच गए। मृतकों की पहचान बलिधनजॉय त्रिपुरा (47), मजीदा त्रिपुरा (50), बाथोजॉय त्रिपुरा (39), नरजॉय त्रिपुरा (36) के रूप में हुई है। छह अन्य लोग घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। दुर्घटना के समय घायल हुए अधिकांश लोग ट्रक के केबिन के अंदर यात्रा कर रहे थे। घटना के तुरंत बाद, पास के सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) चौकियों के जवान मौके पर पहुंचे और बचाव अभियान शुरू किया। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने चार मजदूरों को मृत घोषित कर दिया। मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है।

मोटोहॉस ने गुवाहाटी में भव्य लांच के साथ नॉर्थईस्ट में किया अपनी मौजूदगी का विस्तार

गुवाहाटी। मोटोहॉस इंडिया ने आरके स्पैक्ट्रम के साथ साझेदारी में गुवाहाटी शोरूम के भव्य लांच के साथ उत्तर-पूर्वी (नॉर्थईस्ट) भारत में अपने फुटप्रिन्ट का आधिकारिक विस्तार कर लिया है। इस लांच के साथ प्रीमियम युरोपियन मोबिलिटी ब्राण्ड्स- ब्रिक्सटन मोटरसाइकल्स और वीएलएफ स्कूटर अब क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण और तेजी से विकसित होते ऑटोमोटिव मार्केट्स में सुलभ हो गए हैं। डीलर प्रिंसिपल राजेश कलिता के नेतृत्व में यह नई डीलरशिप मोटोहॉस इंडिया की विस्तार योजनाओं में एक और बड़ी उपलब्धि है, जिसके तहत ब्रांड ने देश के मुख्य महानगरों और उभरते मार्केट्स में विस्तार की योजनाएं बनाई हैं। गुवाहाटी के लालमती में स्थित यह नया शोरूम उत्तरपूर्वी भारत में प्रीमियम मोटरसाइकल प्रशंसकों, लाइफस्टाइल राइडरों एवं शहरी मोबिलिटी अडॉप्टर्स की बढ़ती संख्या को ब्रांड की ओर से अधिक विजिबिलिटी और सुलभता प्रदान करेगा। नोर्थईस्ट के गेटवे के रूप में गुवाहाटी में मोटोहॉस इंडिया के विस्तारित होते पोर्टफोलियो के लिए ढेरों संभावनाएं हैं। गौरतलब है कि इस पोर्टफोलियो में प्रीमियम मोटरसाइकलें और नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी समाधान शामिल हैं। यह भारत में कंपनी का 15वां शोरूम है और मोटोहॉस इंडिया ने 2026 के अंत तक देश भर में 15 और शोरूम खोलने की योजना बनाई है । गुवाहाटी में

मोटोहॉस के नए शोरूम में प्रीमियम मोटरसाइकलों और स्कूटरों के क्यूरेटेड पोर्टफोलियो को पेश किया गया है। ये वाहन खासतौर पर उन प्रशंसकों के लिए डिजाइन किए गए हैं जो खास स्टाइलिंग, परफोर्मेन्स एवं मोबिलिटी के आधुनिक समाधानों की उम्मीद रखते हैं। लांच के अवसर पर प्रेस, मीडिया के सदस्य, ऑटोमोटिव पत्रकार, क्रिएटर, उद्योग जगत के पेशेवर और मोटरसाइकल प्रशंसक मौजूद रहे, जिन्होंने मोटोहॉस इंडिया की विस्तृत होती प्रोडक्ट रेंज तथा उत्तर-पूर्वी भारत में ब्रांड के दीर्घकालिक विजन को देखने का अवसर मिला।

अरुणाचल प्रदेश : वैज्ञानिकों ने सेला दर्रे के पास दुर्लभ हिमालयी पौधे *जियम मैक्रोसेपलम* की पुनः खोज की

इटानगर। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि अरुणाचल प्रदेश के अल्पाइन क्षेत्र में दुर्लभ पुष्पीय पौधे की प्रजाति *ज्यूम मैक्रोसेपलम* को फिर से खोजा गया है, जो लगभग 120 वर्षों में भारत में इसका पहला दर्ज अवलोकन है। पूर्वी हिमालय में पाई जाने वाली और *संकटग्रस्त* श्रेणी में वर्गीकृत इस प्रजाति को भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (बीएसआई) के शोधकर्ताओं ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सेला दर्रे के पास उच्च ऊंचाई वाले अल्पाइन घास के मैदानों के व्यापक सर्वेक्षण के दौरान फिर से खोजा है। अधिकारियों ने बताया कि यह पुनर्खोज पश्चिमी अरुणाचल प्रदेश के अल्पाइन और सबअल्पाइन क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के वनस्पति विविधता पर प्रभाव और संवहनी पौधों की आवाजाही की जांच करने वाली एक परियोजना के तहत किए गए क्षेत्र अध्ययन के दौरान हुई। शोध दल में वनस्पति विज्ञानी सुभाजित लाहिड़ी, मोनालिसा दास और सुधांशु शेखर डैश शामिल थे, जिन्होंने तवांग और पश्चिम कामेंग जिलों के बीच सेला क्षेत्र में लगभग 4,200 मीटर की

ऊंचाई पर इस प्रजाति की पहचान की। इन निष्कर्षों को अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पत्रिका फाइटोटैक्सा में प्रकाशित किया गया है, जिसमें इस पुनर्खोज को पूर्वी हिमालय के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को समझने में एक महत्वपूर्ण योगदान बताया गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार, भारत में इस पौधे का अंतिम विश्वसनीय दस्तावेजीकरण 1905 में सिक्किम से हुआ था, जिसके बाद से केवल सीमित ऐतिहासिक रिकॉर्ड ही उपलब्ध हैं। गुलाब परिवार से संबंधित, जियोम मैक्रोसेपलम अपने हल्के पीले से हाथीदांत-पीले रंग के फूलों के लिए जाना जाता है जिनमें लाल रंग की झलक होती है और लटकते हुए फूल होते हैं, जो कि अत्यधिक अल्पाइन परिस्थितियों के अनुकूलन का परिणाम है। शोधकर्ताओं ने भारतीय हिमालय के सबसे कम खोजे गए क्षेत्रों में से एक में अल्पाइन घास के मैदानों और दलदली क्षेत्रों में इस प्रजाति को उगते हुए पाया। प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ के मानदंडों के आधार पर, भारत में इस प्रजाति को *कमजोर* श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि इसका वितरण क्षेत्र सीमित है और नाजुक पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्रों में विकासात्मक गतिविधियों और पारिस्थितिक गड़बड़ी से बढ़ते खतरे हैं। इस अध्ययन में शामिल वैज्ञानिकों ने इस बात पर जोर दिया कि इस पुनर्खोज से अरुणाचल प्रदेश में मजबूत वनस्पति अनुसंधान और दीर्घकालिक संरक्षण प्रयासों की आवश्यकता उजागर होती है, जो विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट का हिस्सा है। यह क्षेत्र वनस्पतियों और जीवों की समृद्ध विविधता के लिए जाना जाता है, जिसमें कई स्थानिक और दुर्लभ प्रजातियां शामिल हैं, जिनमें से कई दुर्गम भूभाग और सीमित वैज्ञानिक अन्वेषण के कारण अभी तक दर्ज नहीं की गई हैं। इस पुनर्खोज ने संरक्षणवादियों, शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं का ध्यान आकर्षित किया है, और उपमुख्यमंत्री चोवना मीन ने इसे राज्य की असाधारण पारिस्थितिक समृद्धि की याद दिलाने वाला बताया है। सोमवार को एक्स पर एक पोस्ट में, मीन ने कहा कि पूर्वी हिमालय के एक भूले हुए खजाने की पुनः खोज। दुर्लभ जियोम मैक्रोसेपलम, जो लगभग 120 वर्षों से भारत में नहीं देखा गया था, अरुणाचल प्रदेश के अल्पाइन परिदृश्यों में फिर से पाया गया है, जो इस क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता और पारिस्थितिक महत्व को उजागर करता है। हाल के वर्षों में, अरुणाचल प्रदेश वानस्पतिक खोजों और पुनर्खोजों के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा है, जिसमें कई नई और दुर्लभ पौधों की प्रजातियों-जिनमें ऑर्किड, बेगोनिया और अल्पाइन जड़ी-बूटियां शामिल हैं-को इसके दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों से पहचाना गया है।

संपादकीय

'रुपए' से ढहती आर्थिकी

भारत मे एक डॉलर की कीमत 96.35 रुपए तक पहुंच चुकी है। यह घट-बढ़ भी सकती है, लेकिन व्यापक परिवर्तन संभव नहीं हैं। यह भारतीय मुद्रा 'रुपए' का सबसे निचले स्तर का अवमूल्यन है। रुपए और डॉलर के इस समीकरण के बाद विश्व में सबसे कमजोर मुद्रा 'रुपया' ही है। यह बेहद चिंताजनक स्थिति है, बेशक भारत विश्व की एक बड़ी अर्थव्यवस्था है। नतीजा यह है कि हमने मार्च, 2026 में जो कच्चा तेल 1.17 लाख करोड़ रुपए में खरीदा था, वही अप्रैल में 1.79 लाख करोड़ रुपए में खरीदना पड़ा है। कच्चे तेल के अलावा, गैस, खाद, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, खाद्य तेल, दालें, सोना और अन्य आयातित वस्तुएं, सेवाएं हमें महंगी खरीदनी पड़ेंगी। अंततः महंगाई बढ़ती जाएगी और आम आदमी कराहता रहेगा। सिर्फ एक ही बुनियादी कारण है-रुपए का अवमूल्यन। यह स्थिति मोदी सरकार के 12 सालों में लगातार खराब होती गई है। हालांकि 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपए के कृत्रिम नियंत्रण की कोशिश की थी, लेकिन आज अवमूल्यन का यथार्थ सामने है। लिहाजा 'मूडीज' की ताजा रपट भी चर्चा में है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी ने निष्कर्ष दिया है कि भारत के जीडीपी की विकास दर 0.8 फीसदी कम हो गई है। वित्त वर्ष के अंत में विकास दर करीब 6 फीसदी ही रहने वाली है। सरकार 7-7.5 फीसदी की विकास दर का दावा करती रही है। रिजर्व बैंक ने भी 6.5 फीसदी तक का आकलन देना शुरू कर दिया है। एक आर्थिक वज्रपात यह भी हुआ है कि 2026 के पहले पांच महीनों में ही विदेशी निवेशकों ने 2.2 लाख करोड़ रुपए के शेयर बेच दिए हैं और भारतीय बाजार को अलविदा कह दिया है। हालांकि कुछ नई और छोटी कंपनियों में विदेशियों के निवेश अब भी मौजूद हैं, लेकिन वे अर्थव्यवस्था को अपेक्षित प्रभावित नहीं करते। ऐसे निवेशकों ने जापान, दक्षिण कोरिया और अमरीका की कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की कंपनियों में निवेश करना बेहतर समझा है। अप्रैल में 60,900 करोड़ रुपए और मई में अभी तक 1.22 लाख करोड़ रुपए विदेशी निवेशक हमारे बाजार से निकाल चुके हैं। नतीजतन भारत को विदेशी मुद्रा का भी नुकसान झेलना पड़ेगा। जो आर्थिक उथल-पुथल हम देख रहे हैं, वह पूर्णतः ईरान युद्ध के नतीजतन नहीं है। युद्ध ने तेल, गैस, खाद समेत विश्व की बुनियादी सप्लाई चेन को तोड़ कर रख दिया है। इसी दौरान भारत-संयुक्त अरब अमीरात में समझौता हुआ है कि अरब देश हमारे यहां 5 अरब डॉलर का निवेश करेगा और 3 करोड़ बैरल कच्चे तेल का भंडारण तैयार करेगा, जिसका इस्तेमाल भारत भी आपातस्थिति में कर सकेगा। इसमें समय लगेगा, क्योंकि अभी खुद अरब देश ईरान के मिसाइल-ड्रोन हमले झेलने को विवश है। बहरहाल भारत के संदर्भ में 'रुपए' का अवमूल्यन बहुत बड़ा प्रभाव है, क्योंकि भारत 147 करोड़ से अधिक की आबादी और घोर आर्थिक, सामाजिक असमानताओं का देश है, लिहाजा यह तेल-गैस का ही नहीं, बल्कि आम भारतीय की आजीविका का भी 'आपातकाल' है। भारतीय अर्थव्यवस्था में चालू खाता घाटा वित्त वर्ष 2026-27 में जीडीपी के 2.3 फीसदी तक पहुंच सकता है, जबकि बीते 2025-26 में यह 0.9 फीसदी बताया जा रहा है। यह संकट प्रधानमंत्री मोदी की अपील, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों के मेट्रो में सफर करने या ई-रिक्शा, विद्युत बस में दफ्तर जाने अथवा पैदल चलने और अंततः बचत करने से ही दूर नहीं होगा। यदि 'रुपए' के अवमूल्यन से भारत चौथी अर्थव्यवस्था से फिसल कर छठी अर्थव्यवस्था पर आ सकता है, तो 7-8वां स्थान बहुत दूर नहीं है। फ्रांस जैसे विकसित देश की चुनौती सामने है। अर्थशास्त्रियों का सवाल है कि हम डॉलर में तेल क्यों खरीद रहे हैं? यदि सरकार के पास पैसा है, तो सबसिडी दे दें और तेल-गैस सस्ते में बेचें। बहरहाल यह भी विचार हो सकता है, लेकिन एक और आयाम सामने आया है। भारत में रेलवे, रक्षा, पोर्ट ट्रस्ट, सार्वजनिक उपक्रमों के पास 20-25 हजार वर्ग किलोमीटर जमीनें हैं। उन्हें आंशिक तौर पर बेचा या दीर्घकालिक लीज पर दिया जा सकता है। जमीन का यथोचित हिस्सा सुरक्षा और आपातस्थिति के लिए छोडने के बाद भी करीब 16-17 लाख करोड़ रुपए आ सकते हैं।

रुपए और डॉलर के इस समीकरण के बाद विश्व में सबसे कमजोर मुद्रा 'रुपया' ही है। यह बेहद चिंताजनक स्थिति है, बेशक भारत विश्व की एक बड़ी अर्थव्यवस्था है। नतीजा यह है कि हमने मार्च, 2026 में जो कच्चा तेल 1.17 लाख करोड़ रुपए में खरीदा था, वही अप्रैल में 1.79 लाख करोड़ रुपए में खरीदना पड़ा है। कच्चे तेल के अलावा, गैस, खाद, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, खाद्य तेल, दालें, सोना और अन्य आयातित वस्तुएं, सेवाएं हमें महंगी खरीदनी पड़ेंगी। अंततः महंगाई बढ़ती जाएगी और आम आदमी कराहता रहेगा। सिर्फ एक ही बुनियादी कारण है-रुपए का अवमूल्यन। यह स्थिति मोदी सरकार के 12 सालों में लगातार खराब होती गई है। हालांकि 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपए के कृत्रिम नियंत्रण की कोशिश की थी, लेकिन आज अवमूल्यन का यथार्थ सामने है। लिहाजा 'मूडीज' की ताजा रपट भी चर्चा में है, जिसमें अंतराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी ने निष्कर्ष दिया है कि भारत के जीडीपी की विकास दर 0.8 फीसदी कम हो गई है। वित्त वर्ष के अंत में विकास दर करीब 6 फीसदी ही रहने वाली है।

पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बढ़त के लिए ममता को खुलेआम जिम्मेदार ठहराना एक तरह से तृणमूल की ताबूत का कील ही साबित हुआ

फिर कैसे मिले सुर मेरा-तुम्हारा

उमेश चतुर्वेदी

बंगाल की शेरनी कही जाने वाली ममता बनर्जी की हार ने विपक्षी खेमे के उन दलों के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई हैं, जो इन चुनावों से बेपरवाह थे। केरल की गठबंधन सरकार में वापसी की वजह से कांग्रेस थोड़ी राहत में भले ही हो, लेकिन ज्यादातर क्षेत्रीय दलों को अपने अस्तित्व पर खतरा नजर आने लगा है। तमिलनाडु में सत्ता की चाहत में विपक्षी गठबंधन टूट भी चुका है। कांग्रेस के हाथ ने डीएमके का बरसों पुराना साथ छोड़ नवेली टीवीके का दामन थाम लिया है। दूसरी तरफ धांधली का आरोप लगाने के साथ ही ममता बनर्जी को विपक्षी एकता, खासकर इंडिया ब्लॉक की याद आने लगी है। अब उन्हें विपक्षी एकता मजबूत करने की याद भी आने लगी है। दिलचस्प यह है कि अतीत में इंडिया ब्लॉक की एकता से बेपरवाह रहीं ममता को अब उसी की बहुत याद आने लगी है। वैसे विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस की ओर से भी कम गलतियां नहीं हुई हैं।

विधानसभा चुनावों में बड़े विपक्षी चेहरों की बड़ी नाकामी से विपक्षी खेमे में खलबली मच गई है। बंगाल की शेरनी कही जाने वाली ममता बनर्जी की हार ने विपक्षी खेमे के उन दलों के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई हैं, जो इन चुनावों से बेपरवाह थे। केरल की गठबंधन सरकार में वापसी की वजह से कांग्रेस थोड़ी राहत में भले ही हो, लेकिन ज्यादातर क्षेत्रीय दलों को अपने अस्तित्व पर खतरा नजर आने लगा है। तमिलनाडु में सत्ता की चाहत में विपक्षी गठबंधन टूट भी चुका है। कांग्रेस के हाथ ने डीएमके का बरसों पुराना साथ छोड़ नवेली टीवीके का दामन थाम लिया है। दूसरी तरफ धांधली का आरोप लगाने के साथ ही ममता बनर्जी को विपक्षी एकता, खासकर इंडिया ब्लॉक की याद आने लगी है। अब उन्हें विपक्षी एकता मजबूत करने की याद भी आने लगी है। दिलचस्प यह है कि अतीत में इंडिया ब्लॉक की एकता से बेपरवाह रहीं ममता को अब उसी की बहुत याद आने लगी है। वैसे विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस की ओर से भी कम गलतियां नहीं हुई हैं। राहुल गांधी का पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बढ़त के लिए ममता को खुलेआम जिम्मेदार ठहराना एक तरह से तृणमूल की ताबूत का कील ही साबित हुआ। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि विपक्षी एकता का विचार फिर से परवान चढ़ सकता है ? अतीत में एकता को लेकर जिस तरह विपक्षी खेमे में एक-दूसरे को शह और मात देने का खेल चला है, उससे क्या मुकम्मल एकता की उम्मीद बचती है ? 2024 के आम चुनावों के पहले विपक्षी राजनीति को एक मंच पर लाने और भाजपा विरोधी मोर्चा बनाने की कोशिश तो हुई, लेकिन आपसी टकराव और वर्चस्व के चलते यह हकीकत नहीं बन पाया। 23 जून 2023 को पटना में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुआई में विपक्षी क्षत्रपों की बैठक में इंडिया ब्लॉक बनाने का फैसला तो हुआ,लेकिन नेतृत्व के मुद्दे पर एक राय नहीं बन पाई। नीतीश कुमार ने खुलकर भले ही कभी नहीं कहा, लेकिन उनकी चाहत थी कि विपक्षी गठबंधन का संयोजक उन्हें बनाया जाय। लेकिन कांग्रेसी आलाकमान की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। दरअसल कांग्रेस विपक्षी राजनीति की लगाम खुद के हाथ में ही रखना चाहती है। नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और एमके स्टालिन का साथ तो उसे चाहिए, लेकिन इनमें से किसी का भी नेतृत्व उसे गवारा नहीं। अपने पहले परिवार की पूरी स्वीकार्यता भले ही ना हो, लेकिन अगुआई कांग्रेस को ही चाहिए। यही वजह है कि विपक्षी राजनीति के सबसे ज्यादा स्वीकार्य चेहरा रहे नीतीश कुमार ने निराशा में उसी मोदी का हाथ थाम लिया, जिनसे वे दूर हो चुके थे। इसके बाद का इतिहास सबको पता है। ममता को राजनीति में पहला बड़ा ब्रेक बेशक राजीव गांधी ने दिया, लेकिन वामपंथियों के साथ राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेसी सहयोग ने उन्हें बाद के दिनों में गांधी-नेहरू परिवार से दूर कर दिया। हालिया हार के

बावजूद अपनी संघर्षशीलता के चलते ममता विपक्षी राजनीति का अब भी बड़ा चेहरा हैं। उनकी अपनी छवि अक्सर राहुल गांधी पर भी भारी पड़ती है। इंडिया ब्लॉक के विचार के वक्त पूर्व कांग्रेसी होने के नाते ममता को पता था कि कांग्रेस अपने हाथ में नेतृत्व बनाए रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी, इसीलिए उन्होंने ही नीतीश कुमार और लालू यादव को पहली बैठक पटना में कराने का सुझाव दिया था। बाद के दिनों में कांग्रेस ने जैसी चाल चली, उससे विपक्षी एकता का राग बेसुरा हो गया। जिसका नतीजा लोकसभा चुनाव नतीजों में दिखा भी। विपक्ष को उसी वक्त चेतना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। असर यह हुआ कि हरियाणा, महाराष्ट्र और बिहार के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मार ली। बाकी कसर बीते विधानसभा चुनावों ने पूरी कर दी है। गौर करने की बात है कि जब भी सत्ता पक्ष के उफान में विपक्ष बह जाता है, उसकी एकता की छटपटाहट बढ़ जाती है। ज्यादातर यह अस्तित्व संकट टालने का यह फौरी उपाय होता है। तब वह हार के बाद वोटों के गुणा-गणित में जुट जाता है। फिर उसे इलहाम होता है कि अगर वह एक रहता तो वह भारी पड़ता। 1962 के आम चुनावों में नेहरू को फूलपुर की सीट पर सीधी चुनौती में हार मिलने के बाद लोहिया को भी कुछ ऐसा ही लगा। तब भारी उत्सुकता और उत्साह के बावजूद लोहिया हार गए थे। इसके बाद उन्होंने गैर कांग्रेसवाद का विचार दिया। तब कांग्रेस को 44 प्रतिशत से कुछ ज्यादा वोट मिले थे। लोहिया को लगा कि विरोध में पड़े 56 प्रतिशत वोटों को अगर एक किया जाता तो नतीजे कुछ और होते। गैर कांग्रेसवाद के बैनर के तले उन्होंने 1963 के उपचुनावों और 1967 के आम चुनावों में इसे आजमाया। इसका असर यह हुआ कि आठ राज्यों से कांग्रेस की विदाई हो गई। तब से सत्ता में आने वाली पार्टी के खिलाफ बाकी विपक्ष की एकता के सुर उठने की परंपरा बन गई है। कभी यह कांग्रेस के खिलाफ होता था, जिसमें वामपंथियों और जनसंघ- बीजेपी भी शामिल रहते थे, अब यह भाजपा के खिलाफ हो रहा है। प. बगाल के बीते विधानसभा चुनाव में ममता को जहां करीब 42 प्रतिशत वोट मिला है, वहीं बीजेपी को करीब 46 प्रतिशत। कांग्रेस को 2.97 और वामपंथियों को 4.45 प्रतिशत वोट मिले हैं। गैर बीजेपी वोटों को मिला दें तो यह आंकड़ा 49 प्रतिशत से ज्यादा हो जाता है। चुनावी राजनीति में सात प्रतिशत का अंतर बड़ा होता है। अब विपक्षी खेमे को लग रहा है कि अगर वे एक होते तो बीजेपी को ऐसी जीत नहीं मिलती। वैसे चुनावी गणित सामान्य गणित की तरह नहीं होता। 2018 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस से बीजेपी को पांच लाख से ज्यादा वोट मिले थे, लेकिन सीटों के मामले में वह पिछड़ गई थी। चुनावी मैदान में जब सिर्फ दो खेमे होते हैं, तब मतदाताओं के बीच लंबवत ध्रुवीकरण हो जाता है। तब बिखराव वाले आंकड़े भी बदल जाते हैं। 2014 के संसदीय चुनाव में उत्तर प्रदेश में ऐसा साफ दिखा, जब बीजेपी सब पर भारी रही। संसदीय चुनाव में सफलता के लिहाज से देखें तो कांग्रेस को 99 सीटों के बाद 37 सीटों के साथ समाजवादी पार्टी विपक्ष का दूसरा बड़ा दल है। तीसरे नंबर पर 29 सीटों के साथ ममता ही हैं। इंडिया ब्लॉक की पहली बैठक के पीछे ममता का ही विचार था, फिर भी ना तो लोकसभा और ना ही विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस या ब्लॉक के दूसरे दलों को तवज्जो दिया। तमिलनाडु में डीएमके के साथ कांग्रेस की खींचतान जारी रही। विपक्ष के किसी भी दल ने एकता की कीमत पर त्याग स्वीकार नहीं किया। विपक्षी खेमे का संकट यह है कि वह अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में सहयोगियों से हिस्सेदारी बांटना ही नहीं चाहता। मजबूत एकता के लिए विपक्ष के पास राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य साफ छवि वाला चेहरा होना जरूरी है। लेकिन विपक्ष के पास ऐसा चेहरा है भी नहीं। ममता बड़ी नेता तो हैं, लेकिन उनकी तुनकमिजाजी उन्हें सर्वमान्य चेहरा मानने के राह की बड़ी बाधा है। राहुल मोदी-शाह की जोड़ी को चाहे जिस अंदाज में चुनौती दें, मोदी विरोधी बौद्धिकों को उनका यह अंदाज चाहे जितना भी पसंद हो, लेकिन आमजन को उनमें कई बार बचकानापन नजर आता है तो कई मर्तबा प्रहसन। स्टालिन चाहे जितनी अच्छी तमिल बोलें, लेकिन राष्ट्रीय स्तर स्वीकार्यता के लिए वे अयोग्य हैं। इसी तरह केजरीवाल के पास बड़ा आधार नहीं है। रही बात अखिलेश यादव की तो, वे भी जमीनी राजनीति के बजाय बयानों के गुब्बारे उड़ाने के उस्ताद होते गए हैं। आपसी अहं के टकराव के चलते नीतीश विपक्षी खेमा छोड़ चुके हैं। दूसरी बड़ी नेता ममता को चुनावी मैदान में करारी शिकस्त मिल गई है। अखिलेश को भी अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा के सियासी मैदान में बीजेपी से दो-दो हाथ करना है। बीजेपी की कोशिश उन्हें तीसरी बार शिकस्त देने की होगी। अगर वह ऐसा करने में कामयाब रही तो उसके सामने दूर-दूर तक कोई चुनौती नहीं होगी। ऐसे में विपक्षी खेमे का संकट बड़ा है। अतीत के विपक्षी व्यवहार से नहीं लगता कि शायद ही भविष्य में कोई मजबूत मोर्चा बन सके। खुलकर विपक्षी खेमा भले ही ना कहे, लेकिन अंदर ही अंदर वह जरूर गुनगुना रहा है।

समय | बोध

भारत नॉर्डिक समिट से वैश्विक साझेदारी के नए युग की शुरुआत

नरेंद्र मोदी की नॉर्वे यात्रा और तीसरे भारत-नॉर्डिक समिट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत अब केवल दक्षिण एशिया की शक्ति नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति अर्थव्यवस्था और तकनीकी सहयोग का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है। नॉर्वे डेनमार्क फिनलैंड आइसलैंड और स्वीडन जैसे विकसित तथा तकनीकी रूप से अग्रणी देशों के साथ भारत की बढ़ती निकटता आने वाले समय में विश्व राजनीति और वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे सकती है। यह समिट केवल औपचारिक बैठक नहीं थी बल्कि बदलती विश्व व्यवस्था में समान विचारधारा वाले लोकतांत्रिक देशों के बीच रणनीतिक सहयोग का मजबूत संकेत भी था। भारत और नॉर्डिक देशों के संबंध पिछले कुछ वर्षों में तेजी से मजबूत हुए हैं। इन देशों की पहचान स्वच्छ ऊर्जा आधुनिक तकनीक मानव विकास नवाचार और सामाजिक कल्याण के मॉडल के रूप में होती है। दूसरी ओर भारत विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्ति तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था विशाल बाजार और युवा जनसंख्या वाला देश है। ऐसे में दोनों पक्षों के हित एक दूसरे के पूरक बनते दिखाई देते हैं। यही कारण है कि इस समिट में व्यापार डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कृत्रिम बुद्धिमत्ता अंतरिक्ष विज्ञान ब्लू इकॉनमी और क्लीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में व्यापक सहयोग पर सहमति बनी। प्रधानमंत्री मोदी ने समिट के दौरान लोकतंत्र कानून के शासन और बहुपक्षवाद को भारत और नॉर्डिक देशों की साझी ताकत बताया।

देश | दुनीया से

नीट परीक्षा : छात्रों का क्या कसूर?

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने 3 मई 2026 को आयोजित हुई नीट यूजी परीक्षा को कथित पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के कारण पूरी तरह रद्द कर दिया है। यूं तो इस कांड ने पूरे देश के शिक्षा जगत को हिला दिया है, इस पूरे मामले को केंद्र सरकार ने भी गंभीरता से लिया है। इसलिए अब इस गड़बड़ी की पूरी जांच सीबीआई को सौंपी गई है। इस जांच में रोज नए तथ्य उजागर हो रहे हैं। नीट-यूजी भारत की एकमात्र एकीकृत मेडिकल प्रवेश परीक्षा है, जो देशभर में स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश तय करती है। पहले होने वाली कई राज्य स्तरीय मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की जगह इस मानकीकृत परीक्षा ने ले ली थी, जो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मान्य है। साल 2024 में भी यह परीक्षा पेपर लीक और ग्रेस मार्क्स देने में अनियमितताओं के आरोपों में घिरी रही थी, जिसके बाद हजारों अभ्यर्थियों को असामान्य रूप से अधिक नंबर मिलने पर देशभर में विरोध प्रदर्शन हुए थे। एनटीए से पहले केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) मेडिकल के लिए नीट और इंजीनियरिंग के लिए जेईई जैसी परीक्षाएं आयोजित करता था, जबकि राज्य बोर्ड और विश्वविद्यालय अपनी अलग प्रवेश परीक्षाएं कराते थे। एनटीए की स्थापना नवंबर 2017 में भारत की उच्च शिक्षा प्रवेश परीक्षा व्यवस्था में सख्ती, मानकीकरण और विश्वसनीयता लाने और स्टूडेंट्स को कई परीक्षाओं के बोझ से राहत देने के उद्देश्य से की गई थी। यह एजेंसी 15 से अधिक परीक्षाएं आयोजित कराती है। लेकिन एनटीए लगातार समस्याओं से घिरी रही है और उस पर पारदर्शिता और सार्वजनिक जवाबदेही की कमी के आरोप लगे हैं। इस पर एक बड़े मंथन की जरूरत है। साल 2024 में प्रशासन को 'परीक्षा की शुद्धता प्रभावित होने' का हवाला देते हुए यूजीसी-नेट परीक्षा भी पूरी तरह रद्द करनी पड़ी थी। इसी दौरान पेपर लीक के आरोप भी सामने आए। शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि प्रवेश परीक्षा के आयोजन में सबसे बड़ी समस्या परीक्षा केंद्रों, निरीक्षकों और कर्मचारियों के लिए आउटसोर्सिंग पर

एजेंसी की भारी निर्भरता है, क्योंकि प्रवेश परीक्षा का आयोजन करने वाली एजेंसी अपने परीक्षा ढांचे के बड़े हिस्से पर सीधे नियंत्रण नहीं रखती, जिससे कमजोरियां पैदा होती हैं। इसमें सुधार किया जाना चाहिए। आज तो इंजीनियरिंग की जेईई जैसी परीक्षाएं अब ऑनलाइन हो चुकी हैं और कई शिफ्टों मे आयोजित होती हैं, जबकि इसके उलट नीट अब भी पारंपरिक पेन-और- पेपर परीक्षा है। इससे भारी लॉजिस्टिक चुनौती पैदा होती है। हजारों प्रश्नपत्र सुरक्षित वाहनों से देशभर के लगभग सैंकड़ों परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने पड़ते हैं, जिससे पूरी परिवहन श्रृंखला सुरक्षा उल्लंघन के लिए संवेदनशील हो जाती है। एनटीए के सामने तो आज भी लॉजिस्टिक चुनौतियां बनी हुई हैं। इस सिस्टम को सुधारना होगा। दुनिया में शायद ही कहीं और लाखों स्टूडेंट्स की पेन और पेपर से परीक्षा एक ही दिन, एक ही शिफ्ट में कराई जाती है। सुनते हैं कि नीट जैसी परीक्षा के लिए करीब 5500 केंद्रों और 550 शहरों में दो लाख से अधिक वॉलंटियर्स, वेंडर्स और अधिकारी शामिल होते हैं। इतने बड़े पैमाने पर परीक्षा कराने से खामियों की संभावना बढ़ जाती है। विशेषज्ञों का कहना है कि नीट अब भी पेन और पेपर से इसलिए होता है ताकि सभी आर्थिक और भौगोलिक पृष्ठभूमि के छात्रों को समान अवसर मिले, क्योंकि कंप्यूटर गरीब या ग्रामीण छात्रों के लिए आसानी से उपलब्ध नहीं हो सकते। लेकिन इस तर्क पर अब सवाल उठ रहे हैं। पूर्व इसरो अध्यक्ष के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाले सात सदस्यीय पैनल ने पेन और पेपर से होने वाली परीक्षा से कंप्यूटर आधारित परीक्षा की ओर धीरे-धीरे बढने की सिफारिश की थी। इस परीक्षा की प्रक्रिया में सुधार सुझाने के लिए बनी इस कमेटी ने एनटीए के पुनर्गठन और एक सुरक्षित परीक्षा प्रशासन तंत्र निर्मित करने के लिए राज्य और जिला प्राधिकारियों के साथ एक मजबूत संस्थागत जुड़ाव बनाने की सिफारिश की थी। इनके अलावा उसने बहु-चरणीय परीक्षा, कागज और कंप्यूटर के हाइब्रिड इस्तेमाल और सेंध व कदाचार रोकने के उपायों की श्रृंखला की भी सिफारिश की, इस पर काम किया जाना जरूरी है। सवाल यह भी है कि क्या कंप्यूटर आधारित परीक्षा ग्रामीण छात्रों के साथ अन्याय करेगी। कुछ शिक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि केंद्रीकृत परीक्षा प्रणाली एक त्रुटिपूर्ण मॉडल है। यह सत्य है कि एक इज्जत के सवाल वाली नीट जैसी परीक्षा भारत के विशाल और महंगे कोचिंग उद्योग के पक्ष में माहौल बना देती है और उन छात्रों को नुकसान पहुंचाती है जो इसका खर्च नहीं उठा सकते। ऐसी प्रवेश परीक्षा उन छात्रों के खिलाफ काम करती है जो कोचिंग का खर्च नहीं उठा सकते। आज सबसे बड़ा सवाल अब सिर्फ प्रवेश परीक्षा पर नहीं, बल्कि इसको संचालित करने वाले सिस्टम की विश्वसनीयता पर खड़ा हो गया है। क्यों न छात्रों के भविष्य को एक ही प्रवेश परीक्षा पर निर्भर रहने से दूर किया जाए? स्कूल परीक्षाओं के प्रदर्शन का भी क्या महत्व नहीं है? केंद्रीकृत परीक्षाएं उन बच्चों को फायदा देती हैं जो कोचिंग का खर्च उठा सकते हैं और हजारों गरीब और मेधावी छात्र संसाधनों की कमी के कारण डाक्टर बनने से रह जाते हैं। हमें इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। वैसे तो एनटीए का अस्तित्व सार्थक है, लेकिन उसकी परीक्षा प्रक्रियाओं में तत्काल सुधार की जरूरत है।

आप का | नजरीया

शहरों को क्या मिलेगा

हिमाचल की राजनीति में नगर निगम चुनाव एक इबारत की तरह दर्ज हुए हैं, जहां पार्टियों ने शक्ति का प्रदर्शन किया। आश्चर्य यह कि जब स्थानीय मुद्दे ढीले पड़े तो सत्ता बनाम विपक्ष हो गया। सारी तोहमतें अगर नगर निगमों के सिंहासन पर फूटीं, तो अगले साल विधानसभा चुनाव के मुद्दे क्या होंगे। नगर निगम चुनावों की जेब में हालांकि कुछ बेहतरीन संकल्प पत्र आए, लेकिन सबसे अहम रहा इनके विस्तार और इनके डिकंजेशन को लेकर अगर कहीं सोचा गया। ताज्जुब यह भी कि यह चुनाव या तो निगम क्षेत्रों में शामिल किए गए गांवों को बाहर निकालने तक पहुंच गया या कहीं टीसीपी कानून को न्यस्त करने का बन गया। यानी दिल से हम कुछ और हैं और नजर हम कुछ और आना चाहते हैं। मंडी नगर निगम के वार्ड नंबर 14 यानी बैहना ने पूरी चुनाव प्रक्रिया का बहिष्कार करके यह साबित कर दिया कि नागरिक समाज 'घोषित शहरी' नहीं होना चाहता। भले ही गांव का कूड़ेदान भर कर परेशान कर रहा है, लेकिन शहरी जीवन की मर्यादा खंडित रहे। यहां व्याख्या गांव की करके 'शहरी लोग' निरंकुश बने रहना चाहते हैं या राजनीति इसकी मदद करती है। पूरे हिमाचल में हजारों एकड़ जमीन पर खेतीबाड़ी नहीं हो रही। गांव की अर्थव्यवस्था चौपट है और लोग किसी भी तरह की नौकरी के लिए दौड़ रहे हैं, फिर भी यह ताना-बाना यही चाहता है कि या तो बीपीएल में दिन गुजर जाए या गांव की रूपरेखा में लाभ की फसल कट जाए। हिमाचल का शहरीकरण उस मानसिकता में है जो हर सडक के किनारे व्यापारी परिसर खड़ा करना चाहती है या घर को आलीशान सुविधाओं के तरीके से चलाना चाहती है। एक और पैटर्न बढ़ते कचरे में देखा जा सकता है, जो गांव की खड्ड तक को परेशान कर रहा। ऐसे में शहर अब ऐसी आर्थिकी का निवेश कर रहे हैं, जो आसपास के दर्जनों गांवों को जोड़कर एक सेतु बना रही है। टीसीपी कानून की मूल आत्मा भी यही कहती है कि शहरी परिदृश्य से जुड़े गांव भी शहरी योजना-परियोजना के दायरे में विकसित हों। अगर नगर निगमों के मर्ज एरिया बाहर करने का आश्वासन चुनाव करते रहे हैं, तो यह शहरी उत्थान के अनेकों दावों का चीरहरण ही करेगा। आज की तारीख में परवाणू से सोलन तक शहरीकरण के कई पड़ाव दिखाई देते हैं, तो इनको संबोधित करने के लिए विकास प्राधिकरण की स्वतंत्र इकाई चाहिए। भुंतर-कुल्लू से मनाली, मंडी-नेरचौक से सुंदरनगर, नादौन-हमीरपुर-भोटा, धर्मशाला-गगल-कांगड़ा या धर्मशाला-चामुंडा-पालमपुर के लिए विकास प्राधिकरण गठित करके गांव और शहर के विकासात्मक रिश्ते सुदृढ़ होंगे। हिमाचल की शहरी तस्वीर को ट्रैफिक जाम या पार्किंग की मजबूरियां खराब कर रही हैं। वाहन पंजीकरण की ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए ताकि वही गाड़ी शहर में दौड़े, जिसके मालिक के पास माकूल पार्किंग सुविधा हो। इसके लिए यह भी जरूरी है कि शहर में सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था को नए सिरे से पढ़ा जाए। हिमाचल में दो या दो से अधिक शहरों के क्लस्टर बना कर स्थानीय परिवहन के मायने बदलने होंगे। स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के तहत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदे तो गए, लेकिन एचआरटीसी ने इनके संचालन में अपने रूट ही बचाए, जबकि इन बसों से शहरी परिवहन का संचालन निजी वाहनों से निजात दिला सकता था। कहना न होगा कि चुनाव गुजरने के बावजूद हमारे राजनीतिक दल यह आश्वासन नहीं दे पाए कि उन्होंने शहरों में बेहतर जीवन देने के लिए लड़े। राजनीति बनाम राजनीति में शहर को क्या मिला, यह आने वाले वक्त में पता चलेगा।

आश्चर्य यह कि जब स्थानीय मुद्दे ढीले पड़े तो सत्ता बनाम विपक्ष हो गया। सारी तोहमतें अगर नगर निगमों के सिंहासन पर फूटीं, तो अगले साल विधानसभा चुनाव के मुद्दे क्या होंगे। नगर निगम चुनावों की जेब में हालांकि कुछ बेहतरीन संकल्प पत्र आए, लेकिन सबसे अहम रहा इनके विस्तार और इनके डिकंजेशन को लेकर अगर कहीं सोचा गया। ताज्जुब यह भी कि यह चुनाव या तो निगम क्षेत्रों में शामिल किए गए गांवों को बाहर निकालने तक पहुंच गया या कहीं टीसीपी कानून को न्यस्त करने का बन गया। यानी दिल से हम कुछ और हैं और नजर हम कुछ और आना चाहते हैं। मंडी नगर निगम के वार्ड नंबर 14 यानी बैहना ने पूरी चुनाव प्रक्रिया का बहिष्कार करके यह साबित कर दिया कि नागरिक समाज 'घोषित शहरी' नहीं होना चाहता। भले ही गांव का कूड़ेदान भर कर परेशान कर रहा है, लेकिन शहरी जीवन की मर्यादा खंडित रहे। यहां व्याख्या गांव की करके 'शहरी लोग' निरंकुश बने रहना चाहते हैं या राजनीति इसकी मदद करती है। पूरे हिमाचल में हजारों एकड़ जमीन पर खेतीबाड़ी नहीं हो रही। गांव की अर्थव्यवस्था चौपट है और लोग किसी भी तरह की नौकरी के लिए दौड़ रहे हैं, फिर भी यह ताना-बाना यही चाहता है कि या तो बीपीएल में दिन गुजर जाए या गांव की रूपरेखा में लाभ की फसल कट जाए। हिमाचल का शहरीकरण उस मानसिकता में है जो हर सडक के किनारे व्यापारी परिसर खड़ा करना चाहती है या घर को आलीशान सुविधाओं के तरीके से चलाना चाहती है।

दृष्टि | कोण

आवारा कुत्तों की भयावह समस्या पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला- लेकिन जिम्मेदारी तय किए बिना कैसे बनेगी बात?

देश की सर्वोच्च अदालत ने आवारा कुत्तों की नसबंदी और दूसरी जगह भेजने के अपने पहले के आदेश को वापस लेने के लिए दायर की गई सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने डॉग लवर्स की याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि यह अदालत देश भर में कुत्ता काटने की घटनाओं की अनदेखी नहीं कर सकती है। इसका सबसे ज्यादा शिकार बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त शब्दों में अपने पहले के आदेश की फिर से याद दिलाते हुए कहा कि सड़क के कुत्तों पर 7 नवंबर, 2025 को दिया गया उनका आदेश ही लागू होगा। इन आदेशों को लागू करने वाले अधिकारियों को कानूनी सुरक्षा दी जाए और जो अधिकारी इनका पालन न करे, उन पर विभागीय और अवमानना की कार्यवाही की जा सकती है। लेकिन क्या इससे देश के आम नागरिकों को खुश होना चाहिए? क्या इससे देश में आवारा कुत्तों से परेशान लोगों - खासकर बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को राहत मिल पाएगी? यह इतना भी आसान नहीं है। जब तक किसी खास अधिकारी की जिम्मेदारी तय नहीं की जाएगी तब तक इस समस्या का निदान नहीं हो सकता है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद व्यवहारिक स्थिति तो यही है कि ज्यादातर राज्य सरकारें और जिला प्रशासन इसे गंभीरता से लेती नज़र नहीं आ रही हैं। इसलिए इस आदेश को लागू करने के लिए हर जिले में जिलाधिकारी यानी सीधे DM को ही जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के नवंबर में दिए गए आदेश के 6 महीने बीत जाने के बावजूद हालत यह है कि देश की राजधानी दिल्ली का नगर निगम - MCD कुत्तों को रखने के लिए एक डॉग सेंटर तक तैयार नहीं कर पाई है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह आदेश जारी कर दिया है कि जो कुत्ता एक से अधिक बार लोगों को काट चुका हो, उसे सार्वजनिक स्थानों पर नहीं छोड़ा जाएगा लेकिन दिल्ली से सटे गाजियाबाद समेत राज्य के कई जिलों में भी अभी भी जरूरी डॉग सेंटर का निर्माण फाइल्स में ही अटका पड़ा है। क्या इस तरह की लापरवाही और लेट-लतीफी

के लिए जिलों के DM को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए? समय आ गया है कि हर जिले, हर राज्य और सबसे ऊपर सीधे सुप्रीम कोर्ट को अपनी निगरानी में एक टोल फ्री नंबर जारी करना चाहिए जिस पर कॉल करने वाले हर व्यक्ति को तुरंत उनकी शिकायत का एक नंबर भी अलॉट कर देना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो टोल फ्री नंबर पर बैठने वाले अदालत के स्टॉफ का खर्चा भी लोगों से ले सकता है और इसके लिए प्रति कॉल 3 से 5 रुपए की राशि भी फिक्स की जा सकती है लेकिन हर कॉल का उचित फॉलोअप सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। इस काम को युद्धस्तर पर करने की जरूरत है क्योंकि भारत में आवारा कुत्तों के काटने की समस्या दिन-प्रतिदिन भयावह होती जा रही है। वैसे तो देश में कुत्तों द्वारा काटने के सारे आंकड़े दर्ज नहीं करवाए जाते हैं लेकिन जो भी आंकड़े दर्ज होते हैं, उसके मुताबिक वर्ष 2024 में हर मिनट पर डॉग बाइट के 7, हर घंटे में 430, रोजाना 10,321 , हर महीने 3,09,643 और वर्ष भर में 37,15,713 मामले दर्ज किए गए हैं। यानी सरकार भी यह मान रही है कि एक साल में 37 लाख से भी ज्यादा लोग कुत्तों के काटने का शिकार बनते हैं। वहीं वर्ष 2025 में कुत्तों के काटने की संख्या 47 लाख से भी ज्यादा बताई जा रही है। सरकारी रिपोर्ट की मानें तो, भारत में हर साल रेबीज के कारण 300 लोगों की मौत होती है। लेकिन WHO के अनुसार भारत में हर साल रेबीज के कारण 18 से 20 हजार लोगों की मौत हो जाती है। यहां इस बात का ध्यान रखना भी जरूरी है कि इस तरह के ज्यादातर मामले आंकड़ों में दर्ज ही नहीं किए जाते हैं।

भाजपा सरकार पक्षपाती और विश्वासघाती : अखिलेश यादव

लखनऊ, (हि.स.)। समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) का हक (आरक्षण) लूटने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ये सरकार पक्षपाती, विश्वासघाती है। बाबा साहब ने भेदभाव दुख को झेला है, इसलिए उन्होंने संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बुधवार को राजधानी लखनऊ में पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस दौरान पीडीए आरक्षण की लूट मामले से जुड़ी एक लाल घोटाला पुस्तक बांटी। जिसमें लिखा था "22 परीक्षाएं, 11514+पीडीए आरक्षित सीटों की लूट।" इसको उन्होंने इस तरह से बताया कि अगर विद्यार्थियों को अपने हक के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़े तो समझ लेना चाहिए कि सरकार पक्षपाती है, के रूप में समझाया। उन्होंने कहा कि यह आंकड़ा आया, ये आंकड़ा अभी और इम्प्रूव होगा। सपा अध्यक्ष ने भाजपा सरकार में "संविधान बचाओ-आरक्षण बचाओ" का नारा दिया। इस नारे के साथ, खतरे में पीडीए आरक्षण, खतरे में संविधान को बचाने की बात कही। उन्होंने कहा कि सपा सरकार आने पर 90 दिन में जातीय जनगणना कराएंगे।

उप्र परिवहन निगम की बसों की लाइव ट्रैकिंग से सुरक्षित बनाया जा रहा यात्रियों का सफर

-प्रतिदिन 16 लाख से ज्यादा यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही योगी सरकार

लखनऊ,(हि.स.)। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने और यात्रियों की सुरक्षा के लिए लगातार प्रयास करती आ रही है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) यात्रियों को सुरक्षित, सुगम यात्रा का अनुभव देने के लिए बड़े पैमाने पर नवीनतम तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। यूपीएसआरटीसी की लगभग सभी बसों की लाइव ट्रैकिंग हो रही है, ताकि प्रतिदिन इन बसों में सफर करने वाले 16 लाख से अधिक यात्रियों की सुरक्षा पुख्ता की जा सके। यूपीएसआरटीसी के वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को बताया कि प्रदेश में परिवहन व्यवस्था को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए 13 हजार 500 से अधिक बसों को व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटीडी) से जोड़ा जा चुका है। इसकी ट्रैकिंग लखनऊ स्थित मुख्यालय के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से हो रही है। उन्होंने बताया कि इन बसों में प्रतिदिन 16 लाख से अधिक लोग यात्रा कर रहे हैं। बसों की ट्रैकिंग के लिए हर रोज 24 घंटे मुख्यालय का कमांड सेंटर और 20 रीजनल मॉनिटरिंग सेंटर एक्टिव रहते हैं। यहां से बस की ओवर स्पीड, तेज ब्रेक लगाने, तेज गति में बस मोड़ने, तय सीमा से अधिक रफ्तार पर बस चलाने, तय रूट समेत अन्य पर नजर रखी जा रही है। इसकी मुख्यालय से रोज रिपोर्ट तैयार होती है और गलती पाए जाने पर बस ड्राइवर को चेतावनी या कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। इससे प्रदेश में दुर्घटनाओं में काफी कमी लाई जा रही है। उन्होंने बताया कि लाइव ट्रैकिंग के साथ इन बसों में हादसे या आपात स्थिति के लिए पैनिक बटन भी लगाए गए हैं। इनका इस्तेमाल होते ही अलर्ट यूपीएसआरटीसी कमांड सेंटर के साथ यूपी पुलिस के कंट्रोल रूम को भी जाता है। इसके बाद फौरन कंडक्टर से संबंधित विभागों से बात कर उचित एक्शन लिया जाता है। यूपीएसआरटीसी के मुताबिक हर रोज पांच हजार से अधिक अलर्ट आते हैं। जरूरत के हिसाब से मदद उपलब्ध कराई जाती है। यूपीएसआरटीसी के मार्गदर्शी पोर्टल और निगम की वेबसाइपट पर ट्रैक माई बस के जरिए यात्रियों को काफी सुविधा मिल रही है। यात्री बस की लोकेशन कहीं से भी लाइव देख सकते हैं।

परिक्रमा मार्ग की व्यवस्थाएं परखने आधी रात को सड़कों पर उतरे मथुरा के जिलाधिकारी

मथुरा, (हि.स.)। अधिक मास के पावन अवसर पर गिरिराज महाराज की नगरी गोवर्धन में उमड़ रहे आस्था के जनसैलाब के बीच प्रशासनिक अमला पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और उनकी सहूलियत को देखते हुए जिलाधिकारी (डीएम) चंद्र प्रकाश सिंह ने स्वयं कमान संभाल ली है। बीती रात डीएम खुद सड़कों पर उतरे और गोवर्धन परिक्रमा मार्ग का पैदल भ्रमण कर व्यवस्थाओं की जमीनी हकीकत परखी। बीती रात करीब दो बजे तक चले इस निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने परिक्रमा मार्ग पर प्रकाश व्यवस्था, पेयजल, साफ-सफाई, सुरक्षा व्यवस्था और यातायात प्रबंधन का बारीकी से जायजा लिया। परिक्रमा मार्ग पर लगातार बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए जिलाधिकारी ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को कड़े और स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिक मास के चलते प्रतिदिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु गिरिराज महाराज की परिक्रमा के लिए देश-विदेश से ब्रज पहुंच रहे हैं। ऐसे में सभी संबंधित विभाग पूरी संवेदनशीलता और आपसी समन्वय (कोऑर्डिनेशन) के साथ काम करें ताकि किसी भी परिक्रमार्थी को कोई असुविधा न हो। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने परिक्रमा मार्ग पर बने सार्वजनिक शौचालयों, स्वास्थ्य शिविरों, विश्राम शेडों, भंडारों और भोजन वितरण स्थलों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाए तथा लगातार कूड़ा उठाया जाए। भीषण गर्मी को देखते हुए पूरे मार्ग पर पेयजल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील प्वाइंट्स पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जाए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने केवल प्रशासनिक रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया, बल्कि मार्ग में चल रहे श्रद्धालुओं और स्थानीय निवासियों से सीधा संवाद भी किया। उन्होंने लोगों से व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया और कुछ स्थानों पर मिली कमियों को देखते हुए मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को तुरंत सुधारात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी के साथ अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) डॉ. पंकज कुमार वर्मा, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) अमरेश कुमार, उप जिलाधिकारी (एसडीएम) गोवर्धन सुशील कुमार सिंह, तहसीलदार बृजेश कुमार सहित विभिन्न विभागों के आला अधिकारी और पुलिस बल मौजूद रहा। गौरतलब है कि 17 मई से शुरू हुआ यह पावन अधिक मास मेला आगामी 15 जून तक चलेगा। इस एक महीने की अवधि में देश के कोने-कोने से लाखों-करोड़ों श्रद्धालु ब्रज चौरासी कोस और गोवर्धन की परिक्रमा करने पहुंच रहे हैं।

हर जाति का सम्मान, सामाजिशिक्षा संस्थानों को नफरत और विभाजन की राजनीति से दूर रखे: अजय राय

वाराणसी (हि.स.)। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय (बीएचयू) जैसे देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान में एमए इतिहास की परीक्षा में ह्लब्राह्मणवादी पितृसत्ताह्व जैसे शब्दों को जिस प्रकार प्रश्न के रूप में प्रस्तुत किया गया है, इसको लेकर विवाद गहराता जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने बुधवार को इस मामले में तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हर जाति का सम्मान, सामाजिक समरसता हमारी पहचान है। ऐसे में शिक्षा संस्थानों को नफरत और विभाजन की राजनीति से दूर रखा जाए। शिक्षा का उद्देश्य किसी जाति, वर्ग या समुदाय के प्रति दुर्भावना पैदा करना नहीं, बल्कि समाज को ज्ञान, संवेदनशीलता और एकता की दिशा देना होता है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज शिक्षा संस्थानों में भी ऐसी विचारधाराएं थोपी जा रही हैं जो समाज में वैचारिक टकराव और जातीय विभाजन को बढ़ावा देती हैं। अजय राय ने कहा कि भारत की सनातन परंपरा में ब्राह्मण समाज सदैव ज्ञान, तप, शिक्षा, संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक रहा है। वेदों, उपनिषदों, भारतीय दर्शन, संस्कृत साहित्य और शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाने में ब्राह्मण समाज का ऐतिहासिक योगदान रहा है। ब्राह्मण समाज सदैव पूजनीय था, है और रहेगा।

भाजपा ने संविधान खत्म कर दिया : राहुल

रायबरेली, (हि.स.)। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और वैचारिक संगठनों ने मिलकर संविधान को खत्म कर दिया है। हर जगह इनके वैचारिक संगठन के लोगों ने कब्जा कर रखा है। अब संविधान को बचाने की जिम्मेदारी आप सब की है। राहुल गांधी अपने उप्र दौरे के दूसरे दिन बुधवार को यहां लोधवारी में शहीद वीरा पासी की प्रतिमा के लोकार्पण के बाद आयोजित बहुजन स्वाभिमान सभा को सम्बोधित कर रहे थे। इस दौरान गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के लिए कुछ आपत्तिजनक शब्द भी बोले। राहुल गांधी ने कहा कि देश में महात्मा गांधी व अंबेडकर की जरूरत है। इन लोगों ने संविधान को फाड़ के फेंक दिया है। मनरेगा बंद कर दिया। विश्वविद्यालयों में अपने चांसलर बैठा दिए, जिन्हें कुछ नहीं आता है। वे केवल संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि महंगाई बढ़ रही है। आर्थिक व्यवस्था ध्वस्त हो रही है, लेकिन प्रधानमंत्री विदेश घूम रहे हैं। वह दूसरों को विदेश जाने से रोक रहे हैं। जब निर्णय लेने का समय है तो जनता को छोड़कर बाहर घूम रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हमेशा की तरह फिर प्रधानमंत्री कहेंगे कि उनकी गलती नहीं है। जबकि आर्थिक तूफान आनेवाला है, जिसे आप सभी को ही भुगतना पड़ेगा। हिन्दुस्तान की सरकार और प्रधानमंत्री आप को बचा नहीं पाएंगें। स्थानीय सांसद गांधी ने लोगों से कहा कि अब चुप रहने का समय नहीं है। उठ खड़े होने का समय है। आवाज उठाने की जरूरत है। इससे पहले राहुल गांधी ने अमर शहीद वीरा पासी की प्रतिमा का लोकार्पण किया। इस अवसर पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना, सांसद तनुज पुनिया सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के पहले राहुल गांधी ने भुएमऊ स्तिथ गेस्ट हाउस में कार्यकताओं व आमजन से मुलाकात की। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकताओं से संगठन को मजबूत करने को कहा व आमजन की समस्याओं को सुनकर निराकरण का आश्वासन दिया। राहुल ने भुएमऊ गेस्ट हाउस में कार्यकताओं, पार्टी पदाधिकारियों, प्रतिनिधिमंडलों व आमजन से मुलाकात की। इस दौरान मीडिया को दूर रखा गया। बाहर मिलने वालों का जमावड़ा लगा रहा। एक-एक व्यक्ति को अंदर भेजा गया।

ईडी केस में आरोपित इंजीनियर सिद्धांत कुमार ने किया आत्मसमर्पण, मिली जमानत

रांची, (हि.स.)। ग्रामीण विकास विभाग में टेंडर घोटाले से जुड़े धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) मामले में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच के दायरे में आए अधिशाषी अभियंता सिद्धांत कुमार ने बुधवार को रांची सिविल कोर्ट स्थित पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) की विशेष अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण के तुरंत बाद अदालत ने उन्हें राहत देते हुए सशर्त जमानत प्रदान कर दी। अदालत ने जमानत देते हुए शर्तें लागू कीं, जिनमें एक लाख रुपये का निजी मुचलका, पासपोर्ट जमा करना तथा अदालत की पूर्व अनुमति के बिना देश से बाहर न जाने का निर्देश शामिल है। इसके साथ ही उन्हें जांच एजेंसियों के साथ सहयोग बनाए रखने की भी अपेक्षा की गई है। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय का आरोप है कि ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत टेंडर प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं बरती गईं। जांच एजेंसी के अनुसार, ठेके आवंटन में नियमों की अनदेखी, मिलीभगत और कमीशनखोरी के जरिए बड़े पैमाने पर वित्तीय गड़बड़ी को अंजाम दिया गया, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा। ईडी ने इस मामले में पहले ही कई अधिकारियों और ठेकेदारों को जांच के दायरे में लिया है। हाल ही में एजेंसी ने प्रमोद कुमार सहित कुल 14 आरोपितों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र (सप्लीमेंट्री चार्जशीट) दाखिल किया था, जिसके बाद अदालत ने सभी आरोपितों को समन जारी किया था। यह मामला नया नहीं है। ईडी ने वर्ष 2023 में पहली बार इस कथित घोटाले को लेकर बड़ी कार्रवाई करते हुए कई इंजीनियरों और ठेकेदारों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। उस दौरान दस्तावेज, डिजिटल रिकॉर्ड और वित्तीय लेन-देन से जुड़े महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए गए थे। इसके बाद 6 मई 2024 को दूसरी बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें कई अभियंताओं और ठेकेदारों के परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया गया। जांच एजेंसी का कहना है कि इस दौरान भी कई महत्वपूर्ण वित्तीय दस्तावेज और लेन-देन के सुराग मिले हैं, जिनका विश्लेषण जारी है। चार्जशीट दाखिल होने के बाद इस मामले में कई अन्य आरोपित भी अदालत में आत्मसमर्पण कर चुके हैं। इनमें से अधिकांश को शर्तों के साथ जमानत मिल चुकी है। कानूनी प्रक्रिया के तहत सभी आरोपितों से पूछताछ और दस्तावेजी जांच आगे बढ़ाई जा रही है। फिलहाल यह मामला जांच के अधीन है और ईडी द्वारा इसकी गहन छानबीन की जा रही है। एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि टेंडर आवंटन प्रक्रिया में किन-किन स्तरों पर अनियमितताएं हुईं और इसमें किन लोगों की भूमिका रही।

विकेन्द्रित उत्पादन से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलती है मजबूती: कल्पना सोरेन

रांची,(हि.स.)। झारखंड के गांडेय विधानसभा क्षेत्र की विधायक कल्पना सोरेन ने महिलाओं की सामूहिक शक्ति, आत्मनिर्भरता और सहयोग की भावना को रेखांकित करते हुए बुधवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक विचारोत्तेजक संदेश साझा किया। अपने पोस्ट में उन्होंने ह्लसंघे शक्ति कलियुगेह्व की अवधारणा का उल्लेख करते हुए प्रसिद्ध सहकारी संस्था ह्यश्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ह्व को महिला सशक्तिकरण का जीवंत और प्रेरणादायक उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि लिज्जत पापड़ केवल एक व्यावसायिक संस्था नहीं, बल्कि महिलाओं के सामूहिक प्रयास, आत्मविश्वास और आर्थिक स्वावलंबन का सफल आंदोलन है, जिसने लाखों महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का कार्य किया है। कल्पना सोरेन ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि झारखंड विधानसभा की महिला एवं बाल विकास समिति के महाराष्ट्र एक्सपोजर विजिट के दौरान उन्हें मुंबई स्थित डब्बावाला इंटरनेशनल एक्सपीरियंस सेंटर जाने का अवसर मिला। लगभग 135 वर्षों से अपनी मेहनत, अनुशासन, समयबद्धता और उत्कृष्ट सेवा के लिए विश्वभर में पहचान बना चुके मुंबई के डब्बावालों की कार्यप्रणाली को नजदीक से समझना बेहद प्रेरणादायक अनुभव रहा। उन्होंने लिखा कि सीमित संसाधनों के बावजूद जिस प्रकार डब्बावाले सामूहिक समन्वय और अनुशासन के बल पर प्रतिदिन लाखों लोगों तक भोजन पहुंचाने का कार्य करते हैं, वह संगठन शक्ति और कार्य संस्कृति का अनूठा उदाहरण है। अपने संदेश में विधायक ने कहा कि ह्यलिज्जत पापड़ह्व केवल एक उद्योग नहीं, बल्कि महिला सशक्तिकरण का एक सशक्त आंदोलन है, जिसने लाखों महिलाओं को सम्मानजनक आजीविका, आत्मनिर्भरता और सामाजिक पहचान दिलाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के सहकारी मॉडल समाज में आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन लाने की बड़ी क्षमता रखते हैं। सामूहिक भागीदारी और साझी जिम्मेदारी पर आधारित यह मॉडल महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के साथ-साथ उनमें आत्मविश्वास भी पैदा करता है। कल्पना सोरेन ने विशेष रूप से ह्यडिस्ट्रिब्यूटेड प्रोडक्शनह्व यानी विकेन्द्रित उत्पादन प्रणाली की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह मॉडल महिलाओं को अपने घर या स्थानीय स्तर पर रहकर काम करने की सुविधा प्रदान करता है, जिससे वे पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ-साथ आर्थिक रूप से भी सशक्त बन पाती हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में इस प्रकार की व्यवस्था महिलाओं के लिए अत्यंत उपयोगी साबित हो सकती है, क्योंकि इससे उन्हें रोजगार के लिए घर छोड़कर दूर शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। साथ ही स्थानीय संसाधनों, पारंपरिक कौशल और घरेलू उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा। विधायक ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए गृह एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना समय की बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि लिज्जत पापड़ जैसे सफल सहकारी मॉडल को हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण, वन उत्पाद, बांस उद्योग और अन्य लघु उद्योग क्षेत्रों में भी लागू किया जाना चाहिए। उनके अनुसार यदि महिलाओं को प्रशिक्षण, बाजार और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाए तो वे न केवल अपने परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकती हैं, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। कल्पना सोरेन ने सरकार, स्वयंसेवी संस्थाओं और निजी क्षेत्र से इस दिशा में समन्वित प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केवल योजनाएं बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें जमीनी स्तर पर प्रभावी तरीके से लागू करना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि यदि सहकारी मॉडल और महिला समूह आधारित उत्पादन प्रणाली को व्यवस्थित तरीके से बढ़ावा दिया जाए, तो ग्रामीण परिवारों को स्थायी और सम्मानजनक आजीविका उपलब्ध कराई जा सकती है। उल्लेखनीय है कि गांडेय से विधायक कल्पना सोरेन झारखंड विधानसभा की महिला एवं बाल विकास समिति की सभापति भी हैं। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रबीन्द्रनाथ महतो द्वारा संसदीय समितियों के पुनर्गठन के दौरान उन्हें यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई थी। समिति के माध्यम से महिलाओं, बच्चों और ग्रामीण समाज से जुड़े मुद्दों पर विभिन्न राज्यों के सफल मॉडलों का अध्ययन किया जा रहा है, ताकि झारखंड में भी उन्हें लागू करने की दिशा में पहल की जा सके।

पटना में बीपीएससी टीआरई-4 वैकेंसी को लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री ने जल्द विज्ञापन का दिया आश्वासन

पटना, (हि.स.)। बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की टीआरई-4 (शिक्षक भर्ती परीक्षा) की वैकेंसी जल्द जारी करने की मांग को लेकर बुधवार को राजधानी पटना में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन शुरू होने से पहले ही पुलिस ने छात्र नेता रिंकल यादव को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद मौके पर तनावपूर्ण स्थिति बन गई और अभ्यर्थियों में भारी आक्रोश फैल गया। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि वे लंबे समय से शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बार-बार सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। छात्रों का आरोप है कि सरकार लगातार भर्ती प्रक्रिया में देरी कर रही है, जिससे लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटक गया है। इसी नाराजगी के बीच आंदोलनकारियों ने थाली और बेलन के साथ सड़क पर उतरकर अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया और सरकार को ह्लनींद से जगानेह्व की चेतावनी दी। प्रदर्शन शुरू होने से ठीक पहले पुलिस ने छात्र नेता रिंकल यादव को हिरासत में ले लिया। रिंकल यादव पटना विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव में अध्यक्ष पद के उम्मीदवार रह चुके हैं। आरोप है कि पुलिस ने उन्हें प्रदर्शन स्थल से घसीटते हुए हिरासत में लिया, जिसके बाद वहां मौजूद छात्रों में नाराजगी और बढ़ गई। इस कार्रवाई के बाद धरना स्थल पर माहौल तनावपूर्ण हो गया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस ने आंदोलन को दबाने के लिए बल प्रयोग किया। छात्रों का कहना है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगें रखने पहुंचे थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें रोकने की कोशिश की। प्रदर्शन के दौरान कुछ महिला अभ्यर्थियों के साथ भी पुलिस की सख्ती देखने को मिली। आरोप है कि धरना स्थल खाली कराने के दौरान कुछ महिला अभ्यर्थियों को जबरन हटाया गया और उनके साथ धक्का-मुक्की की गई। इस घटना के बाद प्रदर्शनकारियों में और ज्यादा नाराजगी फैल गई। वहीं प्रशासन की ओर से कहा गया है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियाती कदम उठाए गए। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था को रोकना उनकी प्राथमिकता है और स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई। इस बीच राज्य के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने स्थिति को संभालने की कोशिश करते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि छात्रों को घबराने या पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सरकार टीआरई-4 भर्ती प्रक्रिया को लेकर गंभीर है और इसका विज्ञापन जल्द ही जारी किया जाएगा। हालांकि मंत्री ने वैकेंसी जारी होने की कोई निश्चित तारीख नहीं बताई। उन्होंने यह भी कहा कि भर्ती प्रक्रिया में देरी जानबूझकर नहीं की जा रही है और सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने आंदोलन के पीछे कुछ बाहरी तत्वों के सक्रिय होने की आशंका भी जताई। उन्होंने कहा कि कुछ लोग छात्रों को भड़काकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मंत्री के अनुसार सरकार इस पर नजर बनाए हुए है और किसी भी तरह की अराजकता को सफल नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा, ह्लसरकार इस पर काम कर रही है। छात्रों को उकसाया जा रहा है। इस प्रदर्शन में कुछ बाहरी लोग भी शामिल हैं। मंत्री ने यह भी कहा कि जब उन्होंने शिक्षा विभाग का कार्यभार संभाला था, उस समय भी अभ्यर्थियों ने जोरदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने कहा,ह्लयह मेरे लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था। मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं थी कि उस दिन प्रदर्शन होने वाला है। मैं अपने कार्यालय में काम संभाल रहा था, तभी मीडिया के जरिए पता चला कि अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ है। इसके बाद मैंने तुरंत पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से बात की थी। प्रदर्शन, पुलिस कार्रवाई और सरकार के बयानों के बीच पटना में तनाव का माहौल बना हुआ है। एक ओर अभ्यर्थी भर्ती में हो रही देरी को लेकर लगातार नाराज हैं, वहीं सरकार जल्द वैकेंसी जारी करने का आश्वासन दे रही है। फिलहाल टीआरई-4 वैकेंसी की आधिकारिक तिथि घोषित नहीं की गई है। ऐसे में अभ्यर्थियों की बेचैनी बनी हुई है और आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज होने की संभावना जताई जा रही है।

प्रभारी मंत्री का विद्या मंदिर में भाजपा कार्यकताओं ने किया अभिनंदन

अररिया (हि.स.)। बिहार सरकार के वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री सह जिले के प्रभारी मंत्री डॉ रामचंद्र प्रसाद का फारबिसगंज के विद्या मंदिर में आगमन पर बुधवार को उनका भाजपा कार्यकताओं के द्वारा भव्य स्वागत और अभिनंदन किया गया। सबका सम्मान जीवन आसान अभियान के तहत आयोजित सहयोग शिविर का निरीक्षण करने बिहार सरकार के वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री सह जिला के प्रभारी मंत्री डॉ रामचंद्र प्रसाद का मंगलवार संध्या को अररिया पहुंचे थे। फारबिसगंज भाजपा के कार्यकताओं ने नगर अध्यक्ष वीरेंद्र प्रसाद मिंटू के अगुवाई में उन्हें फूल माला बुके एवं अंग वस्त्र पहनाकर स्वागत किया। मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष आदित्य नारायण झा, जिला उपाध्यक्ष प्रताप नारायण मंडल, भाजपा नेता प्रवीण कुमार मंत्री डॉ प्रसाद के साथ मौजूद थे। जबकि मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र राय नगर मंत्री विपिन जायसवाल, शिवराम शर्मा, शुभम राय अंशू आहूजा सहित विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष सच्चिदानंद मेहता सचिव डॉ नेहा राज, वार्ड पार्षद बुलबुल यादव, जदयू के बमबम विश्वास आदि ने प्रभारी मंत्री का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान प्रभारी मंत्री डॉ प्रसाद ने कहा कि लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान कर उन्हें न्याय दिलाना ही सहयोग शिविर का मूल उद्देश्य है।

मंत्री ने स्पष्ट किया की पीएम मोदी देश को विकसित तथा पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को समृद्ध बनाना चाहते हैं। उन्होंने बताया की बिहार सरकार के मुख्यमंत्री के निदेर्शानुसार अब बिहार के सभी जिलों सहित अररिया जिला में माह के प्रथम और तृतीय मंगलवार को पंचायत स्तर पर सहयोग शिविर आयोजित किए जाएंगे। अंचल, प्रखंड या थाना स्तर के सभी जन समस्याओं का समाधान 30 दिनों में सुनिश्चित किए जाएंगे।समाधान नहीं होने पर 31वें दिन संबधित पदाधिकारी स्वतः निलंबित हो जाएंगे। प्रभारी मंत्री समस्याओं के आवेदन के लिए बिहार सरकार द्वारा जारी सहयोग ई पोर्टल के साथ हेल्पलाइन की जानकारी दी।

निवेश के लिए खरीदा फिजिकल गोल्ड सबसे महंगा और घाटे वाला विकल्प

आज भी भारत के घरों में करीब पच्चीस हजार टन सोना पड़ा है

नई दिल्ली

भारतीय समाज और सोने का रिश्ता सदियों पुराना है। त्योहारों की रौनक हो या शादियों का उल्लास, सोना हर मोड़ पर भारतीय परिवारों के सुख-दुख का साथी रहा है। एक अनुमान के मुताबिक आज भी भारत के घरों में करीब पच्चीस हजार टन सोना पड़ा है, जो काफी हद तक निष्क्रिय है, अलमारियों में बंद है और जिसकी देश भर में कोई एक तय कीमत भी नहीं है, लेकिन बदलते समय के साथ सोने के बाजार की यह पूरी तस्वीर अब बदल रही है। साल 2024 से सरकार ने नए सावरेन गोल्ड बान्ड (एसजीबी) को जारी करना पूरी तरह बंद कर दिया था, जिसके बाद बजट 2026 के नए नियमों ने इसके टैक्स फायदों को भी सीमित कर दिया। दूसरी तरफ नवंबर 2025 में सेबी ने मोबाइल ऐप्स पर मिलने वाले अनरेगुलेटेड डिजिटल गोल्ड को लेकर कड़ी चेतावनी जारी की थी।

रिपोर्ट के मुताबिक इस बदलते सिस्टम के बीच नेशनल स्टाक एक्सचेंज (एनएसई) के इलेक्ट्रानिक गोल्ड रिसीट्स (ईजीआर) ने निवेश की दुनिया में कदम रखा। अब देश के आम निवेशकों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि सोने में निवेश का सबसे व्यावहारिक, सुरक्षित और किफायती रास्ता कौन सा है। क्या हमें सुनार की दुकान से पारंपरिक सोना खरीदना चाहिए, सालों से चल रहे गोल्ड ईटीएफ में बने रहना चाहिए या फिर नए ईजीआर को अपनाना चाहिए।

पारंपरिक रूप से भारत में सोने की खरीद हमेशा से आभूषणों या सिक्कों के रूप में की जाती रही है, जिसे हम फिजिकल गोल्ड कहते हैं। सुनार की दुकान पर जाकर अपनी आंखों के सामने सोने को देखना और उसे छूकर महसूस करना हमेशा से भारतीयों की पसंद रही है। हंसा रिसर्च ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड की एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट इस उपभोक्ता व्यवहार की गहराई को समझाते हुए कहती हैं कि भारत में गहनों और सोने का अपना एक सांस्कृतिक और भावनात्मक महत्व है, क्योंकि यह लोगों को टैन्जिबल ओनरशिप यानी संपत्ति को छूकर महसूस करने और खुद के पास सुरक्षित रखने की वास्तविक खुशी देता है। यही कारण है कि भारतीय परिवारों में इसकी मांग हमेशा बनी रहेगी।

उन्होंने कहा कि अगर आप इसे सिर्फ निवेश के नजरिए से देखें, तो फिजिकल गोल्ड सबसे महंगा और घाटे वाला विकल्प साबित होता है। सोना खरीदते ही सबसे पहले आपको 3फीसदी जीएसटी देना पड़ता है। इसके अलावा ज्वेलर्स 5फीसदी से लेकर 20फीसदी या उससे भी ज्यादा तक मेकिंग चार्ज वसूल लेते हैं, जिसका निवेश से कोई फायदा नहीं होता। फिर इसकी सुरक्षा की चिंता अलग रहती है। या तो घर में चोरी का डर बना रहता है, या बैंक लाकर के लिए हर साल मोटा किराया देना पड़ता है। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब आप सोना बेचने जाते हैं।

न्यूज ब्रीफ

टोयोटा इनोवा हाईक्रास और क्रिस्टा का जबर्दस्त क्रेज

नई दिल्ली। टोयोटा इनोवा हाईक्रास और टोयोटा इनोवा क्रिस्टा का क्रेज भारतीय ग्राहकों के बीच लगातार बढ़ता जा रहा है। अप्रैल माह में एक बार फिर इनोवा देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली 7-सीटर कार बनकर उभरी है। टोयोटा इंडिया द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, बीते महीने इनोवा की कुल 9,630 यूनिट्स की बिक्री हुई, जो पिछले साल अप्रैल की तुलना में 25 प्रतिशत अधिक है। टोयोटा की बिक्री सूची में दूसरे स्थान पर टोयोटा अर्बन क्रूजर हाईराइडर रही। इस एसयूवी की बिक्री में सालाना आधार पर 96 प्रतिशत की जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई और इसकी 9,115 यूनिट्स बिकीं। वहीं, कंपनी की लोकप्रिय एसयूवी टोयोटा फार्च्यूनर और प्रीमियम हैचबैक टोयोटा ग्लैंजा की बिक्री में गिरावट देखने को मिली, जो बाजार की बदलती प्राथमिकताओं का संकेत है इसके अलावा, टोयोटा रूमियन और टोयोटा टाईसोर ने भी स्थिर प्रदर्शन किया। वहीं, लग्जरी एमपीवी टोयोटा वेलफायर की बिक्री में 490 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो प्रीमियम सेगमेंट में इसकी बढ़ती मांग को दर्शाता है। कंपनी की दमदार एसयूवी टोयोटा लैंड क्रूजर को भी ग्राहकों ने खूब पसंद किया। टोयोटा इंडिया ने अप्रैल माह में कुल 30,159 वाहनों की बिक्री की, जो पिछले साल के मुकाबले 21 प्रतिशत ज्यादा है। इनोवा हाईक्रास की लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण इसका प्रीमियम केबिन, शानदार माइलेज और दमदार हाइब्रिड इंजन माना जा रहा है।

मारुति सुजुकी ब्रेजा जल्द आएगी नए अवतार में

नई दिल्ली। सबसे लोकप्रिय कामपैक्ट एसयूवी में शुमार मारुति सुजुकी ब्रेजा अब एक नए अवतार में आने की तैयारी कर रही है। हाल ही में दिल्ली के पास वेस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पर ब्रेजा फेसलिफ्ट के टेस्ट माडल को देखा गया। टेस्टिंग के दौरान गाड़ी में एमिशन टेस्टिंग किट लगी दिखाई दी, जिससे संकेत मिल रहे हैं कि कंपनी इसमें नया इंजन विकल्प पेश कर सकती है। जानकारी के अनुसार, मारुति इस फेसलिफ्ट माडल में 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन या फिर 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दे सकती है। अगर ऐसा होता है, तो नई ब्रेजा की शुरुआती कीमत पहले से अधिक आकर्षक हो सकती है, क्योंकि वर्तमान में कंपनी इस एसयूवी में 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन देती है। नई ब्रेजा फेसलिफ्ट के डिजाइन में भी कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसके फ्रंट ग्रिल को पहले से ज्यादा आधुनिक लुक दिया गया है, जबकि बंपर में रडार हाउसिंग दिखाई दी है, जिससे उम्मीद लगाई जा रही है कि इसमें एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) फीचर दिया जा सकता है। इसके अलावा, नए ट्राएंगल शेप फाग लैंप, सिल्वर स्किड प्लेट और 16-इंच के नए अलाय व्हील्स भी देखने को मिल सकते हैं, जो इसके लुक को और भी स्पोर्टी बनाएंगे। सीएनजी वैरिएंट में भी एक बड़ा बदलाव संभव है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी सीएनजी टैंक को गाड़ी के नीचे शिफ्ट कर सकती है, जिससे बूट स्पेस पहले से ज्यादा मिलेगा।

वोक्सवैगन गोल्फ जीटीआई की सिर्फ 2 यूनिट बिकीं

नई दिल्ली। लग्जरी कार निर्माता कंपनी वोक्सवैगन इंडिया की वोक्सवैगन गोल्फ जीटीआई को खरीददार नहीं मिल रहे है। यही वजह है कि अप्रैल में सिर्फ 2 यूनिट बिकीं। कंपनी द्वारा जारी हालिया आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल माह में कंपनी की यह हाई-परफार्मेंस कार सिर्फ 2 ग्राहकों तक ही पहुंच सकी। इससे पहले मार्च महीने में भी इसकी केवल 3 यूनिट्स बिकी थीं, जो इसकी बेहद सीमित बिक्री को दर्शाती है। 53 लाख रुपये की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत वाली यह कार कई प्रीमियम फीचर्स से लैस है। इसमें 12.9-इंच की बड़ी टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 7-स्पीकर साउंड सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ, एम्बिएंट लाइटिंग, वायरलेस चार्जिंग और हीटेड फ्रंट सीट्स जैसे फीचर्स दिए गए हैं। कार को यूरो एनकैप से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिल चुकी है, जो यात्रियों की सुरक्षा के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को उजागर करती है। परफार्मेंस की बात करें, तो इसमें 2.0-लीटर टीएसआई टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 261 बीएचपी की ताकत और 370 एनएम का टार्क पैदा करता है। यह कार महज 5.9 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है, जो इसे एक सच्ची स्पोर्ट्स कार बनाती है। इसमें 7-स्पीड डीएसजी गियरबाक्स दिया गया है और इसकी टाप स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटा तक सीमित रखी गई है।

सरकार ऊर्जा संकट के बीच अब इलेक्ट्रिक बस-ट्रकों को बढ़ावा देने की तैयारी में

1 अरब डालर की प्रोत्साहन योजना पर विचार कर रहा केंद्र

नई दिल्ली

भारत सरकार ऊर्जा संकट के बीच प्राइवेट सेक्टर में इलेक्ट्रिक बसों और ट्रकों को बढ़ावा देने के लिए 1 अरब डालर यानी करीब 8,300 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रोत्साहन योजना पर विचार कर रही है। इस योजना का मकसद कामर्शियल परिवहन क्षेत्र में जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना है।

एक रिपोर्ट के मुताबिक नाम न छापने की शर्त पर मामले से जुड़े लोगों ने बताया कि यह प्रोग्राम 10 सालों तक चलेगा और मुख्य रूप से भारत के प्राइवेट ओन्ड कामर्शियल फ्लीट को टारगेट करेगा। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा इंटर-सिटी बस आपरेटरों के लिए रखा जा सकता है। योजना को अंतिम रूप देने के लिए इस महीने प्रधानमंत्री कार्यालय और इंडस्ट्री से जुड़े पक्षों के साथ बैठकें हो सकती हैं। अंतिम बजट आवंटन, प्रोत्साहन पाने वाले वाहनों की श्रेणी और सब्सिडी ढांचे पर अभी काम चल रहा है और इसमें बदलाव संभव है।

रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम एशिया संकट के कारण ऊर्जा आपूर्ति में आई बाधाओं के बाद भारत सरकार पेट्रोल, डीजल आदि पर निर्भरता घटाने की कोशिश कर रही है। इससे ऊर्जा सुरक्षा और आयातित महंगाई को लेकर चिंताएं फिर बढ़ गई हैं। भारत अपनी कीरब 90 फीसदी कच्चे तेल की जरूरत आयात के जरिए पूरी करता है, जिससे वह वैश्विक भू-राजनीतिक संकट और कीमतों में उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील बना रहता है। कमर्शियल ट्रांसपोर्ट का

इलेक्ट्रिफिकेशन भारत में बढ़ते वायु प्रदूषण को कम करने में भी मदद करेगा। इंटरनेशनल काउंसिल आन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन के मुताबिक नई दिल्ली जैसे शहरों में वाहनों से होने वाला उत्सर्जन सालाना सूक्ष्म कण प्रदूषण का लगभग 40 फीसदी तक योगदान देता है। पिछले पांच सालों में इलेक्ट्रिक बसों को अपनाने की रफ्तार तेजी से बढ़ी है, जिसमें सरकारी परिवहन कंपनियों की बड़ी भूमिका रही है। हालांकि भारत में अभी भी ज्यादातर नई बसें डीजल से चलती हैं।

हालांकि डीजल पर निर्भरता केवल भारत की समस्या नहीं है, चीन, अमेरिका और यूरोप जैसे क्षेत्र कमर्शियल वाहनों के इलेक्ट्रिफिकेशन में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। चीन में पहले से ही लाखों इलेक्ट्रिक ट्रक और बसें चल रही हैं, जबकि अमेरिका और यूरोप शहरी लाजिस्टिक्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्लीट को तेजी से इलेक्ट्रिक बना रहे हैं। अनुमानों के मुताबिक भारत में 20 लाख से ज्यादा बसें हैं, लेकिन इनमें से केवल 5 फीसदी बसों पर सरकार का नियंत्रण है। वहीं देश में करीब सभी ट्रक निजी क्षेत्र द्वारा संचालित किए जाते हैं और यही डीजल की सबसे बड़ी खपत करते हैं। उन्होंने बताया कि अधिकारी छोटे कमर्शियल फ्लीट आपरेटरों को इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के उपायों पर विचार कर रहे हैं। ये आपरेटर ऊंची शुरुआती लागत और सीमित वित्तपोषण के कारण कठिनाई का सामना कर रहे हैं। विचाराधीन प्रोत्साहनों में वाहन की पूरी अवधि में प्रति वाहन 15 लाख रुपए तक का ब्याज सब्सिडी लाभ शामिल हो सकता है, जिसे समय के साथ धीरे-धीरे कम किया जाएगा। सरकार प्राइवेट कंपनियों को इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहन खरीदने के लिए वित्तपोषण उपलब्ध कराने के लिए आंशिक क्रेडिट गारंटी व्यवस्था पर भी विचार कर रही है।

ओमेक्स ने इंदौर-उज्जैन की आवासीय परियोजनाओं के लिए जुटाए 75 करोड़

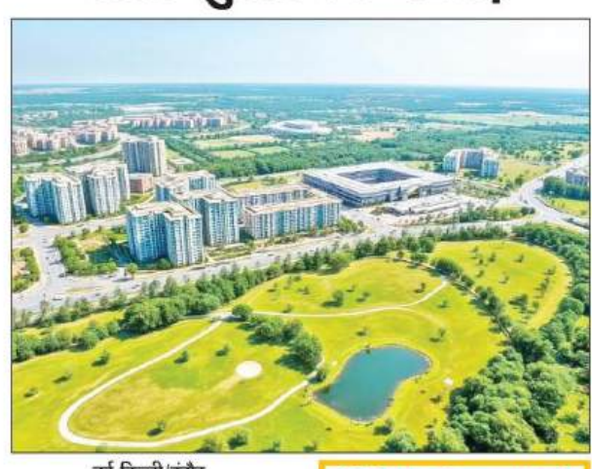

निवेश फर्म डब्ल्यूएसबी पार्टनर्स के साथ हुआ करार; आवासीय प्लाट परियोजनाओं को मिलेगी नई गति

नई दिल्ली/इंदौर

रियल एस्टेट क्षेत्र की प्रमुख कंपनी ओमेक्स ने अपने विस्तार को नई दिशा देने के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय उपलब्धि हासिल की है। कंपनी ने निवेश फर्म डब्ल्यूएसबी पार्टनर्स के साथ करार कर 75 करोड़ रुपये की पूंजी जुटाई है। यह निवेश मुख्य रूप से कंपनी की इंदौर और उज्जैन में चल रही दो प्रमुख आवासीय परियोजनाओं के विकास के लिए किया गया है।

मंगलवार को जारी नियामक फाइलिंग में ओमेक्स समूह ने इस निवेश की पुष्टि करते हुए बताया कि यह फंडिंग विशेष रूप से इंदौर और उज्जैन में विकसित की जा रही आवासीय प्लाट परियोजनाओं के लिए है। कंपनी का कहना है कि प्राप्त पूंजी का उपयोग मुख्य रूप से ग्रोथ कैपिटल के तौर पर विकास कार्यों को गति देने में किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, एक हिस्सा कार्यशील पूंजी और भविष्य के रिजर्व के लिए आवंटित किया गया है।

रियल एस्टेट बाजार में बढ़ेगा भरोसा - वर्ष 1987 में स्थापित ओमेक्स भारत की अग्रणी रियल एस्टेट कंपनियों में से एक है। कंपनी अब तक देश के 8 राज्यों के 31 शहरों में लगभग 140.17 मिलियन वर्ग फीट का निर्माण कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर चुकी है।

इसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं। ओमेक्स आवासीय, वाणिज्यिक और एकीकृत टाउनशिप परियोजनाओं के निर्माण में विशेषज्ञता रखती है। इस निवेश से इंदौर और उज्जैन में ओमेक्स की आवासीय परियोजनाओं के निर्माण कार्य में तेजी आने की प्रबल संभावना है, जिससे स्थानीय रियल एस्टेट बाजार में ग्राहकों का भरोसा भी बढ़ेगा।

एसयूवी किआ सेल्टोस का बिक्री में शानदार प्रदर्शन

नई दिल्ली। हालिया बिक्री आंकड़ों पर नजर डाले तो किआ इंडिया की लोकप्रिय एसयूवी किआ सेल्टोस ने शानदार प्रदर्शन किया है। जारी आंकड़ों के अनुसार, नई सेल्टोस कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गई है, जिसके दम पर किआ इंडिया को सालाना आधार पर 15 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि हासिल हुई है। अप्रैल माह में सेल्टोस की कुल 10,566 यूनिट्स बिकीं, जबकि पिछले साल इसी महीने इसकी 6,135 यूनिट्स की बिक्री हुई थी। इस तरह इस माडल ने 72 प्रतिशत से अधिक की शानदार बढ़त दर्ज की, और कंपनी की कुल बिक्री में इसका हिस्सा करीब 39 प्रतिशत रहा, जो इसकी लोकप्रियता को दर्शाता है दूसरी ओर, किआ सोनेट की बिक्री भी मजबूत रही, जिसकी अप्रैल माह में 10,537 यूनिट्स बिकीं, जो पिछले साल की तुलना में करीब 31 प्रतिशत ज्यादा है। वहीं, किआ कैरेंस क्लैविस की 5,465 यूनिट्स बिकीं, जिसमें मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई। हालांकि, किआ साइरोस की बिक्री में भारी गिरावट देखने को मिली और इसकी बिक्री 86 प्रतिशत तक घट गई। इसके बावजूद, कंपनी की कुल बिक्री 27,286 यूनिट्स तक पहुंच गई, जो पिछले साल की तुलना में 3,663 यूनिट्स ज्यादा है। नई सेल्टोस की सफलता का सबसे बड़ा कारण उसका नया डिजाइन, प्रीमियम फीचर्स और दमदार इंजन माना जा रहा है।

भारतीय बाजार में कई दमदार इलेक्ट्रिक एसयूवी हैं मौजूद

नई दिल्ली

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ईंधन बचाने और वैकल्पिक ऊर्जा अपनाने की अपील की थी, जिसके बाद इलेक्ट्रिक कारों को लेकर लोगों की दिलचस्पी और बढ़ गई है। भारतीय बाजार में इस समय कई दमदार इलेक्ट्रिक एसयूवी मौजूद हैं, जो शानदार रेंज और आधुनिक फीचर्स के साथ ग्राहकों को आकर्षित कर रही हैं। मारुति सुजुकी ई विटारा, कंपनी की पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी के तौर पर सामने आई है, जिसे 49 केडब्ल्यूएच और 61 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक के साथ लान्च किया गया है। बड़ी बैटरी के साथ यह कार 543 किलोमीटर तक की एआरएआई प्रमाणित रेंज देने का दावा करती है। इसकी शुरुआती कीमत बैटरी-एज-ए-सर्विस माडल के तहत 10.99 लाख रुपये रखी गई है।

वहीं, महिंद्रा बीई 6 अपनी स्पोर्टी डिजाइन और शानदार परफार्मेंस के कारण काफी चर्चा में है। यह एसयूवी केवल 6.7 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है और एक बार चार्ज करने पर 638 किलोमीटर तक की दूरी तय करने में सक्षम है। इसकी शुरुआती कीमत 18.90 लाख रुपये है। एमजी विंडसर प्रो पारिवारिक ग्राहकों के लिए एक व्यावहारिक विकल्प साबित हो रही है, जिसमें बड़े केबिन और आरामदायक सीटिंग के साथ 449 किलोमीटर तक की रेंज मिलती है। दूसरी ओर, टाटा पंच ईवी बजट ग्राहकों के लिए बेहतर विकल्प बनकर उभरी है, जिसकी शुरुआती कीमत 9.69 लाख रुपये है और यह करीब 355 किलोमीटर तक की रेंज देती है।

इसके अलावा, बियतनामी कंपनी की विनफास्ट वीएफ 7 भी भारतीय बाजार में तेजी से लोकप्रिय हो रही है। 70.7 केडब्ल्यूएच बैटरी से लैस यह एसयूवी एक बार चार्ज करने पर 510 किलोमीटर तक चल सकती है, जो इसे लंबी दूरी के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाती है। मालूम हो कि देशभर में पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों ने आम लोगों के बजट को बुरी तरह प्रभावित किया है। ऐसे में अब ग्राहकों का रुझान तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ रहा है।

तेल की जंग: किसने छापे अरबों, कौन हुआ बेहाल, अमेरिका ने कमाए 4.81 लाख करोड़, रूस को 1.44 लाख करोड़ का लाभ

नई दिल्ली

मध्य-पूर्व में लंबे समय से जारी भू-राजनीतिक तनाव ने वैश्विक ऊर्जा बाजार में एक अभूतपूर्व उथल-पुथल मचा दी है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन में भारी गिरावट तथा सामरिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य के बाधित होने से अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल व गैस की कीमतें आसमान छू गई हैं। इस गंभीर ऊर्जा संकट ने जहां कुछ देशों के लिए अप्रत्याशित अवसर खोले हैं, वहीं कई पारंपरिक तेल निर्यातक देशों को गहरे वित्तीय घाटे में धकेल दिया है। इस भूचाल का सबसे बड़ा फायदा अमेरिका और रूस को हुआ है, जबकि 5 प्रमुख खाड़ी देशों को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। एक स्थानीय समाचार पत्र की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक बाजार में कच्चे तेल और ईंधन की कमी का फायदा उठाते हुए अमेरिकी कंपनियों ने जमकर मुनाफा कमाया है। अमेरिकी तेल

कंपनियों ने इस दौरान करीब 14.50 करोड़ बैरल अतिरिक्त तेल की बिक्री की, जिससे देश को 4.81 लाख करोड़ रुपए की बंपर अतिरिक्त आय हुई है। अमेरिका लगातार बड़े पैमाने पर कच्चे तेल, डीजल और अन्य ईंधन का निर्यात बढ़ा रहा है। इसी तरह युद्ध और प्रतिबंधों के बावजूद रूस भी इस संकट का लाभ उठाने में सफल रहा है। युद्ध शुरू होने से पहले जिस रूसी तेल की कीमत महज 41 डालर प्रति बैरल थी, वह 120 डालर प्रति बैरल तक पहुंच गई। नतीजतन, रूस के कुल तेल निर्यात में 5.92 लाख बैरल की गिरावट के बावजूद, उसने 1.44 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त मुनाफा बटोरा है। सऊदी अरब ने भी इस अवसर को भुनाया है। होर्मुज जलडमरूमध्य पर पूरी तरह निर्भर न होने और वैकल्पिक पाइपलाइनों के कारण वह नुकसान से बचा रहा। उसके तेल निर्यात में कमी के बावजूद, महंगे तेल ने आय में 88,538 करोड़ रुपए से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज कराई। हालांकि, जहां कुछ देशों ने आपदा को अवसर में बदला, वहीं ईरान से जुड़े संघर्ष और भौगोलिक बाधाओं के कारण 5 प्रमुख खाड़ी देशों को भारी आर्थिक चोट पहुंची है।

उनके तेल उत्पादन और निर्यात दोनों ही बुरी तरह प्रभावित हुए हैं:

कुवैत: तेल निर्यात में 15 करोड़ बैरल की भारी गिरावट के साथ 96,238 करोड़ का नुकसान।

कतर: 8.40 करोड़ बैरल की कमी से 55,818 करोड़ की राजस्व हानि।

ओमान: तेल कारोबार में गिरावट से आय 55,800 करोड़ घटी।

ईरान: संघर्ष के केंद्र में होने के कारण 4.30 करोड़ बैरल निर्यात घटा, 23,095 करोड़ का घाटा।

यूएई: निर्यात में 5.50 करोड़ बैरल की कमी से 15,405 करोड़ का नुकसान।

नए वैकल्पिक मार्गों की तलाश जरूरी: एसएंडपी ग्लोबल के वैश्विक तेल आपूर्ति प्रमुख जिम बर्कहार्ड के अनुसार यदि यह संकट लंबे समय तक खिंचता है तो वही देश मजबूत बनकर उभरेंगे जिनके पास तेल निकासी के वैकल्पिक मार्ग हैं। जो देश पूरी तरह से होर्मुज स्ट्रेट जैसे संवेदनशील जलमार्गों पर निर्भर हैं, उनकी आर्थिक मुश्किलें भविष्य में और बढ़ सकती हैं। यह संकट वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए नए और सुरक्षित रास्ते तलाशने की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

अब ओलंपिक खेलों पर है महिला मुक्केबाज निखत जरीन की नजरें

साई और बाक्सिंग फेडरेशन विवाद से भी खिलाड़ियों की तैयारी प्रभावित हुई

नई दिल्ली

महिला मुक्केबाज निखत जरीन की नजरें अब 2028 लास एंजिल्स ओलंपिक खेलों पर लग गयी हैं। निखत को हाल ही में एशियाई और राष्ट्रमण्डल खेलों के ट्रायल्स में हार का सामना करना पड़ा था जिससे वह निराश हैं। निखन ने इसका एक कारण भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) और बाक्सिंग फेडरेशन के प्रशासनिक विवाद को भी बताया और कहा कि इन दोनों संस्थाओं के बीच तनाव का सीधा असर खिलाड़ियों की तैयारी पर पड़ा और मुक्केबाज बीच में फंसकर रह गए हैं। ट्रायल मुकाबले में हार के कारणों को लेकर इस मुक्केबाज ने कहा कि वह मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह थक चुकी थीं। वह जनवरी 2025 से लगातार टूर्नामेंट खेल रही हैं और घर पर पर्याप्त समय भी नहीं बिता पा रही थीं। निखत जरीन को भारतीय मुक्केबाजी की सबसे मजबूत पदक दावेदारों में गिना जाता है। ऐसे में उनका ट्रायल से बाहर होना खेल जगत के लिए बड़ा झटका माना जा रहा हैं निखत ने कहा कि अब वह अपनी गलतियों पर काम करेंगी और मजबूत वापसी के प्रयास करेगी। उन्होंने साफ किया कि उनका अगला लक्ष्य लास एंजिलिस ओलंपिक के क्वालीफायर होंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय मुक्केबाजी महासंघ जब भी राष्ट्रीय प्रतियोगिता की घोषणा करेगा, वह पूरी तैयारी के साथ वापसी करेंगी। निखत के अनुसार राष्ट्रीय शिविर 26 मई से शुरू होना था, लेकिन मंजूरी नहीं मिलने के कारण खिलाड़ी संशय में रहे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में उनके पास उचित प्रशिक्षण केंद्र नहीं है, जिससे उनकी चिंता और बढ़ गई थीं। उन्होंने यह भी कहा कि खिलाड़ियों को रोजाना वजन कम करने के सख्त लक्ष्य दिए गए थे। मुक्केबाजों को शारीरिक परीक्षण, ताकत परीक्षण और बीप टेस्ट से गुजरना पड़ा, लेकिन बाद में बताया गया कि इन अंकों को अंतिम चयन में शामिल ही नहीं किया जाएगा। इससे खिलाड़ियों पर अतिरिक्त मानसिक दबाव बन गया था। वहीं महिला टीम के मुख्य कोच सैंटियागो नीवा ने भी निखत का समर्थन किया।

न्यूज ब्रीफ

कलाई की चोट के कारण विंबलडन 2026 से बाहर हुए कार्लोस अल्कराज

नई दिल्ली। दुनिया के नंबर-2 टेनिस खिलाड़ी स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने आगामी विंबलडन 2026 से हटने का फैसला किया है। अल्कराज ने बताया कि वह कलाई की चोट से पूरी तरह उबर नहीं पाए है, जिसके कारण वह घास के कोर्ट सीजन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। अल्कराज ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा, मेरी रिकवरी अच्छी चल रही है और मैं पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूं, लेकिन दुर्भाग्य से मैं अभी खेलने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हूं। इसी वजह से मुझे क्वींस और विंबलडन से हटना पड़ रहा है। ये दोनों टूर्नामेंट मेरे लिए बेहद खास हैं और मैं इन्हें बहुत मिस करूंगा। हम जल्द वापसी के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। 23 वर्षीय अल्कराज इससे पहले फ्रेंच ओपन 2026 से भी हट चुके हैं, जहां वह गत चैंपियन थे। उन्हें पिछले महीने बार्सिलोना ओपन के पहले दौर के मुकाबले के दौरान कलाई में चोट लगी थी। उन्होंने उस मैच में ओटो विर्टानेन को हराया था, लेकिन बाद में टूर्नामेंट से नाम वापस ले लिया। अल्कराज ने इसी साल जनवरी में आस्ट्रेलियन ओपन जीतकर करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले सबसे युवा पुरुष खिलाड़ी बनने का रिकार्ड बनाया था। इस सीजन में उनका रिकार्ड 22-3 का रहा है और उन्होंने दोहा में भी खिताब अपने नाम किया। मोंटे कार्लो मास्टर्स फाइनल में यानिक सिनर से हारने के बाद अल्कराज ने विश्व नंबर-1 की रैंकिंग भी गंवा दी थी ।

आईपीएल 2026 : वैभव सूर्यवंशी की विस्फोटक पारी से जीता राजस्थान, लखनऊ को 7 विकेट से हराया

जयपुर। राजस्थान रायल्स ने तीन मैचों की हार का सिलसिला तोड़ते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराकर शानदार वापसी की। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में राजस्थान ने 221 रन के बड़े लक्ष्य को 19.1 ओवर में हासिल कर लिया। मैच के सबसे बड़े हीरो युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी रहे, जिन्होंने सिर्फ 38 गेंदों पर 93 रन की विस्फोटक पारी खेली। उनकी बल्लेबाजी में 7 चौके और 10 छक्के शामिल रहे। उन्होंने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया और लखनऊ के गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखा। कप्तान यशस्वी जायसवाल ने भी तेज शुरुआत करते हुए 23 गेंदों में 43 रन बनाए। दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 75 रन जोड़कर राजस्थान की जीत की नींव रखी। सूर्यवंशी के आउट होने के बाद ध्रुव जुरेल ने पारी को संभाला और नाबाद 53 रन बनाकर टीम को जीत तक पहुंचाया। अंतिम चरण में डोनोवन फरेरा ने भी तेज 16 रन जोड़कर जीत आसान बना दी। इससे पहले, टास हारकर बल्लेबाजी करने उतरी लखनऊ की ओर से मिचेल मार्श शतक से चूक गए और 57 गेंदों में 96 रन बनाकर रन आउट हुए। जाश इंग्लिश ने 29 गेंदों में 60 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। दोनों ने पहले विकेट के लिए 109 रन की बड़ी साझेदारी की। कप्तान ऋषभ पंत ने भी 35 रन का योगदान दिया, जिससे टीम 20 ओवर में 220 रन तक पहुंच सकी। हालांकि, लखनऊ की गेंदबाजी निराशाजनक रही। राजस्थान के बल्लेबाजों के सामने गेंदबाज लगातार संघर्ष करते दिखे। वहीं गेंदबाजी में राजस्थान के लिए जोफ्रा आर्चर और यश राज पुंजा ने महत्वपूर्ण सफलता हासिल की।

भारतीय अंडर-18 महिला हाकी टीम ने आस्ट्रेलिया को 4-1 से हराकर सीरीज का किया शानदार समापन

भोपाल। भारतीय अंडर-18 महिला हाकी टीम ने बुधवार को भोपाल स्थित उधव दास मेहता (भाई जी) सेंट्रल साई सेंटर में खेले गए चार मैचों की श्रृंखला के अंतिम मुकाबले में आस्ट्रेलिया अंडर-18 महिला हाकी टीम को 4-1 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। मुकाबले की शुरुआत में आस्ट्रेलिया ने आक्रामक खेल दिखाया और पहले क्वार्टर के 8वें मिनट में आरोरा कोवासेविच ने गोल कर टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी। हालांकि भारतीय टीम ने जल्द ही वापसी करते हुए कप्तान स्वीटी कुजूर ने 13वें मिनट में गोल दागकर स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। दूसरे क्वार्टर में भारत ने अपना दबदबा बनाए रखा। 25वें मिनट में दिया ने शानदार गोल कर भारत को 2-1 की बढ़त दिलाई, जो हाफटाइम तक कायम रही। दूसरे हाफ में भी भारतीय खिलाड़ियों ने मैच पर पूरा नियंत्रण बनाए रखा। तीसरे क्वार्टर के 44वें मिनट में प्रियंका मिंज ने गोल कर बढ़त 3-1 कर दी। इसके बाद अंतिम क्वार्टर में नौशीन नाज ने 50वें मिनट में गोल दागकर भारत की 4-1 की शानदार जीत सुनिश्चित कर दी।

आरसीबी के निदेशक ने बताया टीम की सफलता का राज

बेंगलुरु

रायल चैलेंजर्स बेंगलुरू (आरसीबी) का प्रदर्शन आईपीएल के इस 19 वें सत्र में भी शानदार रहा है और वह सबसे पहले प्लेआफ में पहुंची है। आरसीबी ने पिछले साल भी खिताब जीता था जिसे बरकरार रखना इस बार भी उसका लक्ष्य है और टीम उसी दिशा में आगे बढ़ रही है।

टीम के इस सत्र में असाधारण प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए उसके क्रिकेट निदेशक मो बोबाट ने कहा है कि इस शानदार फार्म का कारण एक अनूठी सोच है, जिसने पिछली बार खिताब जीतने के बावजूद खिलाड़ियों को आत्मसंतुष्टि से दूर रखा। बोबाट ने कहा, मैं यह महसूस नहीं करना चाहता जैसे हमने माउंट एवरेस्ट फतेह कर लिया हो। हम हमेशा आग बढ़त रहना चाहते हैं। हमारी सोच हमेशा आक्रामक होनी चाहिये। यह विचार टीम के भीतर लगातार गूंजता रहता है, जिसका लक्ष्य यह पक्का करना है कि खिलाड़ी कभी भी अपनी पिछली उपलब्धियों पर स्थिर न हों, बल्कि हमेशा अगले लक्ष्य की तलाश में रहें। इस दौरान एक महत्वपूर्ण पहलू तेजी से अपने को हालातों के अनुकूल ढालना और अपनी रणनीति को लगातार नया रूप देना है। बोबाट के अनुसार, मेरे लिए और यहां तक कि सीनियर खिलाड़ियों के लिए भी, तेजी से अपने को ढालना, अपनी सोच को फिर से सेट करना और यह तय करना कि अब हम आगे किस चीज पर काम करने वाले हैं, यह सचमुच बहुत जरूरी है। यह प्रक्रिया खिलाड़ियों को वर्तमान चुनौती पर ध्यान केंद्रित करने और भविष्य के लिए तैयार रहने में सहायता करती है। इसके साथ ही इस रणनीति को सफल बनाने में डग आउट में मौजूद खिलाड़ियों की विविधता भी एक अहम भूमिका निभाती है।

भारत में पहली बार खेली जा सकती है आस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग

चेन्नई। आस्ट्रेलिया की प्रतिष्ठित टी20 लीग बिग बैश (बीबीएल) 2026-27 सत्र का आयोजन भारत में हो सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार इस लीग का शुरुआती मुकाबला चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में आयोजित किया जा सकता है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) और तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन (टीएनसीए) दोनों ही इसपर सहमत हो गये हैं। जिससे भारत में पहली बार एक विदेशी टी20 लीग की मेजबानी की राह बन रही है। इस लीग के आयोजन को लेकर क्रिकेट आस्ट्रेलिया (सीए) इस साल की शुरुआत से ही प्रयास कर रहा था। उसने ने कई महीनों पहले ही चेन्नई को संभावित मेजबान स्थल के रूप में चिन्हित कर लिया था। शुरुआती दौर की बातचीत और गहन विचार-विमर्श के बाद अब बीसीसीआई और टीएनसीए, दोनों ही इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन को भारत लाने के लिए उत्सुक दिखाई दे रहे हैं। यह कदम वैश्विक क्रिकेट कैलेंडर में भारत की केंद्रीय भूमिका को और मजबूत करेगा। एमए चिदंबरम स्टेडियम, जिसे चेपाक के नाम से भी जाना जाता है, इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स का गढ़ है। यह मैदान हमेशा से अपने जोशीले क्रिकेट माहौल और दर्शकों के गहरे जुड़ाव के लिए प्रसिद्ध रहा है, जहाँ क्रिकेट मैच किसी उत्सव से कम नहीं होते। आस्ट्रेलियाई टीमें भी भारत में खेलने के लिए जबरदस्त उत्साह दिखा रही हैं। सिडनी थंडर, मेलबर्न स्टार और मेलबर्न रेनेगेड्स जैसी प्रमुख बीबीएल फ्रेंचाइजी ने विशेष रूप से चेन्नई में मैच खेलने की इच्छा व्यक्त की है, जो इस पहल को और बल देता है और बताता है कि आस्ट्रेलियाई टीमें भारतीय प्रशंसकों के सामने खेलने को लेकर कितनी उत्सुक हैं। इस प्रस्तावित आयोजन को लेकर हुए सीए को एक पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी गत दिवस चेन्नई पहुंचा था। इस दल ने स्टेडियम का विस्तृत निरीक्षण किया और आयोजन से संबंधित सभी लाजिस्टिक और प्रबंधकीय पहलुओं की समीक्षा की। इस दौरे से यह स्पष्ट होता है कि सीए इस योजना को अमल में लाने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी आवश्यक तैयारियों को सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है।लाकि, इस मेगा इवेंट को अंतिम रूप देने से पहले अभी कुछ सरकारी औपचारिकताओं और मंजूरियों का इंतजार है। रिपोर्टों के अनुसार, सीए इस संबंध में आस्ट्रेलियाई सरकार के साथ लगातार संपर्क में है और एक बार सभी सरकारी स्तर की चर्चाएं पूरी हो जाने के बाद ही मैच को आधिकारिक मंजूरी मिल सकती है।

डब्ल्यूडब्लयई रेसलर भी बना बुमराह का प्रशंसक

मुम्बई

भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के प्रशंसक केवल भारत में नहीं अन्य देशों में भी हैं। बुमराह के प्रशंसकों में स्काटलैंड के डब्ल्यूडब्लयई रेसलर डू मैकइंटायर भी शामिल हैं। मैकइंटायर ने सोशल मीडिया पर बुमराह की जमकर प्रशंसा करते हुए उनके प्रति सम्मान व्यक्त किया हैं। इस दिग्गज रेसलर ने अपने सोशल मीडिया पर पर एक वीडियो साझा किया है, जिसमें वह जिम में अपने बाइसेप्स की एक्सरसाइज करते हुए दिख रहे हैं। इस वीडियो में सबसे खास बात ये रही कि इसमें मैकइंटायर ने भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी पहनी हुई थी। वीडियो के अंत में, जब वह पीछे मुड़ते हैं, तो उनकी जर्सी पर जसप्रीत बुमराह का नाम और उनका प्रतिष्ठित 93 नंबर स्पष्ट रूप से नजर आता है। इस वीडियो के साथ उन्होंने लिखा, बाइसेप्स बना रहा हूं, गो बूम, जो उनके बुमराह के प्रति प्रेम और उनकी शैली को दर्शाता है। यह एक अनोखा फैन मोमेंट था जिसने क्रिकेट और रेसलिंग दोनों के प्रशंसकों का ध्यान खींचा। एक सफल और नामी रेसलर का इस प्रकार बुमराह के प्रति यह सम्मान निश्चित रूप से भारतीय गेंदबाज की वैश्विक अपील और खेल के प्रति उनकी निरंतर लग्न का एक और प्रमाण है।

मैकइंटायर स्काटलैंड के नामी पेशेवर रेसलर हैं, जिन्हें डब्ल्यूडब्लयई की दुनिया में द स्काटिश वारियर के नाम से जाना जाता है। 6 फीट 5 इंच के कद और फौलादी शरीर वाले मैकइंटायर अपनी ताकत और रिंग में आक्रामक शैली के लिए पहचाने जाते हैं। वह डब्ल्यूडब्लयई के मेन रोस्टर के सबसे प्रमुख चेहरों में से एक हैं! उन्होंने डब्ल्यूडब्लयई इतिहास में कई बड़े मुकाम हासिल किए हैं। वह डब्ल्यूडब्लयई इतिहास के पहले ब्रिटिश वर्ल्ड चैंपियन बनकर उभरे थे, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। अपने करियर में उन्होंने तीन बार डब्ल्यूडब्लयई चैंपियन और एक बार वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन का खिताब जीता है। मैकइंटायर उन्होंने साल 2020 का रायल रंबल मैच जीतकर रेसलमेनिया में अपनी जगह बनाई थी, और हाल ही में 2024 का मनी इन द बैंक लैडर मैच भी अपने नाम किया। वह रेसलमेनिया, समरस्लैम और रायल रंबल जैसे डब्ल्यूडब्लयई के सबसे बड़े इवेंट्स के मुख्य आकर्षणों में से एक रहे हैं।

अमेच्योर और सरताज एकेडमी में विशेष बैडमिंटन प्रशिक्षण शिविर शुरू

इंदौर। शहर के उभरते बैडमिंटन खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने और उन्हें भविष्य का चैंपियन बनाने के उद्देश्य से अमेच्योर बैडमिंटन एकेडमी और सरताज अकादमी के संयुक्त तत्वावधान में विशेष बैडमिंटन प्रशिक्षण शिविरों का आगाज हो गया है। खंडवा रोड स्थित अमेच्योर बैडमिंटन एकेडमी पर शुरू हुए इस विशेष शिविर में चुनिंदा और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को राष्ट्रीय बैडमिंटन रैफरी व प्रशिक्षक धर्मेश यशलहा द्वारा कड़ा अभ्यास कराया जा रहा है। शिविर का मुख्य उद्देश्य बच्चों को न केवल एक बेहतर खिलाड़ी बनाना है, बल्कि उनमें एक जिम्मेदार नागरिक के गुण भी विकसित करना है। इसके साथ ही, अमेच्योर बैडमिंटन एकेडमी में नियमित ग्रीष्मकालीन जूनियर बैडमिंटन प्रशिक्षण शिविर भी शाम के सत्र में सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है। इस शिविर में मुख्य प्रशिक्षक हर्ष सरग बच्चों को बैडमिंटन की बारीकियां सिखा रहे हैं।

आर्सेनल ने जीता प्रीमियर लीग 2025-26 का खिताब, मैनचेस्टर सिटी की ड्रा के बाद हुई पुष्टि

नई दिल्ली

आर्सेनल ने प्रीमियर लीग 2025-26 का खिताब अपने नाम कर लिया है। बुधवार को मैनचेस्टर सिटी और बोर्नमाउथ के बीच मुकाबला 1-1 की बराबरी पर समाप्त होने के बाद आर्सेनल की ट्राफी जीत पक्की हो गई।

इस ड्रा के बाद पेप गार्डियोला की टीम मैनचेस्टर सिटी के 78 अंक हो गए हैं, जबकि आर्सेनल के 82 अंक हैं। लीग में अब सिर्फ एक मुकाबला बचा है, ऐसे में सिटी अब आर्सेनल को पीछे नहीं छोड़ सकती।

आर्सेनल ने पिछली बार 2003-04 सीजन में प्रीमियर लीग का खिताब जीता था। उस ऐतिहासिक इनविंसिबल सीजन में टीम ने आर्सेन वेंगर की कोचिंग में पूरे सीजन में एक भी मैच नहीं गंवाया था।

इस सीजन आर्सेनल के लिए विक्टर ग्योकेरेस ने सबसे ज्यादा 14 गोल किए। वहीं मार्टिन ओडेगार्ड और लिएंड्रो ट्रोसार्ड ने छह-छह असिस्ट देकर टीम की सफलता में अहम योगदान दिया। गोलकीपर डेविड राया ने 19 क्लीन शीट के साथ लगातार तीसरी बार गोल्डन ग्लव अवार्ड अपने नाम किया।

यह आर्सेनल के मुख्य कोच मिकेल आर्टेटा का भी पहला लीग खिताब है। आर्टेटा ने 2019 में क्लब की कमान संभाली थी। इससे पहले वह साढ़े तीन वर्षों तक पेप गार्डियोला के सहायक कोच रहे थे।

प्रीमियर लीग खिताब जीतने के बाद अब आर्सेनल की नजर यूईएफए चैंपियंस लीग 2025-26 के फाइनल पर होगी, जहां उसका सामना मौजूदा चैंपियन पेरिस सेंट-जर्मेन से होगा।

ट्रेवर बेली के नाम है सबसे धीमे अर्धशतक का रिकार्ड

लंदन

टी20 क्रिकेट लीग के इस दौर में जहां बल्लेबाज विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए कुछ ही गेंदों में अर्धशतक और शतक लगा रहे हैं। वहीं टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में इंग्लैंड के दिग्गज आलराउंडर ट्रेवर बेली के नाम धीमी बल्लेबाजी का एक ऐसा रिकार्ड भी दर्ज है जो अब टूटना असंभव है। इस बल्लेबाज ने दशकों पहले एक ऐसी पारी खेली थी जिसने बल्लेबाजी की परिभाषा ही बदल दी। उन्होंने 50 रन बनाने के लिए 350 गेंदें खेलीं। इस प्रकार बेली के नाम सबसे धीमें अर्धशतक का रिकार्ड दर्ज हो गया है। ये वाकया साल 1958 का है तब इंग्लैंड की टीम ब्रिस्बेन के गाबा मैदान पर आस्ट्रेलिया से खेल रही थी। दूसरी पारी में इंग्लैंड टीम मुश्किल में थी। ऐसे कठिन समय में, तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे ट्रेवर बेली ने रन बनाने के जगह क्रीज पर टिके रहना तया किया। बेली ने आस्ट्रेलियाई आक्रमण का सामना करने को ही अपना एकमात्र लक्ष्य बना लिया। बेली ने आस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को बुरी तरह थकाते हुए, धैर्य और दृढ़ता की मिसाल पेश की।

उन्होंने महज 50 रन के आंकड़े तक पहुँचने के लिए रिकार्ड 350 गेंदें खेलीं। ये टेस्ट क्रिकेट के इतिहास का आज तक का सबसे धीमा अर्धशतक है। अपनी इस अविश्वसनीय पारी में बेली ने कुल 427 गेंदों का सामना किया और 68 रन बनाए। भले ही इंग्लैंड यह मैच 8 विकेट से हार गया, लेकिन बेली ने अपनी इस धैर्यपूर्ण और अविस्मरणीय पारी से सभी का दिल जीत लिया। एक आधुनिक क्रिकेट के तेज़-तर्रार स्वरूप को देखते हुए, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बेली द्वारा बनाया गया यह रिकार्ड अब कभी नहीं टूटेगा। आज के दौर में बल्लेबाज हर फार्मेट में तेजी से रन बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, और 15-20 गेंदों में अर्धशतक पूरा करना अब आम बात हो गई है। रन रेट और स्ट्राइक रेट का महत्व इतना बढ़ गया है कि कोई भी बल्लेबाज 350 गेंदों में 50 रन बनाने का जोखिम नहीं उठाएगा।

फीफा विश्व कप 2026 के लिए पुर्तगाल टीम का ऐलान, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और ब्रूनो फर्नांडिस शामिल

नई दिल्ली। पुर्तगाल ने मंगलवार को आगामी फीफा विश्व कप 2026 के लिए अपनी टीम की घोषणा कर दी। अनुभवी स्टार फुटबालर क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक बार फिर टीम की अगुवाई करेंगे। उनके साथ ब्रूनो फर्नांडिस, बर्नार्डो सिल्वा और वितिन्हा जैसे कई स्टार खिलाड़ी भी टीम में शामिल हैं। 41 वर्षीय रोनाल्डो अपने करियर का रिकार्ड छठा फीफा विश्व कप खेलने उतरेंगे। इस उपलब्धि के साथ वह अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी और मेक्सिको के गोलकीपर गिलर्मो ओचोआ की सूची में शामिल हो जाएंगे। यूरो 2016 चैंपियन पुर्तगाल को विश्व कप में ग्रुप-के में रखा गया है, जहां उसका सामना डीआर कांगो, कोलंबिया और उज्बेकिस्तान से होगा। विश्व कप अभियान शुरू होने से पहले पुर्तगाल की टीम चिली और नाइजीरिया के खिलाफ अभ्यास मैच खेलेगी। इसके बाद टीम 17 जून को डीआर कांगो के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी। वहीं 23 जून को उज्बेकिस्तान और 27 जून को कोलंबिया से मुकाबला होगा।

बच्चों को सुलाने के आसान तरीके

आमतौर पर बच्चों को जब नींद नहीं आती है तो वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। फिर उन्हें किसी भी तरह बहलाने फुसलाने की कोशिशें बेकार साबित होती हैं। उस समय उन्हें जरूरत होती हैं प्यारी सी लोरी के साथ शांत माहौल और मां के गोद की। लोरी सुनाकर बच्चों को सुलाने का चलन बरसों से चला आ रहा है। आज भी मां अपने बच्चों को लोरी सुनाकर ही सुलाती हैं। धीरे-धीरे और मीठे स्वर में गाई गई लोरी का बच्चे के दिमाग पर काफी असर होता है इसको सुनते-सुनते वे धीरे-धीरे मीठी नींद की ओर बढ़ने लगते हैं।

लोरी ही जरूरी नहीं: लोरी बच्चे को सुलाने का सबसे प्यारा तरीका समझा जाता है। लेकिन सिर्फ लोरी ही जरूरी नहीं है इसके साथ बच्चे के शरीर पर हल्की-हल्की थपकी और गोद में उसे धीरे-धीरे झुलाना भी काफी मददगार साबित होते हैं। और यह प्रक्रिया आपको तब तक करनी चाहिए जब तक बच्चा गहरी नींद में ना सो जाए।

लोरी सुनते ही क्यों सो जाते हैं बच्चे: लोरी की मीठी आवाज से बच्चे का ध्यान आस-पास की आवाजों से हटने लगता है। बच्चों को लगातार गोद में झुलाते रहने से उसकी नजर किसी भी चीज पर नहीं टिक पाती। और थोड़ी ही देर में उसकी आखों में नींद आने लगती है। और वह धीरे-धीरे अपनी आंखों को बंद करने लगता है।

स्तनपान करते हुए: आमतौर पर देखा जाता है कि बच्चें मां की गोद में स्तनपान करते हुए भी सो जाते हैं। ऐसे में उनके सिर पर धीरे-धीरे हाथ से सहलाएं जिससे उनकी आंखों में नींद आने लगे। और जब वह पूरी नींद में सो जाए तो उसे धीरे से बिस्तर पर लेटा दें।

गोद में लेकर झुलाएं: बच्चो को जब नींद आती है तो वो आपकी गोद में झुलना चाहते हैं। ऐसे में बच्चे को अपनी गोद में लेकर दाएं से बाएं झुलाएं। धीरे-धीरे उसकी आंखे भारी होने लगती है और वह थकवाट के कारण अपनी आंखे बंद करने पर मजबूर हो जाता है। ध्यान रहे कि ज्यादा से जोर से झुलाने पर बच्चा डर भी सकता है।

मौजूद है टिंबकटू शहर...

आपने अक्सर किस्से कहानियों में टिंबकटू जैसी चीजों का नाम सुना होगा। आज हम आपको एक ऐसे शहर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नाम टिंबकटू है। यह शहर अफ्रीका के माली देश में बसा हुआ है। यह शहर किसी समय एजुकेशन के लिहाज से यह बहुत आगे हुआ करता था। इसे 333 संतो का नगर भी कहा जाता था।अफ्रीका इस्लाम की पढ़ाई के लिए यह शहर एक केन्द्र हुआ करता था। आज भी इसका विश्वविद्यालय इस्लामिक पढ़ाई के लिए लोगों को अपनी ओर एटरेक्ट करता है। टिंबकटू माली के समृद्ध सांस्कृतिक और अध्यात्मिक विरासत वाला शहर है। इस शहर की अमूल्य विरासत के कारण संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक इकाई यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत की सूची में दर्ज रखा है। यह शहर 5वीं सदी में बना था और लगभग 15वीं सदी तक व्यापारिक नगर से जाना जाने लगा था। यहां पर ऊंटो के सहारे सोने का बिजनेस चलता था। मुस्लिम व्यापारी इसी शहर से पश्चिमी अफ्रीका और यूरोप से सोने की मार्केटिंग करते थे। बदले में उन्हें अपनी जरूरतों की चीजें मिलती थी। कहा जाता है कि उस समय सोने की कीमत नमक के बराबर थी। लगभग 17वी सदी के आसपास अंटलानटिक महासागर के व्यापारिक नगर बनने के साथ ही यह अमीर विरासत वाला शहर पतन की ओर चल पड़ा।इस शहर में आवाजाही के साधन आसानी से नही मिलते लेकिन फिर भी यह आकर्षण का केन्द्र है। यहां 350 साल पुरानी जिंगरेबर मस्जिद आज भी यहां मौजूद है। लेकिन यह शहर आतंकी हमले की वजह से तबाही की कगार पर पहुंच गया। आतंक के साए से जूझ रहे टिंबकटू निवासी आज भी इसे बचाने की हर कोशिश कर रहे है।

स्किन की रंगत पर भारी आदतें...

जहां स्किन का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है वहीं कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी आदतें ही स्किन को बेजान कर रही हों। स्किन रूखी होने पर अपनी सुंदरता खो देती है, सनलाइट के अलावा और भी ऐसी चीजें है जो आपकी स्किन को नुकसान पहुंचा सकती हैं। कुछ आदतों में बदलाव करकेअपनी स्किन को बेजान होने से बचा सकते हैं। घंटों एसी में बैठे रहने से भी त्वचा की नमी कम हो जाती है। इस कारण त्वचा रूखी होने लगती है। लगातार गर्मी से ठंडक और ठंडक से गर्मी में आने से भी त्वचा खराब होती है।अगर इस्तेमाल करते भी हैं तो तापमान बहुत कम न रखें। गर्मियों में गाड़ी के शीशे खोल कर या बाइक पर रफ्तार में, तेज हवा में ड्राइव पर जाने से मूड फ्रेश हो जाएगा तो हां, ऐसा हो सकता है लेकिन इससे आपकी त्वचा का क्या हाल होगा आप सोच भी नहीं सकते। यह तेज हवा त्वचा के सेल्स को बर्बाद कर सकती है।

सोच से जुदा है ईरान की जिंदगी...

वास्तव में ईरान हमारी और आपकी कल्पना से एकदम अलग देश है। जैसा दिखाया जाता है वैसा नहीं है ईरान। वहां भी आजादी है, हंसी है, खुशी है और जिंदगी जीने वाले जिंदादिल लोग हैं। ईरान में रह रहे लोगों की लाइफस्टाइल उस धारणा से बिल्कुल दूर है, जो यहां के कट्टरपंथियों ने दुनिया को दिखाने की कोशिश की है। बाकी देशों की तरह जुर्म और हिंसा यहां रोजाना की जिंदगी का सच है, लेकिन कुल मिलाकर ईरान एक ऐसा देश है, जो कट्टर परंपरा और आधुनिक संवेदनशीलता के बीच का रास्ता निकालने की कोशिश में लगा है।

अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान को छोड़कर एक नया मार्ग खोलने के प्रयासों के तहत प्रधानमंत्री ईरान यात्रा के दौरान चाबहार बंदरगाह के पहले चरण के विकास के लिए उसके साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगे। मोदी की शिया मुसलमानों के देश ईरान की यह पहली यात्रा है। ईरान का नाम जेहन में आते ही एक ऐसे इस्लामिक देश की छवि उभरती है, जहां नियम-कायदे बहुत सख्त हैं। हालांकि, इस छवि के पीछे काफी हद तक ईरान और अमेरिका के कट्टरपंथी हैं।

इन्होंने ईरान की ऐसी छवि दिखाने की कोशिश की, जो पश्चिमी सभ्यता और आधुनिकता का विरोध करती है। इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान में काफी बदलाव आया है, लेकिन फिर भी इस देश की असल तस्वीर इस राजनीतिक दिखावे से काफी अलग है। ईरान में रह रहे लोगों की लाइफस्टाइल उस धारणा से बिल्कुल दूर है, जो यहां के कट्टरपंथियों ने दुनिया को दिखाने की कोशिश की है। बाकी देशों की तरह जुर्म और हिंसा यहां रोजाना की जिंदगी का सच है, लेकिन कुल मिलाकर ईरान एक ऐसा देश है, जो कट्टर परंपरा और आधुनिक संवेदनशीलता के बीच का रास्ता निकालने की कोशिश में लगा है। इस कोशिश का सबसे ज्यादा असर ईरान की सांस्कृतिक और औद्योगिक राजधानी तेहरान में देखने को मिलता है। यहां के लोगों की जिंदगी अन्य देशों के लोगों की ही तरह एकदम सामान्य है, बात चाहे पहनावे की हो या फिर अपने शौक पूरे करने की। महिलाएं और लड़कियां बराबरी में यहां बाहर काम करती दिखाई दे जाएंगी। महिलाओं को जिम से लेकर हुक्का बार और पार्टीज में आसानी से देखा जा सकता है। जाहिर है किसी भी देश के बारे में कोई भी राय वहां की सरकार और वहां के राजनीतिक परिदृश्य को देखकर नहीं बनानी चाहिए।

युवाओं में हुक्का

हुक्का वैसे तो बहुत समय से ईरान और अन्य एशियाई देशों में इस्तेमाल किया जाता है। आजकल ईरान में हुक्का यहां के युवा वर्ग की पहली पसंद बन गया है। तेहरान सहित कई अन्य शहरों में आप हुक्का बार में यहां के युवाओं को हुक्के का लुत्फ उठाते देख सकते हैं। ईरान की खूबसूरती किसी के भी दिल को जीत सकती है। इराक, तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से घिरा हुआ ये देश इरान आए-दिन सुर्खियों में बना रहता है। पर अगर आप इस बड़े से देश की सुंदरता पर गौर करें, तो ये आपका दिल जीतने के लिए काफी है। टूरिज्म की नजर से इरान किसी के लिए भी एक मस्ट-विजिट नेशन के तौर पर देखा जा सकता है। यहां की प्राचीन इमारतें, मॉडर्न लाइफस्टाइल के बीच भी पुराना-सा अहसास और यहां की संस्कृति, सभी कुछ सुंदर है। इरान युनेस्को के 19 रेजिस्टर्ड साइटों में से एक है। इस देश में 1300 प्रोजेक्ट्स का इंवेस्टमेंट पैकेज हो रखा है। स्कीइंग के लिए इरान का नाम आपके जेहन में नहीं आता होगा।

मधुर संबंधों का इतिहास

ईरान के साथ भारत के संबंध सदैव मधुर रहे हैं। ईरान और भारत का अपना साझा इतिहास भी रहा है। भारत और ईरान दोनों की प्राचीन सभ्यताएं हैं। संयुक्त भारत के विभाजन से पूर्व दोनों पड़ोसी मुल्क थे। ईरान में कई भारतीय परिवार रहते थे जो 1920 से ईरान में बस रहे थे उनमें सबसे बड़ी संख्या सिख और गुजरातियों की थी। वे 1950 से ईरान की राजधानी में आकर बसने लगे। ईरान प्राचीन सिल्क रूट का मार्ग भी है जो योरोप तक जाता है। गुरु नानक देव इसी मार्ग से मक्का गए थे। सिख इस स्थान का बहुत सम्मान करते हैं कहते हैं जब संयुक्त भारत का बंटवारा हुआ सन 1947 में जाहदान के आसपास रहने वाले पंजाब के बाशिंदे यह नहीं जानते थे हिन्दोस्तान किधर है ईरान की सीमा उनके क्षेत्र से जुडी थी इसलिए वे वहीं बस गए और वहीं के हो गए। कहते हैं ईरान और पाकिस्तान की सीमावर्ती शहर जाहदान का नाम एक सिख के नाम पर रखा गया था पहले इस शहर का नाम दूजद आब था। जाहदान एक सूखा क्षेत्र है। एक बार ईरान के शाह दुजद आब प्रदेश गए वहां उन्हें एक नेक दिल सिख को सबके साथ रहते देख कर हैरानी हुई उन्होंने इस प्रदेश का नाम उस सिख के नाम पर रख दिया जिन्हें वहां के बाशिंदे जहेदस पायस कह कर पुकारते थे। अतः प्रदेश का नाम ही जाहदान हो गया।

उतनी बंदिशें नहीं

ईरान के राजनेताओं और मौलाना मौलवियों को टीवी या इंटरनेट पर बोलते देख लगता है कि ईरान में भी और इस्लामिक देशों की तरह हर चीज बैन होगी लेकिन ऐसा नहीं है। यहां हर वो चीज है जो किसी और देश में होती है। शराब, नाईट क्लब, हसीनाएं और आजादी। ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद हालात काफी बदले हैं लेकिन फिर भी ईरान में उतनी बंदिशें नहीं हैं। ईरान की राजधानी तेहरान किसी पश्चिमी देश से कम नहीं है। नाईट क्लब, शराब, जगमगाती लाइट्स सब कुछ है तेहरान में। कभी तेहरान में जाकर देखिये वहां के निगह क्लब,वहां का संगीत और वहां की हसीनाएं देखकर आप पेरिस और लास वेगास को भी भूल जाएंगे। फैशन की दुनिया में भी ईरानी मॉडल्स का काफी नाम है। यह मत सोचिये कि ये मॉडल्स हिजाब पहन कर रैंप पर आती हैं। रैंप पर इनके जलवे ही कुछ और होते हैं।

महिलाओं की लड़ाई

ईरान की महिलाएं न सिर्फ खूबसूरती में सबसे आगे हैं अपितु अपने अधिकारों के लिए लड़ने में भी आगे हैं। क्रांति के बाद महिला राजनीतिज्ञों की संख्या में कमी तो आई है पर आज भी इनका राजनीति में पूरा दखल है। ईरान में महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी है और विरोध प्रदर्शन का भी। समय समय पर सरकार के ऊल जुलूल फैसलों पर यहां की महिलाएं अपने अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन करती हैं। मिसीह एलीनेजाद ईरानी महिला पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता है। महिलाओं के अधिकार को ले कर ईरान में इन्होंने एक अलग ही तरह का विद्रोह छेड़ रखा है। 1979 से ईरान में महिलाओं के लिए पब्लिक में हिजाब पहनना अनिवार्य है। इसको न पहनने पर यहां कानूनी कार्रवाई की जाती है। 2009 में ईरान की लगभग 30 लाख महिलाओं पर या तो मुकदमे चलाए गए या जुर्माना लगा। इसे ले कर एक तरह से लोगों में विद्रोह की आग धीरे-धीरे सुलग रही है। लेकिन रूढ़िवादी लोगों की सोच भी इसमें आड़े आ रही है। ईरान में बिना हिजाब के महिलाओं का घूमना एक तरह से अपवाद ही है, लेकिन मिसीह एलीनेजाद जैसी कुछ बहादुर महिलाओं ने इस अपवाद को नकार के रख दिया।

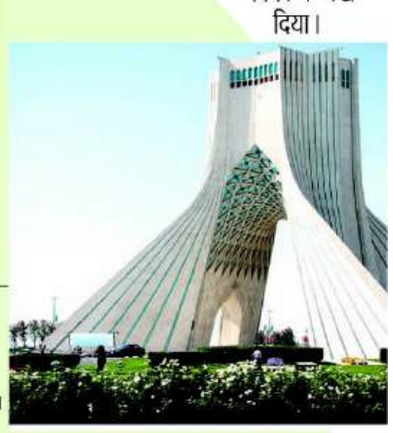

हिजाब की पाबंदी

ईरान के शाह मोहम्मद रजा पहलवी, पहलवी डायनेस्टी के आखिरी शाह थे उन्होंने आर्य मिहिर की उपाधि धारण की थी। वे प्रगति शील थे और धार्मिक सम भाव में विश्वास करते थे लेकिन शाह के खिलाफ क्रांति का माहौल बना। काफी खून खराबे के बाद इस्लामिक सरकार सत्ता में आई। अब ईरान में डाक्टरों की जरूरत थी ईराक के साथ युद्ध भी हो रहा था। अतः मुख्यतया भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश से डाक्टर ईरान में काम करने आए। यह नए सिरे से बदलाव का समय था। अचानक वहां सब कुछ बदल गया। सबसे अधिक महिलाओं के अधिकारों का हनन हुआ। वहां की महिलाएं प्रगतिशील थीं उन पर किसी भी तरह की पाबंदी नहीं थी। वे योरोपियन लिबास पहनती थी अब उनको चादर में अपने आप को लपेटना पड़ा। हिजाब की पाबंदी को विदेशियों पर भी लागू किया गया। ईरानी स्वभाव से मेहमान नवाज हैं। उन्होंने कभी सोचा नहीं था उन्हें ऐसी आजादी मिलेगी सब कुछ बदल जाएगा।

तेहरान में गुरुद्वारा

तेहरान में सिखों का गुरुद्वारा है। यहीं एम्बेसी का स्कूल है। यहां भारतीय बच्चे पढ़ते हैं। ईरान में सात वर्ष का बच्चा स्कूल जाता है। भारतीयों के बच्चों के लिए एम्बेसी के स्कूल के साथ गुरूद्वारे में भी क्लासेस लगती हैं। स्कूल में सीबीएसई का कोर्स पढ़ाया जाता है और परीक्षा रे पेपर भारत से जाते हैं। सिख समुदाय के लोग वहां अपने देश की तरह रहते हैं। इस समय प्रवासियों की चौथी और पांचवी पीढ़ी रहती है लेकिन अभी तक वे भारतीय नागरिक हैं। इससे ईरानियों को मिलने वाले अधिकारों से वे वंचित हैं। वे ईरान की नागरिकता चाहते हैं। वहां प्रवासियों को सम्पत्ति खरीदने का अधिकार नहीं है। व्यापार में भी निवेश करने के लिए ईरानी पार्टनर चाहिए। भारतीय कंपनियां ईरान में कोल, गैस, रेल की पटरियां बिछाने, शिपिंग और खेती बाड़ी के काम में निवेश की इच्छुक है जिसके अवसर भी कम नहीं हैं। तेल की कीमतें घटने के बाद ईरान अन्य क्षेत्रों में विकास के अवसर खोज रहा है।

बालों को लहराने के लिए

फिलहाल मिसीह एलीनेजाद अमेरिका में रहती हैं अपने आस-पास महिलाओं को बिना हिजाब के, बिना किसी शिकंजे के और एक आजाद सोच के साथ जीते देखना उन्हें रोमांचित करता है। मिसीह एलीनेजाद ने अपनी बिना हिजाब वाली तस्वीरें फेसबुक पर पोस्ट करनी शुरू की। लोग देखते, कमेंट करते। कुछ अच्छे कमेंट करते, तो कुछ अपनी गंदी सोच को भी लिख कर जाहिर करते, लेकिन उन्होंने जवाब देना बंद नहीं किया। एक महिला का ईरान में बाल खुले रखना कानूनी जुर्म है। आज भी कई महिलाएं अपनी आजादी के लिए एक दूसरे का हाथ थामे खड़ी हैं। हिजाब से लोगों को नफरत नहीं लेकिन उसकी अनिवार्यता एक तरह से बंधन बन जाती है। मिसीह एलीनेजाद ने उन लोगों के साथ काफी तस्वीरें खिंचवाई हैं, जो महिलाओं के लिए आजादी के इस आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं। इस फेसबुक ग्रुप को कई महिलाओं ने अपना औपचारिक समर्थन भी दिया है। खुली हवा में अपने बालों को लहराते देखना उन्हें काफी अच्छा लगता है।

फिल्म देखने का जुदा अंदाज...

दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं हमें थिएटर यानी की सिनेमा हॉल तो देखने को मिल ही जाएंगे। सिनेमा हॉल में लोग मूवीज देखने जाते हैं लेकिन जिन थिएटर की बात हम कर रहे हैं वहां मूवीज के साथ-साथ लोगों के कंफर्ट का भी खास ध्यान रखा गया है। इन थिएटर के अंदर लोग बोट पर, कार पर, बाथ टब या आरामदायक सोफे पर बैठकर फिल्में देखते हैं।

ग्रीस का ओलिंपिया थिएटर

ग्रीस के ओलिंपिया थिएटर की खास बात यह है कि यहां पर लोग बैठ कर नहीं बल्कि लेटकर फिल्म का लुत्फ उठा सकते हैं। इसकी सीट को आरामदायक बिस्तर का आकार दिया गया है। इस पर लेट कर लोग मूवी का लुत्फ उठा सकते हैं। ओलिंपिया थिएटर का डिजाइन आर्किटेक्ट स्टैवरोस क्रिस्टिडिस ने किया था।

साई-फाई डाइन-इन थिएटर

अमेरिका के ओरलैंडो के साई-फाई डाइन-इन थिएटर में जो कुर्सीयां लगी हैं,वे कार के आकार की हैं। इसमें बैठकर आप न सिर्फ मूवी देख सकते हैं, बल्कि सीट पर ही लंच या डिनर भी ऑर्डर कर सकते हैं।

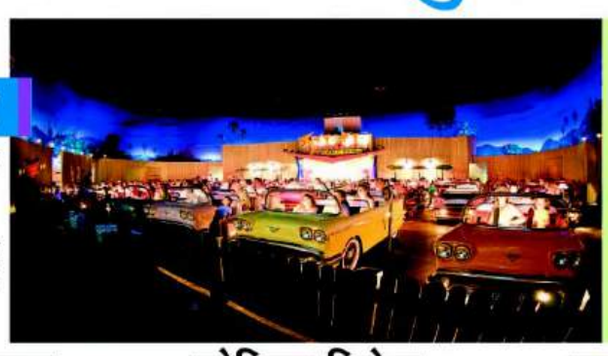

आइनॉक्स थिएटर

वडोदरा का आइनॉक्स थिएटर दर्शकों को आलीशान बिस्तर पर लेटकर फिल्में देखने का मौका मिलता है। इसकी प्रत्येक बिस्तरनुमा सीट पर दो लोग लेटकर फिल्में देख सकते हैं। यह थिएटर गुजरात के वड़ोदरा स्थित रिलायंस मॉल में हैं।

पेरिस का मूवी थिएटर

यह मूवी थिएटर सबसे अलग है। इसमें सिटिंग अरेंजमेंट सबसे अनोखा है क्योंकि इसमें नाव के आकार की सीटें है। मूवी देखने से पहले सभी को चश्मा पहनना होता है।

इलेक्ट्रिक सिनेमा

लंदन के नॉटिंग हिल का इलेक्ट्रिक सिनेमा हॉल अपनी खूबसूरती के कारण दुनिया भर में मशहूर है। इसमें महरून रंग के सोफे लगे हुए है। इनके सामने बहुत ही एटरेक्टीव लैंप लगे हुए हैं।

न्यूपोर्ट अल्ट्रा सिनेमा

न्यूपोर्ट सिटी का न्यूपोर्ट अल्ट्रा सिनेमा 3डी टेक्नोलॉजी पर पूरी तरह आधारित है। इसमें प्राइवेसी का भी पूरा ख्याल रखा जाता है। इस सिनेमा हाल में ज्यादातर कपल्स जाते हैं।

हॉट ट्यूब सिनेमा

लंदन का हॉट ट्यूब सिनेमा घर अपने अनोखें अंदाज के कारण दुनियाभर में मशहूर है। इसमें आरामदायक टब लगे हुए हैं, जो पानी से भरे हुए हैं। यहां आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ मूवी देख सकते हैं। यहां मूवी देखते वक्त ड्रिंक्स पर भी कोई पाबंदी नहीं है।

मुद्रक एवं प्रकाशक राकेश शर्मा द्वारा अजय त्यागी के लिए ईको प्रिंटिंग प्रेस, पोस्ट एवं पीएस : गड़चुक, कटाबाड़ी मस्जिद के पास, कामरूप (मेट्रो), गुवाहाटी-35 से मुद्रित एवं **गुड लक पब्लिकेशंस, हाउस नं. 30, डी. नेउग पथ, डोना प्लैनेट के नजदीक, एबीसी, जीएस रोड गुवाहाटी-5 से प्रकाशित।**
संपादक : राकेश शर्मा, मोबाइल : 94350-14771, 97070-14771 ● **कार्यकारी संपादक : प्रदीप शील ● सहयोगी संपादक : रवि शंकर चौधरी ● फोन : 0361-2960054 (संपादकीय)** e-mail : viksitbharatsamacharghy@gmail.com, **(सभी विवाद सिर्फ गुवाहाटी न्याय क्षेत्र के अधीन)**